



LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Thursday, February 06, 2020 / Magha 17, 1941 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 06, 2020 / Magha 17, 1941 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 61-66)	1-30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 67-80)	31-50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 691-920)	51-280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, February 06, 2020/ Magha 17, 1941 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 06, 2020/ Magha 17, 1941 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281-85
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE Minutes	286
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 25 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT - LAID Shri Hardeep Singh Puri	286
SPECIAL MENTIONS	287-99
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	300-311
Shri Sangam Lal Gupta	300
Dr. Subhas Sarkar	301
Shri Nisith Pramanik	302-03
Shri K. Sudhakaran	304
Shri Deepak Baij	305
Shri A. Ganeshamurthi	306
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	307
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	308
Shri Shrirang Appa Barne	309
Shri Anubhav Mohanty	310

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS	310A-332
(Contd.-conclusive)	
*Shri Sunil Kumar Singh	311A1-A4
*Shri Anubhav Mohanty	311B1-B5
*Shri Tirath Singh Rawat	311C1-C3
*Dr. Heena Vijaykumar Gavit	311D1-D3
*Shri D.S. Rathod	311E1
*Shri Vinod Lakhamashi Chavda	311F1
*Shri Sudarshan Bhagat	311G1-G2
*Shri Dushyant Singh	311H1-H15
*Shri Vasava Parbhubhai Nagarbhai	311J1-J2
*Shri Devji M. Patel	311K1-K2
*Shri Chandra Prakash Joshi	311L1-L5
*Shri Patel Mitesh Rameshbhai	311M1-M5
*Smt. Poonamben Hematbhai Maadam	311N1-N6
*Shri VE. Vaithilingam	311-O1
*Dr. Kalanidhi Veeraswamy	311P1-P2
*Shri Vinod Kumar Sonker	311Q1-Q3
Shri Narendra Modi	312-331
Amendments-Negatived	332
Motion adopted	332

***Laid on the Table**

GENERAL BUDGET- GENERAL DISCUSSION	333-382
-Inconclusive	
Shri Manish Tewari	333-38
Shri Jayant Sinha	339-51
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	352-58
Shri Abhishek Banerjee	359-71
Shri Kanumuru Raghurama Krishna Raju	372-75
Shri Arvind Sawant	376-82

XXXXX

(1100/PC/RC)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या – 61, श्री राहुल कस्वां।

(प्रश्न 61)

श्री राहुल कस्वां (चुरु): सर, मुझे मंत्री महोदय से यह पूछना है कि 'साई' के जो एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम डे-बोर्डिंग सेंटर्स भी बोलते हैं, बीते चार सालों में मेरे लोक सभा क्षेत्र में हॉकी, एथलेटिक्स, टेबिल-टेनिस और हैण्डबॉल के ऐसे चार डे-बोर्डिंग सेंटर्स चुरु जिले में खुले हैं। इन सेंटर्स में 20 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए उनको प्रति महीने 600 रुपये दिए जाते हैं। 1 लाख रुपये इन सेंटर्स को चलाने के लिए दिए जाते हैं।

सर, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह 1 लाख रुपये की जो राशि है, यह अत्यंत ही कम है। 600 रुपये में हम बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन देंगे? क्या सरकार का ऐसा कोई प्रावधान है, जिससे इस राशि को बढ़ाया जाए? काफी सालों से यह राशि 1 लाख रुपये ही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ।

श्री किरेन रिजीजू: सर, राहुल कस्वां जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। राजस्थान में हमने खेल के क्षेत्र में अलग-अलग व्यवस्था की है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने पैसे के बारे में जो कहा है, वे पर्याप्त नहीं हैं। सही में खिलाड़ी को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। अभी तक 1 लाख रुपये जो उनको दिया जाता है, वह इसके लिए पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि भारत सरकार की ओर से हम हर संभव मदद जरूर करेंगे।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 280 सेंटर्स को भारत सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चलाती है या मदद करती है। उन्हें पूरा का पूरा चलाना संभव नहीं होता है। इसलिए, आने वाले अप्रैल महीने से 'खेलो इंडिया' के तहत हम अभी तक अलग-अलग सेंटर्स में, अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते आए हैं, उसमें मेजर चेंजेज करने का हमारे मंत्रालय का प्लान है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जो नई पॉलिसी लाएंगे, नया नियम लाएंगे, उसके तहत खिलाड़ियों का राज्य सरकारों से तालमेल कर के, अलग-अलग प्राइवेट एकेडेमीज से तालमेल कर के अच्छी तरह इसे कैसे चलाएं, इस दिशा में व्यापक रूप से काम चल रहा है। इससे माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए।

श्री राहुल कस्वां (चुरु): मंत्री महोदय, धन्यवाद।

सर, मेरा यह मानना है कि इन सेंटर्स के लिए जो 1 लाख रुपये की राशि इक्यूपमेंट्स परचेज करने के लिए दी जाती है, वह अत्यंत ही कम है। पूरे देश भर में करीब 600 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। सीएसआर फंडिंग का प्रावधान रख सकते हैं। आपको पता ही है कि आपके द्वारा चुरु लोक सभा क्षेत्र में ओलंपिक लेवल का क्लास-1 सिंथेटिक ट्रैक बना, जो राजस्थान में नंबर-1 पर है। हमने

ट्रैक बनवा दिया, लेकिन सेंटर्स को मजबूती देने के लिए क्यों न सीएसआर फंडिंग का भी इसमें प्रयोग किया जाए?

सर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा 'एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट' की स्कीम चलाई गई थी। इसी तरह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा 'एडॉप्ट ए स्टेडियम' की भी एक स्कीम चलाई जा सकती है। मैं इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जो बच्चे खेल रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको डायरेक्ट 'खेलो इंडिया' के अंदर क्यों नहीं एंट्री मिल सकती? इन बच्चों को स्टेट के सिस्टम से गुजरना पड़ता है, जहां इनको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लोकल पॉलिटिक्स चलती है। इन बच्चों को इसमें डायरेक्ट परफॉर्म करने के लिए हम क्यों नहीं प्रावधान कर सकते हैं?

श्री किरन रिजीजू: स्पीकर सर, सीएसआर का जो मुद्दा है, उसमें नई नीति लाई गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले सदन में इसका जिक्र भी किया था। अब कोई भी कंपनी, चाहे वह पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, खेल के क्षेत्र में अगर कॉन्ट्रिब्यूशन करती है, हमारे 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड' के तहत आती है तो उसके लिए बिलकुल छूट भी दी गई है। वे तमाम प्रकार के कॉन्ट्रिब्यूशन्स कर सकते हैं।

(1105/SPS/SRG)

हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी खेल के प्रावधान को समझते हुए इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में हमारे सामने आए। सर, चुरु में हमने अपने मंत्रालय से फंडिंग की थी और बहुत बार माननीय सदस्य मुझे उद्घाटन करने के लिए कह चुके हैं। मैं राजस्थान जाना चाहता हूं और सदन खत्म होते ही मैं चुरु जाकर उद्घाटन करूंगा।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Since we are on the question relating to Sports Authority of India, there is an extremely disturbing issue and this pertains to sexual harassment by coaches of the Sports Authority of India. Now, publicly available figures suggest that 45 odd cases have been reported over the past ten years, out of which 29 pertain to coaches. There are two former Director-Generals of Sports Authority of India who are on record saying that this is a culture in Sports Authority of India. Now, this is something which is increasingly disturbing because a lot of the children who are trained are actually girl students. So, because of the pressure, they are forced to withdraw those complaints. My specific question to the hon. Minister is that what the Ministry of Sports and Youth Affairs is doing to deal with this repeated reporting of cases of sexual harassment in the Sports Authority of India.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, the matter brought out by Sh. Manish Tewari Ji is very sensitive and very serious. When I took over this Ministry, I had received certain complaints and certain issues relating to the matter raised by the hon. Member. Sexual harassment is a big issue, not only in sporting arena, but for anybody in

any sector. Recently, when the matter came to my notice, I have given directions also. I have said that by the end of this February, all the pending matters relating to charges of sexual offences should be disposed of. We have sensitized our own Ministry and our institutes in this regard. I discussed this with the Minister for Women & Child Development and I am going to discuss this with the National Commission for Women also so that we can together take up some kind of a large scale awareness campaign to ensure that issues are taken up and cases are registered. If it is a case related to a minor, it can be registered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO). In the same manner, the vulnerability of the female athletes is very high. Keeping that in mind, we have taken certain decisions and my direction is very clear that our approach is athlete-centric and the safety and security of the athlete is our primary concern and if such reports come to my notice, then there will be the stringent action. I assure the hon. Member, through you, that we will not tolerate any kind of sexual advances or any kind of atrocities against women athletes in the Ministry or in our Department.

(ends)

(प्रश्न 62)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा प्रश्न 'पढ़ो परदेश स्कीम' के बारे में है। यह आन्ध्र प्रदेश में किस तरह लागू हो रही है, यह मैंने मूल प्रश्न में पहले पूछा है। उत्तर के बाद मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ो परदेश स्कीम अवेल कर रहे हैं, अगर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक देखें तो आंकड़ा कम होता जा रहा है। स्पेशली वर्ष 2015-16 में 133 स्टूडेंट्स ने स्कीम को अवेल किया और वर्ष 2018-19 में 74 तक कम होते गए। आप जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद वहां की क्या परिस्थितियां हैं। वहां पर बहुत सारे माइनोरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं और स्कीम के तहत बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आंकड़ा कम क्यों हुआ है?

(1110/MM/RU)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पढ़ो परदेश स्कीम के बारे में जानकारी चाही है। ये जो सिक्स्थ नोटिफाइड माइनोरिटीज हैं, उनके जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राएं हैं या नौजवान हैं, जो विदेशों में शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनको हम इंटरैस्ट पर सब्सिडी देते हैं। उसके लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है। इसके अलावा 252 बैंक्स हैं जो इसके लिए लोन देते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है तो आंध्र प्रदेश के जितने भी एलिजिबल छात्र हैं और उन्होंने यदि प्रार्थना पत्र दिया है तो उन सभी को इस पर सब्सिडी दी गयी है। इसके अतिरिक्त पिछले पांच सालों में आंध्र प्रदेश के लगभग 533 स्टूडेंट्स बेनिफिशरी रहे हैं। जिन्होंने भी एप्लीकेशनस दी हैं, उनको मिला है। इसमें हमने 4 करोड़ 19 लाख रुपये का फण्ड दिया है और पूरे देश में देखें तो 11221 नौजवान बेनिफिशरी रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो छात्र विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम समय-समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि किस तरह से माइनोरिटी अफेयर्स में काम चल रहा है, यह जानकर काफी अच्छा लगा।

सर, एक और चीज है कि पढ़ो परदेश स्कीम की गाइडलाइंस को हम देखें तो इसमें एक पॉइंट है कि इस स्कीम के तहत 35 per cent of seats will be earmarked for girl students. अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स की अवेलिबिलिटी नहीं रहती है तो वह बॉयज स्टूडेंट्स को ट्रांसफर हो जाएगा और इसका पीरियोडिकल रिव्यू मंत्रालय से हम करेंगे। क्या इस तरह का अगर कोई रिव्यू हुआ है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो 35 परसेंट इयरमाकर्ड है, क्या उसको रीच किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो किस तरह से इसको हम प्रमोट करेंगे ताकि 35 ही नहीं, उससे भी बढ़कर हम गर्ल्स स्टूडेंट्स तक यह स्कीम पहुंचा सकें।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह बात सही है कि 35 परसेंट गर्ल्स के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि 35 नहीं, बल्कि उससे ज्यादा वे लाभार्थी हों। जैसे हमारी स्कॉलशिप है, इसमें हमने 35 परसेंट तक लड़कियों के लिए रिजर्व किया है, जबकि हम 62-67 परसेंट तक देते हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिलकुल सही है कि हम समय-समय पर स्कीम को रिव्यू भी करते हैं और नोडल बैंक को भी समय-समय पर दिशा-निर्देश देते हैं कि जो बच्चियां एलिजिबल हैं, उनको उसका लाभ दिया जाए।

(इति)

(प्रश्न - 63)

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखण्ड के गिरिडीह लोक सभा संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को आवास प्रदान करने का लक्ष्य क्या हासिल किया गया है? यदि हां, तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत झारखंड के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कितने लाभार्थियों को आवास आबंटित किया गया है?

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना जून, 2015 में प्रारम्भ हुई थी और उस समय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हर एक भारतीय नागरिक को अपना आवास दिलवाना, जिसमें एक पक्का घर होगा, उसमें एक किचन होगा, टॉयलेट होगा और बाकी सब सुविधाएं भी होंगी। इसके बारे में हमने जांच करवायी थी कि कितने आवास ऐसे बनाने होंगे और सैंक्शन करने होंगे? इसका नतीजा यह निकला था कि एक करोड़ से अधिक होगा। बाद में जब डिमाण्ड असेसमेंट की गयी तो उसमें 1 करोड़ 12 लाख एगजैक्ट निकले। मैं बहुत खुशी से और बड़े गर्व से इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिसम्बर के महीने में हमने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और हमने 1 करोड़ 3 लाख आवास ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। जहां तक झारखण्ड का सवाल है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। The total number of houses sanctioned is 1,98,751. Out of this, the number of houses grounded for construction is 1,35,156 and the number of houses where construction is completed is 76,865. The number of houses occupied is 76611 जिनमें लाभार्थियों को आवास दे दिए गए हैं और लाभार्थी उनमें रह रहे हैं।

(1115/SJN/NKL)

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : महोदय, अपना आवास सबका सपना होता है। पूरे कुनबे के साथ अपनी खुद की छत के नीचे जिन्दगी बसर करने की सबकी हसरत पूरी हो सके, इसी सोच के साथ सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सामुदायिक कल्याण योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध करा सकें। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 1,500 आवासों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन अभी तक मकान बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : आपके यहां शहरों के लिए स्वीकृत किया गया है, या गांवों के लिए स्वीकृत किया गया है?

...(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, my Ministry has jurisdiction for the urban areas. मैंने यहां पर जो आंकड़े दिए हैं, वे शहरी क्षेत्रों के लिए दिए हैं। जहां तक ग्रामीण इलाकों का सवाल है, the Ministry headed by my senior colleague, Shri Narendra Singh Tomarji, वह उनके पास है।

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी से यह आग्रह करिगा कि वे माननीय सदस्य को बुलाकर उनसे चर्चा कर लें।

श्री हरदीप सिंह पुरी : महोदय, मैं उनसे वह आंकड़े लेकर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मंत्री जी उनको बुलाकर चर्चा कर लें।

...(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : हम उनसे आपकी भेंट करवा दूंगा...(व्यवधान)

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity.

I would like to know from the hon. Minister, through you, whether there is any scope in PMAY to provide funds for purchase of house sites to marginalised sections like SCs, STs, OBCs, minorities, and physically challenged persons in Andhra Pradesh, especially in Hindupur Lok Sabha Constituency; and if so, the details thereof.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Mr. Speaker Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana was conceptually designed to provide a *pucca* house, and to ensure that every Indian citizen gets a home by 2022 essentially through four verticals. The first is the Credit Linked Subsidy Scheme, which means that if a person desiring to buy an apartment, who would need to take a loan, typically goes to a bank, and let us say that hypothetically, the bank charges an interest rate of 12 per cent, then under the Pradhan Mantri Awas Yojana, if the applicant comes under certain categories like Economically Weaker Sections, LIG or even MIG, he would get an interest subvention of 3 per cent upfront which would lower the applicant's cost of borrowing. The other vertical is Beneficiary-led Construction which means if an applicant owns a traditional family home which requires upkeep or renovation, then the State would provide a sum of Rs. 1,50,000 for that purpose. The third is In-situ Slum Rehabilitation. I suspect, Mr. Speaker Sir, that some of the questions raised by the hon. Member could be covered under this vertical of In-Situ Slum Rehabilitation. The fourth vertical is Affordable Housing in Partnership in which typically, the State Government provides the land and both the State Government and the Central Government provide an element, say Rs. 1,50,000 by the Central Government, and the States may vary. There is no scope within the Pradhan Mantri Awas Yojana's architecture, as it is currently designed, for loans to be given to particular sections of the society. But

the ambit, through those four verticals, is broad enough for marginalised sections like SCs, STs, etc. to avail the facilities under the four verticals.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity. I would also like to thank the hon. Minister for a detailed answer.

In Tamil Nadu, in the process of selection of beneficiaries, there are a large number of complaints, particularly at the local level and the State level. Is there any system or mechanism through which these kinds of corrupt practices at the local level as well as the State level could be reduced? The State Government has institutionalised corruption in a very organised way in Tamil Nadu.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to respond in terms of the process and architecture in place. What any particular State Government is doing or not doing, I think, is outside the scope of this answer. There are enough safeguards. The important issue is, under the different verticals, the State Government can only propose.

(1120/KSP/GG)

If we are looking at the vertical of Credit-Linked Subsidy Scheme, the applicant goes directly to the bank and it is between the bank and the applicant. So, there is no scope for the State Government. But if we go under In-situ Slum Rehabilitation, then it is not an individual who is being benefited, it is an entire community living in an informal settlement or what you would call a slum and the entire community would have to be provided rehabilitation through rebuilding of that informal settlement.

When it comes to Beneficiary-Led Construction, yes, I think the State Government has to do some vetting to make sure that the person who is claiming the loan actually has a traditional home etc. Now, when it comes to Affordable Housing in partnership, some safeguards are built in. It is up to the State Government to identify beneficiaries. We have several examples of applicants, who would like to get it and who do not qualify, are happy to approach the State Government. But the State Government, after vetting, sends it to a Committee in my Ministry, which is headed by the Secretary in the Ministry called the Committee for Monitoring and Sanctioning of Projects and then they will go through this.

But, as I said, individual cases in a particular State need to be looked at and if there are complaints, there are mechanisms in place to address those complaints.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा प्रधान मंत्री आवास सूरत के स्मार्ट शहर में बने हैं। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब जो फॉर्म फिल-अप किया जाता था, उसमें महिलाओं का नाम आवश्यक था। उसी को इस सब्सिडी का लाभ मिलता है। करीब तीन हजार लोग ऐसे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। उनकी माँ का या उनकी बहन का नाम उसमें दाखिल करने का कोई एक प्रावधान किया जाए, तो उनको भी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। कम से कम तीन हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सिंगल नाम से प्रधान मंत्री आवास के लिए अप्लाई किया था, मगर उनको इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, whether the applicant is single or married, only once you can apply under the Pradhan Mantri Awas Yojana. But if some beneficiaries have been left out because of the categorization of their marital status, I am sure this is something we can look at and rectify.

I should have also answered another thing. In response to the previous question, I told to the hon. Member that there are safeguards. मैं बड़ी खुशी से उनको बताना चाहता हूँ कि जो पोटेंशल बेनिफिशरीज हैं, अगर उनको लगता है कि राज्य सरकार उनकी एप्लिकेशन को सीरियसली नहीं ले सकती है, तो वे मंत्री की वेबसाइट – pmay-urban.gov.in पर सीधे हमको भेज सकते हैं। हमने कई ऐसे केसेज टेक-अप भी किए हैं। फिर हम राज्य सरकार को कहते हैं कि हमारे पास यह एप्लिकेंट आया है। किस कारण से आपने इस एप्लिकेशन को आगे नहीं बढ़ाया है? It is a system which is working. Your decision to characterize the State Government as X, Y or Z is something we can politically discuss separately.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, अर्बन में जो हाऊसिंग बन रहे हैं, अभी मंत्री साहब ने बताया है कि एक रूम, एक किचन और एक टॉयलेट बना कर दे रहे हैं। सर, हम लोगों ने तेलंगाना में अर्बन इश्यूज को देखने के बाद, पॉप्युलेशन के इश्यूज देखने के बाद तय किया कि एक फैमली को एक रूम में रहने में बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोग डबल बेडरूम के हाउसेज बना रहे हैं। डबल बेडरूम, एक हॉल और दो बाथरूम के साथ हम लोग इसको बना रहे हैं। उसमें एक हाउस के लिए 6 लाख 50 हजार रुपये की कॉस्ट आ रही है। आप सिर्फ एक लाख 50 हजार रुपये दे रहे हैं। एक रूम में फैमली, बाल-बच्चों के साथ रहने में बहुत परेशानी है। ... (व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि बेनिफिशरी में जो इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैसे सॉर्टआउट करना है। ... (व्यवधान) तेलंगाना में हम लोगों ने पूरे हाउसेज कम्पलीट करने के बाद बेनिफिशरी को सामने रख कर। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, बेनिफिशरी को सामने रख कर हमने कलैक्टर के सामने लॉटरी का सिस्टम किया है। बेनिफिशरी में हम लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम सरकार को यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लैंड कॉस्ट राज्य सरकार बियर कर रही है। आप पूरे देश में डबल बेडरूम हाउसिंग का सिस्टम ले कर आएं। गरीब आदमी भी कम से कम बाल-बच्चों के साथ दो रूम में निवास कर सके। ... (व्यवधान)

(1125/KKD/KN)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to inform the hon. Member that the vertical of affordable housing and partnership, जिसका वह जिक्र कर रहे हैं। उसमें टिपिकली जो घर बन रहे हैं, वे एक कमरे के नहीं हैं। मैंने सूरत में जाकर देखे हैं, हैदराबाद में जाकर देखे हैं और बाकी जगह देखे हैं। अक्सर उसमें दो कमरे होते हैं, किचन होता है, हॉल हो न हो, वह उस प्लॉट साइज़ पर डिपेंड करता है। उसमें बाकी सुविधाएँ भी होती हैं। ये जो 6.5 लाख की कॉस्ट बता रहे हैं, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, लैंड जो है, अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप स्कीम, वह तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है और टिपिकली किसी भी आवास में जो जमीन की कीमत है, वह करीबन 40-45 प्रतिशत होती है। उसके बाद टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट में केन्द्रीय सरकार डेढ़ लाख रुपये देती है, पर स्टेट गवर्नमेंट डेढ़ लाख रुपये दे या दो लाख रुपये दे, कुछ स्टेट्स ज्यादा भी दे रही है, तो 6.5 लाख रुपये कॉस्ट पड़ती है। उसमें एप्लिकेंट अपनी तरफ से भी कुछ डालते हैं और मैंने देश भर में कई ऐसे आवास बने देखे हैं, कॉस्ट उसकी 6.5 लाख रुपये हो, पर उसकी मार्केट वैल्यू उस समय 25-30 लाख रुपये होती है और इसलिए लाभार्थी बहुत खुश हैं।

The other point that I want to submit is that this is a scheme, which was scheduled to be completed by 2022. We have almost completed the numbers now. In the month of December, we sanctioned 6.7 lakh homes, which is the subject of the next Question, and one of the schemes is already completed. I do not see any possibility at this stage to raise the Centre's contribution from Rs. 1.5 lakh upward. As the hon. Member himself has submitted, अगर 6.5 लाख रुपये आवास की कॉस्ट है, जिसमें जमीन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और हम डेढ़ लाख रुपये दे रहे हैं। अगर लाभार्थी को एक ऐसा आवास, जिसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपये है, उसमें अपनी सैविंग्स से डेढ़-दो लाख रुपये दे दिए, and so, this fits in with the spirit of the scheme.

(ends)

(Q. 64)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, Housing for all by 2022 is the Government's initiative. I want to know from the hon. Minister: Is it true that in this year's Budget in the PMAY, his Ministry has been granted Rs. 27,500 crore? Is it also true that to complete 1.12 crore houses, it will trigger an investment of more than Rs. 7 lakh crore? I want to know, how does he intend to generate this revenue because I am sure, he does not have a magic lamp wherein a genie comes out and gives him Rs. 7 lakh crore in two years. That is my first Supplementary to the hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to inform the hon. Member that yes, it is the Government's objective as enshrined in the Prime Minister's original statement that it is his dream that by 2022, every Indian citizen, no matter where he or she lives, should have a home of their own with the title in the name of the lady of the house in order to encourage gender empowerment and also, that it should be a pukka home with a kitchen, a toilet, and all other facilities, which will be provided in a modern home.

Now, when we embarked on this scheme, we realised that you needed to do a demand assessment, and the demand assessment was done before I joined this Ministry. According to that, we would have to construct or sanction one crore homes. This demand assessment was subsequently revised to 1.12 crore. In the month of December, the Committee for monitoring and sanctioning of projects headed by the Secretary in the Ministry, approved 6.7 lakh homes under the request received. This took the figure over the one crore mark, and we have now sanctioned one crore three lakh houses.

(1130/RP/CS)

The overall figure of 1,12,00,000 will also be sanctioned, I think, within the next month or two. Now, the issue comes on whether a project of this magnitude, a project which is so ambitious, can be financed through a budgetary allocation. I think, on an average, if my memory serves me right, we were getting about Rs. 6,500 crore in our budgets over the last five years. This was clearly not sufficient for us to be able to finance a project of this scale. Therefore, soon after I became a Minister, we started examining the possibility of additional funding through the National Urban Housing Fund (NUHF) and we were able to secure another Rs. 60,000 crore. In many of these projects, first of all, in overall

terms, out of 1.12 crore, 32 lakh beneficiaries have already received their homes. They are living in them. Another 60 lakh to 62 lakh beneficiaries have had their projects grounded and work is going on. We have made the initial payment but we will require more funds.

In order to prepare myself for this question, this morning – I knew that I would be asked this question – all I can say, out of the earlier Rs. 60,000 crore, we have just got a release of Rs. 5,000 crore. We still have another Rs. 7,000 crore cushion there but very soon we will have to look at another tranche of extra budgetary funding. I want to assure the hon. Member and this House that we intend on getting this scheme completed well before 2022 and we will find the resources in order to be able to complete that task.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं आपकी मदद चाहता हूँ...(व्यवधान) मैं यहाँ पर आपकी मदद चाहता हूँ...(व्यवधान) आप इनको इतनी आसानी से न छोड़ें।

सर, मेरा सवाल यह था कि मिशन 2022 के तहत आपने वादा किया कि एक करोड़ 12 लाख घर बनाए जाएंगे। मैंने मोहतरम से पूछा कि आपको इस साल बजट में 27,500 करोड़ रुपये दिए गए। एक करोड़ 12 लाख घरों को मुकम्मल करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री को क्या 7 लाख करोड़ रुपये की जरूरत नहीं है? आप फिरा-फिरा कर कभी फास्टर वन, कभी गुगली, कभी चक कर रहे हैं, सर यह क्या है?... (व्यवधान) सर, आप देखिए। अब इसी में चले आते हैं। हमने मोहतरम, वजीर साहब से एक पॉइंटेड सवाल किया और वे बोल रहे हैं कि रिसोर्सेंज जनरेट करेंगे। आप जनरेट करेंगे तो वादा करिए कि 7 लाख करोड़ रुपये देंगे। वह जवाब नहीं दिया गया है।

मेरा दूसरा सप्लीमेन्टरी मिनिस्टर साहब से यह है कि do you know that four days ago in Mau District of Uttar Pradesh, an old woman died because of collapse of stairs under the same PMAY? There are so many complaints about the quality of construction. What steps are being taken by your Ministry to ensure that the quality of construction is of good standard or whatever standard is prescribed? I also want to know from the hon. Minister one more thing. Have all the instalments under this Scheme been transferred to beneficiaries in a timely manner so as to enable them to construct their houses at the earliest? What is the total number of beneficiaries whose claims are pending as of date? What measure is it adopting to ensure timely payment of instalments at the grassroot level?

सर, यह मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे रेस्क्यू चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब बड़े काबिल जरूर हैं, वे ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, लेकिन वे हमें थोड़ा इसका जवाब दें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to inform the Member that this is not a game of cricket and I have provided straight answers with a straight bat and front foot forward. ...(*Interruptions*) Let me repeat that Rs. 27,500 crore is for the Ministry and not for affordable housing. As I said, over the past five years, we have been getting an average about Rs. 6,500 crore or so. Out of this Rs. 27,500 crore, what comes under PMAY is about Rs. 8,000 crore. You cannot have a situation where we cook up the figure and then say that this is a figure as if it has a finality. It could be Rs. 700 thousand crore or it could be Rs. 900 thousand crore. I am trying to explain that the scheme is implemented through four verticals. It is not that 1.12 crore homes are being built. Some are being sanctioned. Some are amounts as small as Rs. 1,50,000 which are given to the beneficiary for construction. If Mr. Owaisi, the hon. Member, has a home of his own and he wants to get it, he will get Rs. 1,50,000.

(1135/RCP/RV)

Equally, if you have a credit linked subsidy scheme in which we have an interest subvention, you are a young professional, you go to a bank, you want to borrow money, we give you three per cent upfront. So, the figure is not Rs.700,000 crore. So, you get the correct figure and then you seek the Speaker's help. You do not need the hon. Chair's help. I am providing the figure ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): What is the figure you require to complete...(*Interruptions*) What is the figure? Please tell us.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am providing you the figure. I am saying that for the total figure, I think, we will need another Rs.70,000 crore or so, apart from the budgetary grants that we have got on an average of Rs.6500 crore a year for five years, Rs.8000 crore this year, and we will keep getting till 2022. If you set those aside, take Rs.60,000 crore which we have got through extra-budgetary funding, may be another Rs.70,000 crore. But I cannot answer the question till I know the specifics of this. Please do not create a false narrative on this subject as well. I am providing you the answer. ...(*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, I want to place the following facts before the House, through you. The situation is, when you carry out a major scheme like this which provides a major transformation where every Indian has a home of their own, these come in different forms. Affordable housing in partnership is one. Let us

say, in previous five years, we got an average of Rs.6,500 crore. ...(*Interruptions*) Now we are in a situation where we are going to exhaust Rs.60,000 crore. We will need another infusion. The total will be about Rs.120,000 crore or Rs.130,000 crore but the exact figure will come when you know precisely how many beneficiaries are there under CLSS and how many beneficiaries are there under beneficiary-led construction.

Sir, the precision in figures is not a part of a political debate. It is precision in order to deliver. The issue is that the homes are being delivered. ...(*Interruptions*) Extra-budgetary funding is to be arranged as we arranged the previous Rs.60,000 crore and we will arrange the next tranche as well.

श्री सैयद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने इसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि जब वर्ष 2016 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो लोगों के अन्दर एक उम्मीद जगी थी कि हर गरीब के सिर पर एक छत रहेगी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो उत्तर हमें दिया गया है, उसमें हम अगर सिर्फ अपनी ही कंस्टीट्यून्सी की बात करते हैं तो वहां के 80,000 गरीब लोगों ने इस उम्मीद पर इसका एप्लीकेशन भरा है कि वे इस स्कीम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन, अभी तक जितने घर सैंकशंड हुए हैं, उनमें 18,178 घर पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए हैं जबकि सिर्फ मेरे ही शहर में 80,000 बेनिफिशियरीज हैं।

माननीय मंत्री जी से हम यह कहना चाहेंगे कि इतने सालों में हमारे यहां के महज 50 लोगों को इसके लिए क्वालिफाई किया गया है। ये जितने भी लोग हैं, ये स्लम एरिया में रहते हैं। उनके घर छोटे-छोटे हैं। इसमें जो कंडीशंस डाले गए हैं, जैसे इसके लिए रजिस्ट्री होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर ये लोग बॉण्ड पेपर के आधार पर कई सालों से उस जगह पर रहते हैं। अब आप उन्हें कहेंगे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ये लोग तो कई सालों से उसी जगह पर रह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना सवाल पूछें।

श्री सैयद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): महोदय, हमारा यह सवाल है कि इसके लिए जो कंडीशंस हैं, क्या उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है या क्या इसे दोबारा रिव्यू किया जाने वाला है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I think, there is a little bit of overlap between the Pradhan Mantri Awas Yojana for the *gramin* areas or rural areas and Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban areas. As I said, some of the figures which we are citing here are for the rural areas. Insofar as the urban areas are concerned, I want to repeat that extra-budgetary funding through the National Housing Board Fund was created for Rs.60,000 crore. We will provide another tranche for this thing. Insofar as the specific areas are concerned, if there are rural areas, the application will have to be made under Pradhan Mantri Awas

Yojana – Gramin. We will have completed our targets by March 2022. If the demand assessment shows that some more applicants are there in urban areas, we will find out under which vertical there are. These are the issues which can be looked at. In Maharashtra, a total of 11.77 lakh homes have been sanctioned. (1140/SMN/CP)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my supplementary question has got two parts. The first part of the question is with regard to the central allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) scheme. In order to have benefit under the BLC schemes, the amount which has been given is just Rs. 1.5 lakh and for Slum Redevelopment scheme, it is rupees one lakh. Sir, if you examine the State allocations regarding this Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), for example, in the State of Kerala, we are allocating Rs. 2.5 lakh in the case of BLC and in the case of Affordable Housing programme, it is rupees five lakh in total. The allocation from the Central Government under the Pradhan Mantri Awas Yojana is very meagre. It is negligible. So, would the Minister and the Government take into consideration the need to increase the central allocation for the construction of the house? This is the first part of my question.

My second part of the supplementary is this. What is the role of the Members of Parliament in designing and determining the beneficiaries and the supervision of the PMAY? You may kindly see this.

Hon. Speaker Sir, we are all seeking the protection not only under the PMAY but also in all the centrally sponsored schemes regarding the role of the MPs. Even the municipal councils and the corporations are not even inviting the Members of Parliament for reviewing the programme. I would like to know about this. This is the second part of my supplementary question.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member through you that some of the examples he has cited, the Centre's allocation of Rs. 1.5 lakhs may not appear enough but this has to be seen in the context of how the *in-situ* rehabilitation is effected. For instance, we have an example in Delhi of Katputli colony where 2800 families were living and here, the development is done through a PPP model whereas a developer is assigned by the State Government. I do not know what the situation in Kerala is and elsewhere; and they are developing that by temporarily relocating the inhabitants there nearby.

In 1975, when civil liberties were dispensed with, people were settled 100-200 kilometres away. It was called the Emergency then. We do not do those things. We take the people and we put them nearby temporarily and then we bring them back after the development has been done.

Sir, so far as the States' share is concerned, if the scheme were not taking off and if we had a shortage of applicants for the Pradhan Mantri Awas Yojana, I could have said that a very strong case has made out but the resources are limited. They have to be spent in the most effective and efficient manner and I believe the State Governments are compensating for that and providing more resources like the State of Kerala is providing more than Rs. 1.5 lakhs. We are giving only Rs. 1.5 lakh and the scheme is working very well under different verticals and the proof of that lies in the fact that the targets have been met almost two years before the completion date.

(ends)

(प्रश्न 65)

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सर, मेरा क्वेश्चन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। अभी तक 7 स्टेट्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए, तो पश्चिम बंगाल के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 per cent of the Bengali population are suffering from this arsenic problem.

1144 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

मतलब पानी तो है, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। That is called physiological drought condition. सबसे अलार्मिंग बात यह है कि 18 districts of West Bengal are engaged in paddy cultivation वेस्ट बंगाल लीडिंग कल्टीवेटर है। आप जानते हैं कि पैडी में बोरो कल्टीवेशन होता है। इस कल्टीवेशन में ग्राउंडवाटर को खींचकर पैडी को दिया जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ही सालों में वेस्ट बंगाल के ग्राउंड वाटर लेवल में और भी डिप्लीशन होगा और वहां आर्सेनिक के साथ फ्लोराइड का पॉल्यूशन भी आएगा।

मेरा मंत्री जी से क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जो समस्या सामने आ रही है, इसको कॉप-अप करने के लिए अटल भूजल योजना में क्या प्रावधान है?

श्री रतन लाल कटारिया: मान्यवर, अटल भूजल योजना को श्रेष्ठ अटल जी के जन्म दिन पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने लागू किया। इसमें 7 राज्यों को लिया गया है।

(1145/NK/VR)

ये वे राज्य हैं जो वाटर स्ट्रेसड एरिया के अंतर्गत आते हैं और जिनको पहले चिन्हित किया गया था। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट की 50-50 परसेंट की फंडिंग है। इन राज्यों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए इन सात राज्यों को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, जब कोई आगे फेज चलेंगे तो उस समय इन सब बातों के ऊपर विचार हो सकता है।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, जो टाइप-दो सिटीज हैं, अभी वहां अबर्नाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइप-दो सिटीज और जो उससे छोटी सिटीज हैं, वहां बड़े-बड़े हाउसिंग कम्प्लेक्स बन रहे हैं। These housing complexes are drawing water from the ground. मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जो टाइप-दो सिटीज हैं या उससे छोटी सिटीज हैं, उसमें जो हाउसिंग कम्प्लेक्स बन रहे हैं, क्या उनमें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान है? क्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करने का प्रावधान मेनडेटरी करने का कोई प्लॉन है, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी हो?

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति महोदय, जो अर्बन एरियाज हैं उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कुछ नार्म्स बनाए हैं और सौ मीटर से ज्यादा के प्लॉट में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करना लाजिमी होगा, इसके बारे में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

1146 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Sir. According to the Composite Water Management Index-2019 released by the NITI Aayog, Odisha has been placed as a low-ranking State at 13th rank. The Central Ground Water Board has clearly indicated that ground water in 24 out of 30 districts is depleting and the State is facing a major water crisis.

The Government of Odisha has not enacted any ground water legislation and is yet to set up an integrated water data centre. In this context, I would request the hon. Minister if the State of Odisha can be included in the Atal Bhujal Yojana.

Sir, my question to the hon. Minister is, whether the Government has formulated any mechanism to monitor the efficient implementation of the scheme to enable proper utilization of funds by the States through social audit to evaluate its impact assessment and what steps are being taken by the Government to promote rain water harvesting in community water purification plants in order to provide potable water to the public. Thank you.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 18 परसेंट है और हमारे पास इतना ही पशुधन है। भारतवर्ष में जो वर्षा होती है वह केवल चार प्रतिशत ही होती है। उसका आठ प्रतिशत ही हम केवल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बचा पाते हैं, शेष पानी वाष्पीकरण के माध्यम से या डेजर्ट में वेस्ट चला जाता है।

अटल भूजल योजना को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत भूमि के जलस्तर को ऊपर उठाकर सबको पानी देने का प्रयत्न किया जाएगा। ओडिशा की जो मांग आई है, अभी सात राज्य लिए गए हैं उसमें ओडिशा नहीं है। जब फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा, उसके बाद इन राज्यों के बारे में भी विचार-विमर्श कर लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि क्वेश्चन और आंसर शार्ट में हो, इससे हम अधिकतम माननीय सदस्यों के प्रश्न ले पाएंगे। माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शार्ट में सवाल जवाब दें और शार्ट में सवाल पूछें।

(1150/SAN/SK)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, it is also to be seen that when a Minister is replying to a question, he should not be arrogant, at least, while he is replying. ...(*Interruptions*) He was ... (*Not recorded*) a few minutes back. ...(*Interruptions*) Hon. Minister Shri Puri was ... (*Not recorded*). This type of attitude should not be reflected on the floor of the House. ...(*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the Minister is aware that the NITI Aayog has given a report stating that more than ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: उनका ऐसा बोलने का स्वभाव नहीं है, दिखते हैं लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट हैं।
...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Is the Minister aware that the NITI Aayog has earmarked 10 States where by 2020, the groundwater will go totally dry? There are more than 21 such districts, and especially Central Chennai which I represent, are predicted to be totally dry of groundwater in this year itself. Unfortunately, out of Rs. 6,000 crore granted, only seven States are benefitting from it. No work has been started in Punjab, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

Sir, I would like to say that Chennai went through the worst crisis last year. People were totally on the roads even for a bucket of water. Why is there discrimination against Tamil Nadu and why is there discrimination against Chennai. Tamil Nadu Government is your ... (*Not recorded*) Government. You just have to wink and they will fall at your feet. You should do something on that.

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक फरमाया है कि नीति आयोग ने कुछ शहरों के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2020 के बाद पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं इसके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि नीति आयोग ने जो आकलन किया है, एक्वा लेयर फर्स्ट स्टेज का है। एक्विफर के नीचे जो पानी बहता है, नीति आयोग ने उसका अध्ययन नहीं किया है। यह बात सच है कि शहरों में कंक्रीट के ढांचे खड़े होने के कारण पानी की समस्या आई है।

हमारे सारे के सारे परंपरागत वाटर रिसोर्सिस सूख गए हैं। जो बावंरिया चलती थीं, नहीं चल रही हैं, कुएं बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान लिए हैं। 18 पेनिसुलर रीवर रीजन्स को नदी जल योजना के अंतर्गत लिया है, 14 हिमालय रीवर रीजन के क्षेत्रों को लिया है। हम नदी जल योजना के माध्यम से पानी को लाने का प्रयत्न करेंगे।

इसके साथ ही अटल भूजल योजना के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी सरपंचों को इसके बारे में पत्र लिखा है कि वे अपने क्षेत्रों में पानी का प्रबंध करें। आपने जो बात कही है, उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। हम इसके अंतर्गत पानी प्रदान करने की पूरी योजना बनाएंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले आठ महीने में जो सत्र हुए हैं, मैंने एक विषय पर पूरी संख्या जोड़ी है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली है कि अभी तक जो सत्र चला है, उसमें लगभग 286 सांसदों ने पानी और पीने के पानी की समस्या की चर्चा की है। चार प्रश्न जल पर हैं, चाहे पीने का पानी हो, ग्राउंड वाटर हो या एक्विफर्स हो।

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): हाउस को आर्डर में लाने के लिए पृष्ठभूमि देना बहुत जरूरी है।

महोदय, यह मामला बहुत संगीन है, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता होगी। यह बात सही है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस बार पांच वर्ष की कार्य अवधि में जल शक्ति मंत्रालय बना है। देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस मंत्रालय का गठन इसलिए कहा है क्योंकि सचमुच आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ी समस्या होगी।

एक उत्तर में सरप्लस पानी और वाटर डेफिशिएंट के बारे में कहा गया है। सारण जिले को वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है।

(1155/MK/RBN)

इसलिए यह सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। नेपाल से आने वाला पानी लगभग 12 किलो मीटर नेपाल में चलता है, उसके बाद पश्चिमी तटबंध में 116 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में चलता है, फिर बिहार में 64 किलोमीटर प्रवेश करता है। यह रबी की फसल है। नेपाल से 15 हजार क्यूसेक पानी भारत को दिया जाता है, जिसमें से सात हजार क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश को और आठ हजार क्यूसेक पानी बिहार में आता है। पिछले छः माह से एक बूंद पानी, बिहार के तीन करोड़ किसान जो सिवान, गोपालगंज और सारण में रहते हैं, पिछले छः माह में न खरीफ की फसल में, न रबी की फसल में, प्रत्येक महीने, मैं दोहराना चाहूंगा, प्रत्येक महीने आठ हजार क्यूसेक पानी जो बिहार में आना चाहिए था, उसे चोरी कर लिया जा रहा है। उसे बिहार तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। यह दो राज्यों और एक देश के बीच की संधि है। अगर, मेरे किसानों को, चूंकि यह रबी की फसल है, हमारे यहां कम से कम 400 किलोमीटर नहर है, एक बूंद पानी न सारण में है, न सिवान में है और न गोपालगंज में है। यह जो संधि है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ, मंत्री जी मेरे किसानों का पानी कहां है? ...(व्यवधान) आप मुझे ढूंढकर बताइए कि मेरे किसानों का पानी कहां है? अगर, पानी नहीं है तो पानी कहां चोरी हुई, किसके पास यह पानी है, जो किसानों के खेत में जाना चाहिए, उस पानी को मेरे खेतों में पहुंचाने के लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? यह मेरा आपसे सवाल है।

...(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। अगर, ये मेरे चैम्बर में आएंगे तो अलग से मैं इन सारी समस्याओं पर बात करूंगा।

(इति)

(Q. 66)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Speaker, Sir, it is quite unfortunate and mindboggling to know that according to the Second Report of NITI Aayog, by 2020, 21 States will not have access to fresh water, two lakh people will die this year and that 600 million people will face acute water crisis. This is a matter of grave concern. The Government of India should come forward and take steps in this regard. At least now they should wake up from their deep slumber.

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): When the other Member went on asking questions, you allowed it. Please hear me.

माननीय अध्यक्ष: घड़ी में बारह बजने वाले हैं।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I would like to know whether the Government of India will come forward at least now with a detailed comprehensive scheme to see that water is made available to all the States without fail. They should not pass the buck to the States.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि देश के अंदर सभी घरों में 'नल से जल' देने की व्यवस्था भारत सरकार करने जा रही है। हमें प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसी योजना भारत सरकार ला रही है, जिसमें अभी तक हम सत्तर सालों में केवल तीन करोड़ परिवारों को नल से जल दे पाए थे, अब हम पन्द्रह करोड़ घरों को 'नल से जल' देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये से एक नया और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसको पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाएं भारत सरकार बना रही है और उसी के अंतर्गत 'अटल भूजल योजना', 'अटल जल मिशन' आता है और मनरेगा के अंतर्गत भी बहुत-से काम किए जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो बीस शहरों के बारे में बातचीत की थी, वे सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार स्ट्रैटजी बना रही है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Chennai city is facing acute water crisis every year. That is what my colleague Shri Dayanidhi Maran has already stated. This is the most important Question. Every year the city is not getting water because all the sources and lakes, like the Chembarambakkam, Poondi, Red Hills and Cholavaram get dried up during summer.

(1200/SM/YSH)

People of Chennai are facing acute water crisis. I want to know from the responsible Minister on the other side whether this Government will come forward to adopt Israel model. Israel is supplying water from the sea by establishing floating desalination plant in the sea, where 80 per cent of that nation has been covered by this. Why is it not in India? Are you not sensitive to this issue?

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जल की समस्या को हल करने के लिए किसी देश का नहीं, बल्कि मोदी मॉडल को अपना रहे हैं। मोदी मॉडल के अन्तर्गत हर घर में 55 लीटर पानी दिया जाएगा।

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री किरें रिजीजू।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2018-2019.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Power System Operation Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Power System Operation Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Power System Operation Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.
- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Power for the year 2020- 2021.
 - (ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Power for the year 2020-2021.
 - (iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (a) (i) Review by the Government of the working of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (b) (i) Review by the Government of the working of the NBCC (India) Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the NBCC (India) Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (c) (i) Review by the Government of the working of the Air India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Air India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (c) of (1) above.

(3) A copy of the Central Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.883(E) in Gazette of India dated 29th November, 2019 under article 309 of the Constitution of India.

(4) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Civil Aviation for the year 2020-2021.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री मनसुख एल. मांडविया की ओर से, मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. सा.का.नि. 06(अ) जो 2 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 का अनुमोदन किया गया है।
2. सा.का.नि. 27 (अ) जो 13 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2020 का अनुमोदन किया गया है।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Sir, on behalf of my colleague Shri Dhotre Sanjay Shamrao, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Department of Posts for the year 2020-2021.
- (2) Output Outcome Framework of the Department of Posts for the year 2020-2021.

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
3. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
5. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

**COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS
OF THE HOUSE
Minutes**

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the First sitting of the Committee on Absence of Members from the sitting of the House held on 27.11.2019.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 25TH REPORT OF STANDING COMMITTEE
ON URBAN DEVELOPMENT -- LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Urban Development (2018-19) on 'Solid Waste Management including Hazardous waste, Medical waste and E-waste' pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

विशेष उल्लेख

1204 बजे

माननीय अध्यक्ष : डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you, Sir. Actually, the Government is providing free medicines for the poor people. But 50 per cent of the population goes to the private hospitals and corporate hospitals. The corporate hospitals exploit and extract maximum from the pharmaceutical companies and get almost 40 to 50 per cent discounts in MRP of the medicines as well as surgicals. I would like to know whether the Government has any plan to interfere and ensure that these corporate hospitals extend these discounts to the patients for medicines and surgicals.

In almost all the corporate hospitals, there is a saying and there is a grievance from the patients that in ICU, IMCU as well as in IP, the medicines and surgicals that have been utilised are circulated and actually not used. But in the bills, it is being reflected.

I want the Union Government to interfere and devise a mechanism so that this misuse of drugs as well as surgicals does not take place.

(1205/AK/RPS)

Moreover, some scheduled drugs are also being sold on online pharmacies. Normally, in pharmacies, the Pharmacists are in-charge and Drug Inspectors come and check it almost every month. Where are the checking devices for online pharmacies? These drugs are available to the youngsters, and the younger generation is getting spoiled. So, the Government has to interfere and stop this misuse of drugs and surgicals. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. संजय जायसवाल एवं श्री मलूक नागर को डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। श्री अनुभव मोहंती।

माननीय सदस्य, हमेशा पार्लियामेंट में एलर्ट रहा करें, पता नहीं कब किसका नम्बर आ जाए।
SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, the District Mineral Foundations (DMF) established in each district of Odisha has received substantial amount of contribution. Many projects and activities are undertaken in the mining-affected villages and for the affected people as per the rules and guidelines. Presently, income tax has been deducted from the interest on the fund accrued on the ground that it is interest income.

This being a sensitive issue, the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, drew the attention of the Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India *vide* his letter dated 03.10.2019 requesting exemption of the District Mineral Foundation funds from the incidence of income tax with retrospective effect in the interest of the area and people affected by mining activities.

A total sum of Rs. 8,474.42 crore has been collected under DMF till 30.09.2019 by all the 30 districts, and the likely annual accrual to the fund is around Rs.1,800 crore to Rs. 2,000 crore every year. Rs. 39 crore has already been deducted towards income tax on interest income of DMF's of some of the districts till September, 2019.

Unless the DMF Trust fund is exempted from the purview of the provisions of Income Tax Act, 1961, the DMF Trust fund will attract huge tax liability from inception, and a substantial amount of DMF funds will be spent to clear the income tax liability, which will have adverse bearing on these resources and will defeat the very objective of the scheme for upliftment of socio-economic conditions of the people in mining-affected areas.

Sir, through you, I would like to request the hon. Minister to kindly address this issue very seriously and as quickly as possible. Thank you so much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अनुभव मोहंती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुकेश राजपूत ।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730सी है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। इसकी हालत बहुत ही दयनीय एवं जर्जर है। यह राजमार्ग मात्र सात मीटर चौड़ा है। इस राजमार्ग पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। फर्रुखाबाद में इसी मार्ग से लगी हुई तीन नदियां – गंगा नदी, काली नदी और राम गंगा नदी हैं। जब गंगा नदी पर स्नान या मेला लगता है तो यह पूरी रोड जाम हो जाती है। इसलिए आपके माध्यम से, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए, इसे कम से कम फोर-लेन कर दिया जाए, जिससे वहां विकास हो सकेगा और स्थानीय जन समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर – उपस्थित नहीं।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): सर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

सर, यह ऐसी बात है कि सभी लोग, भारत के सभी सिटिजन्स इसका सपोर्ट करेंगे। भारत में फुटबाल की नेशनल टीम हैं – मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्डन स्पोर्टिंग। इंग्लिश पीरियड में, 1922 में कोलकाता में एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ट्रेन बन्द कर देते थे, उसका सब कुछ काम बन्द कर देते थे। वहां से शुरू होकर, जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद अभी एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक उसे बन्द रखना होता है।

(1210/IND/SPR)

मेरी आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, लेकिन अब हम स्वाधीन हो गए हैं। मैं उधर बैठे अपने सभी भाई लोगों से विनती करता हूँ कि उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए कि जैसा इंग्लिश पीरियड में होता था, वैसा अभी भी क्यों हो रहा है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I am associating with the sentiments expressed by the hon. Member.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी और श्री कुलदीप राय शर्मा श्री प्रसून बनर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the Jawaharlal Nehru University was established in 1969. It is one of the most important and premier institutions of our country. It is considered to be a centre of excellence. For the last many months, there has been an organised conspiracy on from the part of the administrators itself to destroy this university.

Relating to the fees hike, there has been constant strikes and agitations from various student organisations. On 5th January, 2020, a number of people from outside came and attacked the students and student leaders of the university. At the same time, there were many people who were beaten outside the university. This is an organised crime with the help of the Vice Chancellor, this is an organised crime with the help of the security staff, and the Delhi Police, who was inside the campus, stayed away from all this. So, an independent inquiry should be ordered to look into this matter. Till now, not a single person has been arrested in this particular issue. None of the bodies in the university, including the Academic Council, the Board of Studies has been discussed it. Sir, removal of Vice Chancellor is very important. Necessary steps should be taken in this regard. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी उलाका, श्री राजन बाबूराव विचारे, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती के. कनिमोझी, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री हिबी इडन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, I am raising a very important and urgent matter, through you. Kerala has been excluded – hon. Finance Minister is here - and denied additional financial assistance from the National Disaster Relief Fund even when the Central Government released funds worth Rs 5,908 crores to seven flood-hit states. It is pertinent to note that Kerala, which was affected severely by two back to back floods in 2018 and 2019, was excluded despite the severity of the damages being very well known to the Union Government. Such discriminatory practices are liable to affect the Centre-State harmony. I urge upon the Union Government to reconsider the request of Kerala and release a special relief assistance package to it at the earliest.

Sir, the United Nations in its Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) Report cited the losses to be to the tune of Rs.31,000 crore in various sectors in Kerala. For example, in construction of houses sector, the loss is to the tune of Rs.5,443 crore; in the health sector, it was Rs.600 crore; in the education and child protection sector, it was Rs.214 crore; in the culture and heritage sector, it was Rs.80 crore.....

माननीय अध्यक्ष : आप बजट पर चर्चा के समय पूरी बात रखिएगा। अभी शून्य काल चल रहा है।
...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): In agriculture, fisheries and animal husbandry sector, the loss was to the tune of Rs.4,498 crore. These are the figures given in the Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) Report.

माननीय अध्यक्ष : अभी आप पूरे आंकड़े मत पढ़िए।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the Central Government is adopting step-motherly attitude towards Kerala. It is not good. Hon. Finance Minister is here. Everybody knows that Kerala has incurred huge losses. Hence, I would request the hon. Finance Minister to immediately announce a special assistance package to Kerala. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती के. कनिमोजी, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री के. सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूँ। राजस्थान प्रांत के सीकर जिले के कांवट कस्बे में 14 साल की मासूम बच्ची के साथ

बहुत जघन्य कांड हुआ है। 27 तारीख को कुछ दरिंदे उस बेटी को बहला-फुसला कर एक तरफ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। जब वह चिल्लाई, तो उन्होंने उसका गला घोट कर मार दिया। 27 तारीख को यह कांड हुआ, लेकिन 31 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके छोटे भाई को बुलाकर थाने में बैठा लिया गया। अभी भी दोषी लोग खुले घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्रीमती के. कनिमोज्जी को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। (1215/UB/ASA)

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Hon. Speaker, Sir, my subject is related to the upgradation of the national highway in Telangana State. In Hyderabad, from the junction of ORR at Gowrelly to Kothagudem junction via Valigonda, Thorrur, Nellikduru, Mahabubabad, Yellandu, about 100 km stretch of this road comes under my constituency. माननीय गडकरी जी से निवेदन है कि तेलंगाना के वास्ते अच्छा नेशनल रोड कंवर्ट करें। इस रोड को नोटिफाइ करें मगर उसको नम्बर नहीं देने की वजह से चार साल से राज्य सरकार भी मेनटेन नहीं कर रही है। उसमें पैसे रुक गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि please allot the number to the highway and give the funds as early as possible. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत खतरनाक और लाइलाज बीमारी सिकल सेल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सिकल सेल विकृति एक जेनेटिक रोग है। विश्व के पांच प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस रोग में गोलाकार लाल रक्त कण (हीमोग्लोबिन) हंसिए के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं। ये रक्त कण शरीर की छोटी रक्तवाहिनी में फंसकर लिवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। रक्त कणों के जल्दी-जल्दी टूटने से रोगी को सदैव रक्त की कमी (एनीमिया) रहती है।

महाराष्ट्र में पाए जाने वाले इस रोग के कुल मरीजों में से 20 प्रतिशत मरीज चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल जिलों में हैं।

सर्वे के अनुसार यहां पिछड़े, वंचित और आदिवासी लोगों में यह बीमारी 10 से 40 प्रतिशत तक व्याप्त है। इस रोग में आरबीसी जल्दी नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है और मरीज को बार बार खून चढ़वाना पड़ता है। चन्द्रपुर में स्थित संस्थान में ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, इस कारण उसके लिए मरीजों को बार बार नागपुर जाना पड़ता है। सिकल सेल पीड़ित मरीज के गर्भ में पल रहे बच्चे की जन्म से पूर्व जांच करने के लिए अभी तक गर्भजल परीक्षण और कोरियोनिक विल्लस सेम्पलिंग नामक जांच प्रारंभ नहीं की जा सकी है, इसके

लिए भी मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। इन तीनों जिलों का एरिया बहुत फैला हुआ है और इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए केवल जिला स्तर तक ही उपलब्ध है। सिकल सेल नियंत्रण का कार्य गांव-गांव के प्राथमिक केन्द्रों तक नहीं पहुंच पाया है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब जो भी माननीय सदस्य शून्यकाल में पढ़कर बोलेगा, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या सदन इस बात के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : बिल्कुल सर।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि मिथिला की बेटी जगत जननी जगदंबा मां सीता के प्रति परमेश्वर भगवान श्रीराम के जन्मस्थली अयोध्या में दिव्य व भव्य मंदिर निर्माण को ट्रस्ट बनाने के लिए उनके ससुराल मिथिलावासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका यह विषय नहीं है। आप अपने विषय पर बोलें।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख फसल है, जिसकी उपज सिर्फ मिथिला क्षेत्र में होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन एवं कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जिसकी महत्ता को देखते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 28 फरवरी 2002 को मिथिला में केन्द्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर इसे केवल मखाना अनुसंधान केन्द्र बना दिया था जिसके कारण इसमें निदेशक का पद और मिलने वाला फंड पूर्णतया समाप्त हो गया जिससे यह केन्द्र पूरी तरह से पंगु हो गया।

पग-पग पोखर माघ मखाना के लिए प्रसिद्ध मिथिला जैसे जल ही जल वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन क्षेत्र केवल 15000 हेक्टेअर दिखाया गया जबकि इसके लिए उपयोगी क्षेत्र 9.5 लाख हेक्टेअर से अधिक है। जिसमें कमल का फूल, मछली, मखाना और सिंघाड़ा की खेती प्रचुर मात्रा में होती है।

(1220/KMR/RAJ)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस संस्थान को राष्ट्रीय केन्द्र का दर्जा मिले। दूसरा, इसके मुख्य संवर्द्धन, कीट विज्ञान, एवं पौधा संबंधित वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाए। तीसरा, मखाना के लिए उन्नत प्रयोगशाला खोल कर इसमें निदेशक नियुक्त किए जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल को श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Speaker, Sir, we all remember the historic Vellore Sepoy Mutiny that originated in Vellore District which led to the freedom struggle in India. Vellore Parliamentary Constituency sends more than 40,000 persons to our prestigious Navy, Army and Air Force. Moreover, about 25,000 to 30,000 military families are residing in Vellore Constituency. For more than 25 years, this House has heard the voices from my Constituency requesting for a Kendriya Vidyalaya for those military families. Therefore, I request this august House to sanction a Kendriya Vidyalaya to my Parliamentary Constituency.

In 2010, the then Deputy Commander Maj. Thamburaj requested the Tamil Nadu Government to allot land to build a Kendriya Vidyalaya. The then Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi sanctioned that land in 2011. But till today the land has not been put to use. I request this august House to put in a word to the Government of India to sanction a Kendriya Vidyalaya in my Constituency and show patronage to our military families. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डी.एम. कथीर आनंद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I would request you to even direct the Government to take up work in connection with development, renovation and beautification of river Ganga in Kolkata. In addition, a statue of Swami Vivekananda, who is worshipped by all Members of this House, can be set up in the city of Kolkata near his residence. I have seen that Varanasi is going to be developed in a big way by spending thousands of crores of rupees. A statue of Sardar Vallabh Bhai Patel has been set up by spending more than Rs.3000 crore. So, why can a statue of Swami Vivekananda be not set up by spending at least Rs.100 crore?

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वाराणसी में गंगा डेवलपमेंट की तरह हमारे कोलकाता में भी गंगा के ब्यूटिफिकेशन के लिए जरूर आगे कदम बढ़ाए और इसके लिए कम से कम वाराणसी गंगा डेवलपमेंट का वन टेन्थ बजटरी एलोकेशन करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Mr Speaker, at the outset, allow me to congratulate the hon. Finance Minister on increasing the allocation for Education by Rs.4,460 crore to Rs.99,300 crore. This increase in

budget allocation for Education is a commendable step. It will address the needs and aspirations of India's youth and will ensure that India can take advantage of its young demographic dividend.

The Andhra Pradesh Government, under Jagan Mohan Reddy Garu, has laid great emphasis on education. Among the important schemes it has initiated are 'Amma Vodi' and 'Nadu-Nedu' programmes.

Sir, under Amma Vodi scheme, below poverty line women with school-going children get direct financial assistance of Rs.15,000 annually. The money is deposited every January into every mother's account. This time, we have deposited money into accounts of almost 43 lakh mothers.

Further, under 'Nadu-Nedu' programme, 15,000 schools in the first phase will be upgraded in every aspect. Basic amenities like clean environment, furniture, toilets, running water, compound wall, blackboards etc., will be provided. Apart from providing for infrastructure, skills will also be upgraded. The Andhra Pradesh Government has allocated Rs.12,000 crore for this programme. Sir, these initiatives seek to raise the quality of education and equip students to compete with their peers across the nation.

Even the Economic Survey 2019-2020 pointed out that due to the absence of a suitable financial support system and high burden of course fee, the poor are pushed out of the education system. The survey also cited that the largest expenditure incurred was on tuition and examination.

(1225/SNT/VB)

Mr. Speaker, Sir, we all know that the Right to Education Act was passed long back. I request, through you, Sir, the HRD Minister to partly bear the cost of Amma Vodi Scheme and Nadu-Nedu Programme as it will increase the enrolment ratio and it will be in line with the New Education Policy.

...(Interruptions)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष जो समस्या रखने जा रहा हूँ, वह केवल मेरे लोक सभा क्षेत्र की ही नहीं है, बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलों की है। यह 154 गाँवों के लाखों लोगों और पशुओं की समस्या है।

यहाँ बहने वाली काली नदी में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इसके तट पर स्थित गाँवों में सैकड़ों लोगों को कैंसर तथा अन्य गम्भीर रोगों से मृत्यु हो चुकी है। नदी की खराब पानी की वजह से भूमि का जल भी दूषित हो गया है, जिससे लोगों को टी.बी., पीलिया, हिपेटाइटिस-बी आदि बीमारियाँ हो रही हैं।

हमारी सरकार ने काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 'नमामि गंगे' योजना के अंतर्गत 682 करोड़ रुपये स्वीकृत की है। परन्तु, कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। गंगा को निर्मल करने के लिए उसकी सहायक नदियों, जिनमें काली नदी भी शामिल है, को निर्मल करना भी बहुत आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन शीघ्र करे। इसके साथ ही आर्द्र भूमि (वेट लैंड), जो अतिक्रमण के कारण नष्ट हो गई है, को दुबारा रिस्टोर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री मलूक नागर को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Speaker Sir, we are discussing in our country on how to tackle the Corona virus. An administrative failure in the medical department is taking away several lives more than that was due to effect of Corona virus. The Centre for Calibration and Testing Medical Equipment of the Anna University has submitted a report recently. The Report says that while testing as many as 12000 medical devices in 250 hospitals of Tamil Nadu, it was found that all those devices were not properly calibrated. This is a shocking revelation for everyone. Because of non-calibration of medical devices several precious lives are being lost. Our Government has ordered for monitoring only 23 types of medical devices. All other devices are not monitored. NITI Aayog has given already a recommendation for setting up a separate body to look after calibration of medical devices. But that recommendation is still pending for implementation. I urge that the recommendation of NITI Aayog should be implemented. I request that the Union Government should set up a Commission to look into the aspect of loss of lives due to non-calibration of medical devices. Thank you, Vanakkam.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री डी. रविकुमार द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak.

I would like to draw the attention of the Government to a very important proposal which relates to the Railway Ministry. My constituency Uluberia has a glorious past of culture and literature. The great Bengali novelist Sarat Chandra

Chattopadhyay made his house in Samta Village in 1923. It is in Bagnan-II Block in my constituency. The house is now famously known as Sarat Chandra Kuthi. His *samadhi* is also within the compound. A lot of tourists visit the place every day.

As we know, the great novelist had made around 50 films in different Indian languages. The famous film Devadas is among those. Deulti railway station of the South-Eastern Railway is the nearest station to reach Sarat Chandra Kuthi.

On behalf of the people of my constituency and fans of Sarat Chandra Chattopadhyay, I would like to urge the Government to rename Deulti Station as Sarat Chandra Station as well as develop the station considering the importance of tourist attraction in that area.

Thank you, Sir.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आपने कहा था कि क्वेश्चन आवर के बाद प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई होगी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैंने शून्यकाल शुरू किया हुआ है। Please, no.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्यकाल महत्वपूर्ण है। आप कृपया बैठ जाइए। आपकी पार्टी के बहुत-से माननीय सदस्यों का आग्रह था कि उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर बोलना है। इसलिए मैंने इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

(1230/GM/PC)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) मैं सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अहमदनगर से पुणे तक प्रतिदिन शटल-रेल सेवा प्रारंभ करने के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्यकाल, महत्वपूर्ण काल है। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The House should not be taken for granted by the Prime Minister. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आपके माननीय सदस्यों का आग्रह था कि उन्हें महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है, इसलिए मैंने उन्हें इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, अहमदनगर से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री पुणे तक की यात्रा शैक्षणिक, पर्यटन और उद्योग के उद्देश्य से करते हैं। ...(व्यवधान) इसके लिए उन्हें चार से पांच घंटे की अवधि लगती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, आपने कहा था कि आपका शून्यकाल में बोलना जरूरी है? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से वहां की जनता की मांग है कि इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच एक इंटरसिटी ट्रेन या शटल-रेल सेवा प्रतिदिन शुरू की जाए। ...(व्यवधान)

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रेल मंत्रालय तत्काल इस पर विचार करे और अहमदनगर और पुणे जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन या शटल-रेल सेवा की शुरुआत करे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, this is called 'Waiting for Godot'! ...(Interruptions)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to bring an important issue to the notice of the House. Everyone here would agree that the States are going to the maximum extent to bring in foreign investment and to improve the domestic investment so that these investments provide employment opportunities to the youth and also help in the economic development of the State. This will be the situation wherever you go in the country. Following the same concept of the decentralized development, the previous Government of Andhra Pradesh under the leadership of Shri Chandrababu Naidu constructed Millennium Towers in Visakhapatnam to improve IT sector in Visakhapatnam. He also brought in investment by Kia Motors in Anantapur, which is also a backward region in Andhra Pradesh. But unfortunately, the present Government of Andhra Pradesh issued a notice to the company's office in Millennium Towers and told them to vacate their premises by 30th of March, 2020. This is a big jolt to the IT companies providing services from the soil of Andhra Pradesh, and also to those companies which are willing to set up their facilities in the State of Andhra Pradesh. ...(Interruptions) Sir,

18,000 people are working in the building and they will be forced to vacate. The previous Government had spent a huge amount to bring in this investment. All those investments are being forced out of the State and the employment opportunities of the youth are being curtailed. ...(*Interruptions*) There is another example also. Whatever I am saying is hard facts. It has been reported in the newspapers also. I am not making any false allegations. These are real facts that I am going to mention. Kia Motors, which has brought a big investment for the State of Andhra Pradesh worth 1.1 billion US dollars, is now being forced out of the State. The company which was brought in by the previous Government has moved its ancillary unit to the other State and now it is thinking to move its main unit also to the neighbouring State. What will happen to our State if the present Government adopts such kind of policies? I request the Central Government to interfere. Such kind of policy should always be questioned by the Central Government. The Central Government should also take responsibility. These are international investments that we are talking about. This is the respect of the country that we are talking about. ...(*Interruptions*) What is this? Can we speak in the House or not? ...(*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, he is misleading the House. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैं आपको मौका दूंगा।

...(*व्यवधान*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Speaker, Sir, we have every right to speak here. We have also come as Parliamentarians only to speak here. Every time we say something, they are all objecting. Please give them an opportunity if they have something else to say. Why are they disturbing us? I am saying these investments are being forced out. Visakhapatnam and Anantapur have been important regions of development for the State of Andhra Pradesh. The previous Government had set up full-fledged facilities to improve the employment opportunities. Now, they are forcing them out of our State.

माननीय अध्यक्ष: श्री श्याम सिंह यादव, श्री गिरीश चन्द्र एवं श्री मल्लूक नागर को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मिधुन रेड्डी जी, आप बोलिए।

...(*व्यवधान*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Speaker, Sir, I want to bring two things to the notice of the House. There is a report in the media which says that Kia Motors is pulling out. This is utterly rubbish. I spoke to the MD of Kia Motors today

morning and they are giving a clarification. This is a false news being circulated in the media and it was not given by the company. I spoke to the MD in the morning and he clearly told me that they are issuing a statement contradicting whatever has come out in the media.

As for Millennium Towers mentioned by him, I want to bring to the notice of the House that there is a company called Franklin Templeton. They have created this dummy company and they have given it land worth thousands of crores of rupees for an investment of Rs. 30 crore.

(1235/RK/SPS)

It is a big scam. We have questioned them too. How can they give Rs.1000 crore worth land for a mere investment of Rs.30 crore? They are on a mission; 'Save Chandrababu Naidu. Save him from scams.'. That is their basic motive. They are not going to talk anything substantive. They are only circulating baseless issues. I would like to say that they should speak some substance when they speak on the floor of the House. We oppose this. We strongly oppose any false claim and we would request you to expunge it from the record....(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, we should be told at what time the Prime Minister will be available in the House....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। विपक्ष के नेताजी, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon. Speaker, Sir, in Puducherry there is a place called Karaikal. The farmers of Karaikal district are affected because the procurement of their produce has not taken place....(*Interruptions*) There is a huge harvest of paddy in Karaikal but there is no procurement centre of the FCI and because of that the farmers are affected. They are not getting the MSP for their produce....(*Interruptions*)

I would request the hon. Minister to arrange for procuring paddy from Karaikal farmers.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: इस सदन के फ्लोर नेता माननीय अधीर रंजन जी ने कहा है कि अविलम्ब लोक मत के विषय को बंद कर दीजिए। इसलिए आज इस विषय को स्थगित किया जाता है।

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नियम 377 के अधीन सभी मामले सभा पटल पर रखे जाएं।

**Re: Need to construct a bigger underpass near level crossing
No. 87C 2E between Chilibila and Jagesharganj railway stations in
Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh**

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) अंतर्गत वाराणसी से लखनऊ जाने वाली रेल लाइन पर चिलबिला रेलवे स्टेशन से आगे जगेशरगंज रेलवे स्टेशन से पहले लेवल क्रॉसिंग संख्या 87C2E के सन्निकट स्थित रेलवे अंडरपास, जो आज़ादी के पहले का बना पुराना अंडरपास है, के मध्य से ही ग्राम सभा संग्रामपुर और हुडहा के बीच आने जाने का एकमात्र मार्ग है और इसी रास्ते से होकर प्रतिदिन कई दर्जन गाँव के लोग दैनिक कार्यों हेतु आते जाते हैं किंतु अंडरपास अत्यंत पुराना व संकरा होने के कारण लोग उसके निकट स्थित रेलवे लाइन को जान जोखिम में डालकर पार करते हैं जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं साथ ही साथ उस मार्ग से होकर कोई बड़ा वाहन न जा सकने के कारण निर्माण सामग्री आदि लेकर जाने वाले बड़े वाहन चोरी चुपके अंडरपास के उपर सीधे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं जिसके कारण किसी दिन बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है इसी के साथ यह अवगत कराना है कि उक्त क्रॉसिंग के पार एक नवीन आईटीआई निर्माण का प्रस्तावित स्थल भी है जिसमें आवागमन का सुचारु रास्ता न होने के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा अनुरोध किए जाने पर रेलवे के तकनीकी अधिकारियों द्वारा असली निरीक्षण भी किया गया तथा उक्त स्थल पर रेलवे अंडरपास को बड़ा कर बनाए जाने हेतु अपनी संस्तुति भी मंत्रालय को प्रेषित की गयी किन्तु 8 माह से प्रकरण लंबित पड़ा है अतः निवेदन है कि वाराणसी-लखनऊ रेल मार्ग के चिलबिला जंक्शन से जगेशरगंज के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 87C2E सन्निकट संग्रामपुर हुडहा गाँव के बीच स्थित पुराने छोटे अंडरपास के स्थान पर तत्काल बड़ा अंडरपास का निर्माण रेल मंत्रालय से कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up an Integrated Textile Park in Bankura and Purulia districts of West Bengal

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Bankura and Purulia districts have a long history of producing both exotic and mass handloom textile products. More than lakh people of the region are directly or indirectly dependent on this industry. However, the industry is suffering from many problems including lack of innovation, improvement of skill set, machineries, investment, marketing infrastructure and urgently need initiative from the Government for its sustenance and growth.

Considering the presence of large existing weaving community, low cost of labour and vast untapped potential, an Integrated Textile Park can resolve the issues limiting the growth of the sector and will enhance the economic condition of the people of the districts and also that of adjacent state of Jharkhand. My humble request to the Hon'ble Minister of Textiles is to consider creating the Textile Park under SITP in Bankura District to bring back the growth of the sector in the entire Jangal Mahal area.

(ends)

(PP 302-303)**Re: Need to set up Jute textile cluster in Coochbehar, West Bengal**

SHRI NISITH PRAMANIK (COOCHBEHAR): I am thankful to Hon'ble Speaker for providing me the opportunity to speak in the House on one of the important concerns for the people of Coochbehar, that is Jute industry and its production. Basically for the people of Coochbehar their common livelihood is jute fibre production for textile industry and various small scale industries. Climatic conditions favour the production of jute crops in these areas. Low cost investment, availability of labour at low cost make this crop production feasible in the area. But as we are aware, the life of jute farmers has become miserable. If things can be revived positively and keeping in mind about the development of the small farmers then Jute production can flourish in Coochbehar, West Bengal.

As per the budget provisions, small textile cluster has been under National Textile Mission, so through you I would demand and request the Government to open one Jute textile cluster in Coochbehar. Through this, thousands of people will get job.

(ends)

Re: Rail connectivity for Kannur International Airport in Kerala

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): A railway line connecting the Kannur International Airport at Mattannoor and Kannur railway station is crucial for the economy and development of North Malabar region. At present, there are a large number of passengers travelling from faraway places in the Malabar region to reach Kannur airport by means of public transport. In this regard, the Union Railway Budget in 2016, had allocated Rs.400 crore. The allocation was made under Extra Budgetary Resources (EBR) partnership mode through formation of a Special Purpose Vehicle. However, in response to my question, the Hon'ble Railway Minister had informed the house on 20/11/2019 that no proposal has been received for the same. Also, it is the need of the hour for setting up a railway ticketing counter at Kannur International Airport considering the significant rise in the number of passengers who choose rail journey to and from Kannur Airport.

(ends)

Re: Need to accord priority to local youths in recruitment in NMDC plant in Bastar and Dantewada districts of Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर) : दंतेवाड़ा-बस्तर जिले में एनएमडीसी प्लांट है, इस संयंत्र में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए समय-समय पर आवेदन ऑल इंडिया स्तर पर अभ्यर्थियों से मंगाया जाता है, भर्ती का केन्द्रीय मुख्यालय हैदराबाद रखा जाता है। बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय युवकों को रोजगार में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। स्थानीय युवकों की नियुक्तियों के लिए अलग प्रावधान नहीं है। जिसके कारण स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चूंकि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसके कारण स्थानीय युवकों का शिक्षा स्तर प्रभावित होता है, इसलिए वे उन अभ्यर्थियों के समकक्ष भर्ती परीक्षाओं में वांछित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं पर प्रतिभा के मामले में स्थानीय युवक किंचित कमतर नहीं हैं।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि दंतेवाड़ा-बस्तर जिले में एनएमडीसी प्लांट में कुछ पदों पर स्थानीय युवकों की नियुक्ति हेतु अलग प्रावधान करे या कुछ पदों को सिर्फ स्थानीय युवकों से भरने का प्रावधान किया जाए जिससे स्थानीय युवकों को नियुक्ति में प्राथमिकता मिल सके।

(इति)

Re: Revision of pension of BSNL employees

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): The BSNL management has approved the revised pay scales after an agreement with all recognized union, recommended by the PRC for the executives and non-executives. The Hon'ble Minister for Communications has also made a statement that pension revision of BSNL absorbed retirees is linked to pay revision but at the same time he pointed out that as wage revision is not possible due to the poor financial condition of BSNL, no proposal has been initiated by the Ministry for pension revision till date. The following points may be brought to the notice of the Ministry:

- (a) Pay revision and pension revision are given once in 10 years. Both Central Government pensioners and BSNL absorbed pensioners are covered under the same CCS (Pension) Rules, 1972. The Central govt. pensioners have already got the revised pension from 01.01.2016.
- (b) pension revision is no way connected to affordability conditions of BSNL as the entire liability lies with the Government as per provisions of the Rule 37A CCS (Pension) Rules 1972.
- (c) Levying of pension contributions on the basis of the maximum of pay scales from BSNL is costing it dearly. Such PSUs implementing govt. projects are exempted from the affordability conditions by the 3 PRC itself and included in the DPE guidelines. Therefore, BSNL is a fitting case for relaxation of affordability conditions as pointed out by the former CMD, BSNL. So BSNL employees cannot be denied the wage revision, particularly in the post VRS scenario.

Therefore, I urge upon the Union Government for an early action to revise the pension/family pension with 15% fitment based on pay scales approved by the BSNL management from 01.01.2017, delinking wage revision.

(ends)

Re: Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Anakapalle in Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): One Kendriya Vidyalaya was sanctioned for Anakapalle of Visakhapatnam district in Andhra Pradesh which is headquarters of my Parliamentary Constituency in the year 2017 but the institution has not been established so far. Anakapalle town consists of urban and semi-urban Jurisdiction, with large number of Government elementary, secondary schools and public Sector Organisations and many Pharma companies exist in and around Anakapalle Town. Due to non-functioning of Kendriya Vidyalaya at Anakapalle, the neighbouring students are relocating from their villages to Vishakhapatnam and nearby places for their education. There is a dire need of institution like Kendriya Vidyalaya, which is a prestigious institution, which provides merit students to the Nation.

Hence, keeping in view of the necessity and in the interest of the public, I earnestly request you to commence functioning of Kendriya Vidyalaya at Anakapalle from the ensuing academic Year 2020-2021.

(ends)

Re: Need to provide two separate coaches in trains for differently-abled persons

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I want to raise the issue of Divyangjans in this august House relating to the problems they are facing in Trains.

Sir, as we are aware that mostly trains are having stoppage for 2-3 minutes and differently abled persons have to board the train within that time. But sometimes the location of Disabled Coach is a hurdle. There are many trains which are not having disabled-friendly coaches which causes severe problems to differently-abled persons.

Sometimes it has also come to notice that persons with disabilities missed the train as the reserved compartment of train was locked from inside. I request the Hon'ble Minister to provide two separate coaches in all trains, one at front side and another at rear side for the convenience of differently-abled persons so that they could get equal opportunity to travel by train.

(ends)

Re: Need to constitute a committee to look into various issues of small savings agents in the country

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, देश भर में लगभग ५ लाख नेशनल स्मॉल सेविंग ऐजेंट्स काम कर रहे हैं। इसमें 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। ये स्माल सेविंग ऐजेंट्स नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश हेतु वित्त मंत्रालय के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन ऐजेंट्स को अपना कार्य करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, काँग्रेस सरकार के समय में इन ऐजेंट्स के पी पी एफ स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाले कमीशन को बंद कर दिया गया, इसके अतिरिक्त काँग्रेस शासन काल में ही श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने बिना कोई फील्ड वेरिफिकेशन और स्टडी के अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी जबकि इस समिति ने कभी भी इन ऐजेंट्स से कोई सलाह मशविरा नहीं किया और न ही इनके साथ कोई बैठक की। रिपोर्ट में इन स्मॉल सेविंग ऐजेंट्स की मेहनत और देश की आर्थिक वृद्धि में इनके योगदान की पहचान नहीं की गई। रिपोर्ट के आधार पर ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की जाने वाली बचत के ऐजेंट का कार्य इनसे छीन लिया गया और समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सुकन्या योजना में भी इन ऐजेंट्स को बाहर रखा गया है। ये पुरुष और महिला ऐजेंट्स पिछले ३० - ४० साल से स्माल सेविंग ऐजेंट्स के रूप में कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जबकि अब कमीशन को कम किए जाने से इन ऐजेंट्स को इस समय में अपने जीवन यापन के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन स्माल सेविंग ऐजेंट्स के हितों की रक्षा हेतु नयी समिति का गठन करे जिसमें वित्त विभाग, डाक विभाग, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट और नेशनल सेविंग ऐजेंट्स असोशिएशन के सदस्य शामिल हों।

(इति)

Re: Need to expedite establishment of railway wagon manufacturing factory in Ganjam district of Odisha

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): It is a matter of grave concern that the Ministry of Railways had sanctioned the establishment of Wagon manufacturing factory at SITALAPALLI in GANJAM District of ODISHA in the year 2011-12 but so far, no progress has been made in that connection. Government of Odisha has identified and alienated over 100 acres of land for this project for Railways and had also requested to change it to Coach manufacturing factory that too if the Wagon requirement is less.

The Government of Odisha was highly hopeful as this would be a major source of employment for the locals and mostly the youth would benefit a lot. Besides, this factory would lead to establish many ancillary business outlets providing secondary employment and subsidiary business in different ways to thousands of locals.

The astonishing fact is that the project which was sanctioned in the year 2011-12 for Ganjam district has not commenced a bit but the Railway Ministry has announced a new Coach factory in Maharashtra. Sir, I have nothing against it but my heart pains when you have not bothered to make any progress on a project sanctioned almost 10 years ago and now you announce to establish a new factory in a different State without caring for the earlier project.

Sir, I would earnestly request the Hon'ble Railway Minister and the Hon'ble Prime Minister to please expedite the establishment of Railway factory at Ganjam District of Odisha at the earliest.

(ends)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

माननीय अध्यक्ष: अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार को आगे जारी करते हैं।

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):

* Laid on the Table

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA):

*Laid on the Table

***श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल):**

* Laid on the Table

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):

*Laid on the Table.

*SHRI DIPSINH SHANKARSINH RATHOD (SABARKANTHA):

*Laid on the Table

*SHRI VINOD LAKHAMSHI CHAVDA (KACHCHH):

*Laid on the Table.

***श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा):**

* Laid on the Table

*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN):

*Laid on the Table

***श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली)**

* Laid on the Table

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):

* Laid on the Table

***श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):**

* Laid on the Table

***श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) (आनंद):**

* Laid on the Table

***SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR):**

***Laid on the Table**

*SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon'ble Speaker Sir, Karaikal is a part of Puducherry and the farmers are having a good harvest of paddy. There is no procurement centre of FCI in Karaikal, Puducherry. So, the purchase of paddy by the traders is below the MSP. MSP price of paddy is Rs.1850/- per quintal. But traders are buying the paddy at Rs.1500/- per quintal. So, farmers are affected very much and they are incurring losses.

So, I request the Government to set up a purchase centre by FCI. Then only the farmers will get MSP for their paddy.

(ends)

*DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):

*Laid on the Table.

***श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी):**

* Laid on the Table

1238 बजे

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 12 – माननीय प्रधानमंत्री जी।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! ...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): बस इतना ही।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मोदी जी यह तो एक ट्रेलर हैं, बाकी अभी बाकी है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी हैं।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गोगोई जी और अन्य माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, यह इलेक्शन स्पीच तो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप बैठ जाइए।

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

(1240/MM/PS)

माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का माननीय राष्ट्रपति जी का यह वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि-कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला यह अभिभाषण है। इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी-अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने-अपने विचार रखे हैं। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है।

श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, प्रो. सौगत राय जी, डॉ. शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, राम कृपाल यादव जी, पी.पी. चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक राऊत जी और भी कई नाम हैं। मैं सभी के नाम लूंगा तो शायद समय बहुत लग जाएगा। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हर एक ने अपने-अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक स्वर यह उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है? सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं? ऐसा भाव भी लोगों की बातों में से आता है। मैं शुरूआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्धृत करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी प्रेरणा के कारण हम लीक से हटकर के तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता में लिखा है-

“लीक पर वे चलें, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं,
जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं।
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने,
ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं।”

माननीय अध्यक्ष जी, लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है, ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की इस देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते, जिस तरीके से आप लोग चलते थे। उसी रास्ते से चलते, जिस रास्ते की आपको आदत हो गयी थी तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं हटता।

(1245/SJN/RC)

आप ही के तौर-तरीकों से चलते, तो आज भी मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की तलवार डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते, तो नाबालिगों से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बन पाता। अगर आप ही की सोच के साथ चलते, तो राम जन्मभूमी आज भी विवादों में रहती... (व्यवधान) अगर आप ही की सोच होती, तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता, तो भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझ पाता... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : यह बांग्लादेश हम लोगों ने बनाया है, गांधी जी ने बनाया है... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, उनको सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरेन रिजीजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, अधीर जी उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार-प्रसार बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं... (व्यवधान) ये भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ-साथ जिम भी करते हैं... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : लेकिन आपकी तरह ढोंगी आसन नहीं करते हैं, असली आसन करते हैं... (व्यवधान) एडवरटाइजमेन्ट का आसन नहीं करते हैं। हम दिखावे का आसन नहीं करते हैं... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : फिट इंडिया मूवमेंट को बल देने के लिए, उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इंकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी-कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों का चुनने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के प्रति जो अपेक्षा है, अगर हम चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम

हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर आगे चलने की गति नहीं बढ़ाते, तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अर्से तक जूझना पड़ता।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम कांग्रेस के रास्ते चलते, तो 50 सालों के बाद भी देश को शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार करते रहना पड़ता। देश को 35 सालों के बाद भी नेक्स्ट जेनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार करते रहना पड़ता। 28 सालों के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं हो पाता। 20 सालों के बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती।

(1250/GG/SRG)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज़ गति की वजह से और हमारा मकसद है, हम एक नई लकीर बना कर, लीक से हट कर चलना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को भली-भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश है कि स्पीड भी बढ़े और स्केल भी बढ़े। डिटरमिनेशन भी हो डेसीसिवनेस भी हो। सेंसिटीविटी भी हो और सॉल्युशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज़ गति से काम किया है, उस तेज़ गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने पांच साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर यह तेज़ गति नहीं होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज़ न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं होता। अगर तेज़ गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर गति तेज़ न होती तो दो करोड़ नए घर गरीबों के नहीं बनते। अगर तेज़ गति नहीं होती तो लंबे अर्से से अटकी हुई दिल्ली की 17 सौ से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की ज़िंदगियां जो अधर में लटकी हुई थीं, वह काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें अपने घर का हक भी मिल गया है।

अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ-ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ-ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य हो, इतनी सीटें नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वह क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ-ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखण्डता के साथ दूर-दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनके काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ वहां के एक-एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ, आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है। इसी के कारण नॉर्थ-ईस्ट में गत पांच वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जा कर खड़ी हो गई है। मंत्री नॉर्थ-ईस्ट में लगातार दौरा करते रहे हैं। रात-रात वहां रुकते रहे, छोटे-छोटे इलाकों में जाते रहे - टीयर-2 और टीयर-3 - कितने सालों से गए? लोगों से संवाद किया, विश्वास का वातावरण पैदा किया।

(1255/KN/RU)

विकास की जो आवश्यकताएँ होती हैं, जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुँचाने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया है और वह विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है, जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है।

यहाँ पर यह बोडो की चर्चा आई है और यह कहा गया कि यह कोई पहली बार हुआ है। हमने भी कभी यह नहीं कहा कि पहली बार हुआ है। हम तो यही कह रहे हैं कि प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक तराजू से लेखा-जोखा करके किया गया। जो भी किया गया, आधे-अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया, एक प्रकार से खाना-पूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पर तो हो गए थे, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन कागज पर किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। चार हजार से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए। अनेक प्रकार के एक्टोर्शन, पचासों प्रकार की बीमारियाँ समाज-जीवन को जो संकट में डाले, ऐसी होती चली गईं। इस बार जो समझौता हुआ है, वह एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आम्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएँ हैं। यह ठीक है कि हमारा ज़रा वह इको-सिस्टम नहीं है, ताकि हमारी बात बार-बार उजागर हो, फैले। लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है- सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं। सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोगों ने सरेंडर किया है और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी माँग बाकी नहीं रह गई है। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे, सूरज तो पहले उगता है, लेकिन सुबह नहीं आती थी। सूरज तो आ जाता था, अंधेरा नहीं छंटता था। आज मैं कह सकता हूँ कि नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है और वह प्रकाश जब आप अपने चश्मे बदलोगे, तब दिखाई देगा...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): जापान के प्रधान मंत्री...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ताकि बोलने के लिए बीच-बीच में मुझे आप विराम दे रहे हैं। कल यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गईं। आपने उसको रिकार्ड पर से निकाल दिया है, इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूँगा। लेकिन मुझे एक पुरानी छोटी-सी कथा याद आती है।

एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सब का अनुभव है। तो वहाँ बैठे हुए एक संत-महात्मा थे। उन्होंने कहा- देखो, पटरी में से कैसी आवाज आ रही है। यह निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है- 'प्रभु कर दे बेड़ापार'। बोले- देखो, यही आवाज आ रही है। सुनो, 'प्रभु कर दे बेड़ापार'। तो दूसरे संत ने कहा- नहीं यार, मैंने सुना। मुझे तो सुनाई दे रहा है- 'प्रभु तेरी लीला अपरम्पार'।

(1300/CS/NKL)

‘प्रभु तेरी लीला अपरम्पार’। वहाँ एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो दूसरा सुनाई दे रहा है। इन संतों ने कहा कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है कि ‘या अल्लाह तेरी रहमत’, ‘या अल्लाह तेरी रहमत’। वहाँ एक पहलवान बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी सुनाई दे रहा है। पहलवान ने कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है कि ‘खा रबड़ी कर कसरत’, ‘खा रबड़ी कर कसरत’।... (व्यवधान) कल जो विवेकानन्द जी के नाम से कहा गया, जैसी मन की रचना होती है, वैसा ही सुनाई देता है, वैसा ही दिखाई देता है।... (व्यवधान) आपको यह देखने के लिए इतनी दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, अपने लोगों को कहिए कि स्वामी जी से आपकी तुलना न करें... (व्यवधान) इसलिए मैंने कहा था कि वे जोगी थे, आप... (Not recorded) हो।... (व्यवधान) मैं अभी भी कह रहा हूँ... (व्यवधान) हम सब... (Not recorded) हैं।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, ये अनपार्लियामेन्टरी शब्द बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप अपने लोगों से कहिए कि स्वामी जी का अपमान न करें।... (व्यवधान) नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त थे।... (व्यवधान) योगी और... (Not recorded) की एक साथ तुलना न करें।... (व्यवधान) यह मैंने कहा था। मैंने यह भी कहा था कि “Each soul is potentially divine”. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

... (व्यवधान)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): इनको पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप जोड़ने की राजनीति कीजिए।... (व्यवधान) आप तोड़ने की राजनीति मत करो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : आपको पता है, क्या बोल रहे हो?... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं? ... (व्यवधान) इसमें कोई राज है।... (व्यवधान) सुरेश जी, कभी आपका भी मौका आएगा, इतनी जल्दी मत करो।... (व्यवधान)

महोदय, यहाँ किसानों के विषय में भी बातचीत हुई है। बहुत से महत्वपूर्ण काम बहुत नए तरीके से, नई सोच के साथ पिछले दिनों किए गए हैं और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र भी किया है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ चर्चा करने का प्रयास हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह अज्ञानवश है या जानबूझकर है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर जानकारियाँ होतीं तो शायद हम ऐसा न करते। हम जानते हैं कि 1.5 गुना एमएसपी करने वाला विषय कितने लंबे समय से अटका हुआ था। यह हमारे समय का नहीं था, पहले से था, लेकिन यह किसानों के प्रति हमारी

जिम्मेदारी थी कि उस काम को भी हमने पूरा कर दिया है। मैं हैरान हूँ, सिंचाई योजनाएं 80-90 परसेंट धन खर्च करके 20-20 साल से पड़ी हुई थीं, कोई पूछने वाला नहीं था। फोटो निकलवा दी, बस काम हो गया। हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा। एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके उनको उसके लॉजिकल एंड तक ले गए और अब किसानों को उसका फायदा होना शुरू हो गया है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना - इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस व्यवस्था से किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ है। किसानों की तरफ से करीब 13 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम आया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ, उसके तहत करीब 56 हजार करोड़ रुपये किसानों को बीमा योजना से प्राप्त हुए हैं।

(1305/RV/KSP)

किसान की आय बढ़े, यह हमारी प्राथमिकता है। इनपुट कॉस्ट कम हो, यह हमारी प्राथमिकता है। पहले एम.एस.पी. के नाम पर क्या होता था? हमारे देश में पहले 7 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद हुई, हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन हुई। 7 और 100 का फर्क तो समझ में आएगा।

'ई-नाम' (ई-एन.ए.एम.) योजना है। आज डिजिटल वर्ल्ड है। हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। 'ई-नाम' योजना के नाते किसान बाजार में अपने माल को बेच सके, उस योजना को हमने लिया और मुझे खुशी है कि गांव का किसान, इस व्यवस्था से करीब पौने दो करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं। किसानों ने अपनी पैदावार का करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपये का कारोबार इस 'ई-नाम' योजना से किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, उसके साथ-साथ एलाइड एक्टिविटीज हो, चाहे वह पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो, सोलर पम्प की बात हो, हमने ऐसी नई, अनेक चीजें जोड़ी हैं, जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है।

वर्ष 2014 में, हमारे आने से पहले, कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार करोड़ रुपये था। अब यह बढ़ कर पाँच गुना, पहले 27 हजार करोड़ रुपये था, अब बढ़ कर पाँच गुना लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक हमने इसे पहुंचाया है।

'पी.एम.-किसान सम्मान निधि' योजना में किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। अब तक करीब 45 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, फाइलों की कोई झंझट नहीं, बस एक क्लिक दबाया और पैसे पहुंच गए। लेकिन, मैं यहां माननीय सदस्यों से जरूर यह आग्रह करूंगा कि राजनीति करते रहिए, करनी भी चाहिए क्योंकि मैं आपकी तकलीफ जानता हूँ, लेकिन क्या हम राजनीति करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे? मैं उन माननीय सदस्यों से विशेष आग्रह करूंगा कि वे अपने राज्यों में देखें, जो किसानों के नाम पर बढ़-चढ़ कर बोल रहे हैं, वे जरा ज्यादा देखें कि क्या उनके राज्य के किसानों को 'पी.एम.-किसान सम्मान निधि' मिले, उसके लिए वे सरकारें किसानों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? इस योजना के

साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? इसमें नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? उस राज्य के किसानों का हुआ। यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा, जो दबी जुबान में, वे शायद खुल करके न बोल पाएं, क्योंकि कहीं जगह पर बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्हें पता होगा। उसी प्रकार से, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है कि आप जरा उन राज्यों में देखिए जहां किसानों से वादे कर-करके, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर-करके वोट बटोर लिए, शपथ ले लिए, सत्ता-सिंहासन पा लिया, लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किए गए। कम से कम यहां बैठे माननीय सदस्य उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे तो वे उन राज्यों से जरूर यह कहें कि किसानों को उनका हक देने में वे कोताही न बरतें।

माननीय अध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तब मैंने विस्तार से सबके सामने एक प्रार्थना भी की थी और अपने विचार भी रखे थे।

(1310/CP/KKD)

उसके बाद सदन के प्रारम्भ में जब मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि यह सत्र हम पूरी तरह अर्थ, आर्थिक विषय, देश की आर्थिक परिस्थितियां, इन सारे विषयों को इस सत्र में हम समर्पित करेंगे। हमारे पास जितनी भी चेतना है, जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी बुद्धि प्रतिभा है, सबका निचोड़ इस सत्र में दोनों सदनों में हम लेकर आए हैं। दुनिया की जो आज आर्थिक स्थिति है, उसका लाभ उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए, कौन सी दिशा को अपनाए, जिससे लाभ हो। मैं चाहूंगा कि यह सत्र, अभी भी समय है, ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे, तब भी पूरी शक्ति, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम आर्थिक विषयों पर गहराई से बोलें, व्यापकता से बोलें और अच्छे नये सुझावों के साथ बोलें, ताकि देश, विश्व के अंदर जो अवसर पैदा हुए, उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं सबको निमंत्रित भी करता हूं। मैं मानता हूं कि आर्थिक विषयों के इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस दायित्व बोध में पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम कहां हैं, उसका पता तब चलता है कि कल कहां था। यह बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह क्यों नहीं हुआ, यह कब होगा, यह कैसे होगा, कब तक करेंगे, यह जब सुनता हूं, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है, करेगा तो यही करेगा। इसलिए मैं आपकी इन बातों को आलोचना नहीं मानता हूं, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं और स्वीकार करने का प्रयास भी करता हूं। इसलिए इस प्रकार की जितनी बातें बताई गई हैं, इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये अच्छी बातें हैं, देश के लिए हम सोचते हैं, लेकिन पुरानी बातों के बिना आज की बात को समझना थोड़ा कठिन होता है।

हम जानते हैं कि पहले क्या काल खंड था। करप्शन, आए दिन चर्चा होती थी हर अखबार की हेडलाइन में, सदन में भी करप्शन पर ही लड़ाई चलती थी। सब जगह यही बोला जाता था। अनप्रोफेशनल बैंकिंग कौन भूल सकता है, कमजोर इनफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज कौन भूल सकता है

और संसाधनों की बंदरबांट, माई गॉड क्या करके रख दिया था? इन सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने की लाँग टर्म गोल के साथ एक निश्चित दिशा पकड़ करके, निश्चित लक्ष्य पकड़ करके उसको पूरा करने का लगातार प्रयास किया है। मुझे विश्वास है, उसी का परिणाम है कि आज इकॉनामी में फिसकल डेफीसिट बनी रही है, महंगाई नियंत्रित रही है और मैक्रोइकॉनामिक स्टेबिलिटी भी बनी रही है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बेरोजगारी पर भी बोलिए। ... (व्यवधान) हिंदुस्तान सुनना चाहता है कि बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? ... (व्यवधान) नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की बात कीजिए। ... (व्यवधान) नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की बात कीजिए। ... (व्यवधान) बेरोजगारी की बात कीजिए। ... (व्यवधान) सरकार का कुछ काम ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) हिंदुस्तान में बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है। यह भी काम हम ही करेंगे। ... (व्यवधान) हाँ, एक काम नहीं करेंगे। ... (व्यवधान) एक काम न करेंगे, न होने देंगे, वह है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। ... (व्यवधान)

(1315/NK/RP)

जीएसटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात हो, आईबीसी लाने की बात हो या एफडीआई रीजिम को लिब्रलाइज करने की बात हो। बैंकों को रि कैपिटलाइजेशन करने की बात हो, जो भी समय-समय आवश्यकता रही है, जो चीज दीर्घकालीन मजबूती की जरूरत हैं, वे सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और उसके लाभ भी आने शुरू हो गए हैं। वे रिफार्म्स जिसकी चर्चा हमेशा हुई है, आपके यहां जो पंडित लोग थे, वे हमेशा यही कहते रहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। अर्थशास्त्री भी जिन बातों की बातें करते थे, आज उसको एक के बाद एक लागू करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, उसको लेकर भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। जनवरी 2019 से 2020 के बीच छह बार जीएसटी रेवेन्यू का कलैक्शन एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। अगर एफडीआई की बात करूं, अप्रैल 2018 से सितम्बर 22 बिलियन डॉलर था, आज उसी अवधि में यह 26 बिलियन डॉलर पार कर गया है। इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर है, यह कन्विकशन बना है, तभी लोग गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, पेट खाली बजाओ ताली।

श्री नरेन्द्र मोदी: अध्यक्ष महोदय, हमारा विजन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्क्रीज वैल्यू एडिशन और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आपका रिपोर्ट कार्ड कहता है कि जॉब नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूँ। किसान बड़ी गर्मी में खेत जोतकर तैयार रखता है लेकिन उस समय बीज नहीं बोता है, सही समय पर बीज बोता है। अभी जो दस मिनट से चल रहा है, वह मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक-एक करके बीज डालूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं ने देश में स्वरोजगार योजनाओं को बहुत बड़ी ताकत दी है। इतना ही नहीं इस देश में करोड़ों लोग पहली बार मुद्रा योजना लेकर खुद रोजी-रोटी कमाने लगे। दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं पहली बार मुद्रा योजना के माध्यम से बैंकों से जिनको धन मिला है, उसमें 70 प्रतिशत माताएं व बहनें हैं।

(1320/SK/RCP)

जो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्षेत्र में नहीं थीं, वे आज कहीं न कहीं इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। 28,000 से ज्यादा स्टार्ट अप रिकोग्नाइज्ड हुए, आज खुशी की बात है कि टियर-2, टियर-3 सिटी में यानी हमारे देश के युवा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुद्रा योजना के तहत 22 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत हुए हैं और करोड़ों युवाओं ने खुद ने रोजगार को पाया है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): एनपीए के बारे में बताइए। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: अधीर रंजन जी, ऐसा करता हूँ, आप एक समय तय कीजिए, आपको जितना कहना है, मैं दोबारा बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे, अच्छा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मेरी प्रतिष्ठा के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी सैल्फ सफिशिएंट हूँ। ... (व्यवधान) लेकिन आप जो उलटी-सीधी बात कर रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उस बात को रजिस्ट करूँ। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: इस देश की 70 साल राजनीति ऐसी रही है कि कोई कांग्रेसी सैल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ... (व्यवधान)

वर्ल्ड बैंक के डेटा ऑफ एन्टरप्रियोनर्स में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। सितंबर 2017 से नवंबर 2019 के बीच ईपीएफओ पेट्रोल डाटा में 1 करोड़ 39 लाख नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, बिना रोजगार के कोई पैसा जमा नहीं करता है।

मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा-पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि छः महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। यह बात सही है कि यह काम जरा कठिन है तो तैयारी के लिए छः महीने तो लगते ही हैं। ... (व्यवधान) छः महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैंने भी तय किया है कि छः महीने रोज़ सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूँ, और अपने आपको गालीप्रूफ बना दिया है, छः महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य

नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने वाली ताकत वाला बना दूंगा। ... (व्यवधान) मैं आभारी हूँ कि पहले से एनाउंस कर दिया है, तो मुझे छः महीने एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा।

श्री राहुल गांधी (वायनाड): आप रोजगार की बात कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप बेरोजगारी की बात कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा हूँ, लेकिन करंट पहुंचते-पहुंचते इतनी देर लग गई। ... (व्यवधान) बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। ... (व्यवधान)

इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी, ये करोड़ों नई जॉब्स के लिए अवसर लेकर आती हैं।
(1325/MK/SMN)

स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल फोर्स तैयार करना, लेबर रिफार्म्स का प्रस्ताव ऑलरेडी संसद में आगे बढ़ा है और भी कुछ प्रस्ताव हैं, मुझे विश्वास है कि यह सदन उसको भी बल देगा ताकि देश में रोजगार के अवसरों में कोई रूकावट न आए। हम पिछली सदी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में नई सोच के साथ इन सारे बदलावों के लिए आना होगा। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि लेबर रिफार्म्स के जो काम हैं, जो सब लेबर यूनियनों के साथ मिलकर तय हुआ है, उसको जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे, रोजगार के नए अवसरों के लिए सुविधा बढ़ेगी और मैं विश्वास करता हूँ।

फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ लिविंग, ये ऐसे नहीं होते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप कांग्रेस से भी पीछे हो गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप ही सबसे पीछे हैं क्यों? ... (व्यवधान) सारा प्रोफिट मेकिंग इंडस्ट्री को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कोई टिप्पणी मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि हमने आने वाले दिनों में 16 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन, पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितना ज्यादा बल इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को देते हैं, वह इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है, रोजगार को भी देता है और नए-नए उद्योगों को भी अवसर देता है। इसलिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम में एक नई गति लाई है। वरना, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था कि सीमेंट कांक्रीट के जंगलों की बात, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था टेंडर की प्रक्रियाएं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था बिचौलिया। यही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती थी तो लोगों को यही लगता था कि कुछ बू आती थी। आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी में आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं, उस पर बल दिया है। हमारी भूमि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह सिर्फ एक सीमेंट कांक्रीट का खेल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर आता है। कारगिल से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, इसको अगर जोड़ने का

काम करने की ताकत किसी में होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एस्पिरेशन और एचीवमेंट्स को जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की क्रिएटिविटी को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, वह इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके कंज्यूमर के साथ जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। ... (व्यवधान) प्रदूषण को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेगनेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। इसीलिए, इरीगेशन से लेकर इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर वाटरवेज तक हमने अनेक ऐसे इनीशिएटिव्स लिए हैं। गत पांच वर्षों में देश ने देखा है और लोगों ने देखा है, तभी तो यहां बैठाया है। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है। ... (व्यवधान)

(1330/YSH/VR)

हमें यूपी की जनता ने बता दिया है।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कैसे होता था। अभी हमारी दिल्ली का विषय ही ले लीजिए। दिल्ली में ट्रैफिक, इन्वायरमेंट और हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रहे थे। यूपीए सरकार ने दिल्ली के सराउंडिंग पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को वर्ष 2009 तक पूरा करने का संकल्प लिया था। हम वर्ष 2014 में आएँ, तब तक वह कागजों में लकीरें बनकर पड़ा हुआ था। हमने वर्ष 2014 के बाद मिशन मोड में इस काम को लिया और आज पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो गया। आज चालीस हजार ट्रक्स दिल्ली में नहीं आते हैं, वे सीधे बाहर जाते हैं। आज दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए यह एक अहम कदम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है? अगर वर्ष 2009 तक पूरा करने का सपना वर्ष 2014 तक कागजों में लकीर बनकर पड़ा रहा हो तो यह अंतर है। आपको उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ अन्य विषयों को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। शशि थरूर जी, आपको नींद आती होगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ लोगों ने बार-बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की हैं। मैं भी मानता हूँ कि कांग्रेस को संविधान बचाने की बात दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए। यह जरूरी है, क्योंकि संविधान के साथ कब और क्या हुआ, अगर आप संविधान का महत्व समझते तो संविधान के साथ यह नहीं हुआ होता। इसलिए आप जितनी बार संविधान बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का अहसास करवा देंगी। आपके इरादों का अहसास करवा देंगी और इस देश में सच में संविधान महामूल्य है, इसका भी अनुभव कराएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, ये वही लोग हैं। क्या आपको इमरजेंसी में संविधान बचाने का काम याद नहीं आया था। यही लोग हैं, इनको संविधान बचाने के लिए बार-बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप इन्होंने ही किया है। जिन लोगों ने

लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार-बार संविधान बोलना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। अगर संविधान में सबसे ज्यादा बार बदलाव करने के प्रस्ताव को कोई लेकर आया है तो उन लोगों के पास संविधान बचाने की बात बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिन लोगों ने दर्जनों बार राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, उनके लिए संविधान बचाना, यह बोल-बोल कर इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया हो और उस प्रस्ताव को प्रेस कान्फ्रेंस में फाँड देना, उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है और उन लोगों को बार-बार संविधान बचाओ का मंत्र बोलना बहुत जरूरी है।

(1335/RPS/SAN)

पी.एम. और पी.एम.ओ. के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप इस तरह की बातें मत करिए। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान) संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या-क्या हो रहा है, उसे देश भलीभांति देख रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत, जो संविधान के अंतर्गत सीधा-सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार-बार कहे कि आन्दोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आन्दोलन ऐसे न हो जो हिंसा के रास्ते पर चल पड़े। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यूपी में क्या हुआ? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप बड़ी-बड़ी बात कहते हैं, यूपी में क्या हुआ? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: अधीर जी, आपने इतनी मेहनत की है, अब आपका सी.आर. ठीक हो गया है। ... (व्यवधान) आपका सी.आर. ठीक हो गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यूपी में क्या हुआ, आपको बोलना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: आपका सी.आर. ठीक हो गया है। ... (व्यवधान) संविधान को बचाने की बातें करते हैं, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा-जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपके एक मंत्री कहते हैं कि गोली से उड़ा दो। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था और शायद वह इस स्थिति पर बहुत सटीक है:

“खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।”

पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए, सदन में उसका जिक्र करना सही नहीं है। पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गईं, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, ... (व्यवधान) और सदन के बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): लेकिन शाहीन बाग में गोली चलाना सही नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में ...(व्यवधान) दादा, पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं, वहां क्या चल रहा है, अगर वे इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तो आपको तकलीफ होगी। ...(व्यवधान) दादा, आपको तकलीफ होगी। ...(व्यवधान) वहां निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है, वह भलीभांति जानते हैं लोग। ...(व्यवधान)

(1340/IND/RBN)

अध्यक्ष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकारों की क्या स्थिति थी? जैसा हम मानते हैं कि संविधान इतना महत्वपूर्ण है, यदि ये मानते होते, तो जम्मू-कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने के लिए आपको किसने रोका था? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू-कश्मीर के मेरे भाइयों-बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया है और शशि जी, आप तो जम्मू-कश्मीर के दामाद रहे हैं। आप उन बेटियों की चिंता करते... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। किसी की नजर में तो जम्मू-कश्मीर तो केवल जमीन ही थी।... (व्यवधान) कश्मीर में जिन्हें सिर्फ जमीन ही दिखती है, उन्हें इस देश का कुछ अंदाज नहीं है और यह उनकी बौद्धिक दरिद्रता का परिचय करवाता है।... (व्यवधान) कश्मीर भारत का मुकुट मणि है।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, कुछ लोगों ने 19 जनवरी, 1990 की काली रात के समय कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परम्परा है। कश्मीर की आइडेंटिटी 'सर्व पंथ सम्भाव' की है। कश्मीर के प्रतिनिधि माँ लाल देद, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर की आइडेंटिटी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। ये कैसे भविष्यवेत्ता हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नेता जेल में हैं, फलां हैं, वगैरह-वगैरहा यह सदन संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, यह संविधान को समर्पित सदन है। यह संविधान का गौरव करने वाला सदन है। यह संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों की आत्मा को छूने की कोशिश करना चाहता है, अगर है तो! ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था? संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने कि महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा था। ये शब्द बहुत गंभीर हैं।

(1345/ASA/SM)

उन्होंने कहा था: "भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था, उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था।" क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं? उनकी वकालत करते हो? उनका अनुमोदन करते हो?... (व्यवधान) उसी प्रकार से श्रीमान उमर अबदुल्ला जी ने कहा था, "आर्टिकल 370 को हटाना, ... (व्यवधान) उमर अबदुल्ला जी ने कहा था: आर्टिकल 370 का हटाया जाना ऐसा भूकम्प लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा।" ... (व्यवधान) माननीय फारुख अबदुल्ला जी ने कहा था: " धारा 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का

मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर धारा 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा।” क्या इस भाषा से, इस भावना से, हिन्दुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है? कोई इससे सहमत हो सकता है क्या? ... (व्यवधान) मैं यह बात उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी आत्मा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की अवाम पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो हैं जिनको कश्मीर की अवाम पर भरोसा है। ... (व्यवधान) हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की अवाम पर भरोसा किया और धारा 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। ... (व्यवधान) और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो, चाहे केरल हो। कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। जनता के साथ संवाद करके वहाँ की समस्याओं का समाधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम आज इस सदन से जम्मू-कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य के लिए, जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर के लोगों की आशाओं-अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब लोग संविधान के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ-साथ मैं लद्दाख के विषय में भी कहना चाहूँगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने एक ऑरगेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को, सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के किसान और उसके नागरिक इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं मानता हूँ कि लद्दाख के विषय में मेरे मन में बहुत साफ चित्र है।

(1350/RAJ/AK)

इसलिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में एन्वायरन्मेंट को लेकर भूटान की भूरी-भूरी प्रशंसा हो रही है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी हुई है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम सभी को संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे। देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब मैं लद्दाख जाऊँगा, तो उनके साथ रह कर, मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो कानून इस सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही हैं। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सारा देश उसके खिलाफ है। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी? ... (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह सरकार भेदभाव कर रही है, यह सरकार हिन्दू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा है कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई

है।...(व्यवधान) वे लोग बोल रहे हैं, जो देश के टुकड़े-टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े हो कर फोटो खिंचवाते हैं।...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): What are you going to do about the Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu? ...(*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है। पाकिस्तान यही बातें कर रहा है।...(व्यवधान) भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।...(व्यवधान) भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेला है, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात नहीं चलती है।...(व्यवधान) पाकिस्तान की बात बन नहीं पा रही है। मैं हैरान हूँ कि जिनको हिन्दुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं, जो कभी यह देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि 'क्विट इंडिया' का नारा देने वाले, 'जय हिन्द' का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए, हमारी नजर में भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खाँ हो,...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Are not Muslims Indians? ...(*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे लड़कपन में खान अब्दुल गफ्फार खाँ जी के चरण छूने का अवसर मिला है। मैं इसे अपना गर्व मानता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खाँ हों, अशाफाकुल्ला खाँ हों, बेगम हजरत महल हों, वीर शहीद अब्दुल हमीद हों या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान् ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हों, सब के सब हमारी नजर से भारतीय हैं।...(व्यवधान)

सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले।...(व्यवधान) आप जोड़ देना। जो नाम लिखवा दें, मेरे भाषण में लिख देना।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मौलाना आजाद का नाम लिख दें।

SHRI NARENDRA MODI : Thank you for this assistance. ...(*Interruptions*)

(1355/VB/SPR)

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, होगा, होगा।

खैर, मैं कांग्रेस और उनके इको-सिस्टम का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो-हल्ला मचाकर रखा है। अगर ये इतना विरोध नहीं करते, इतना हो-हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता।...(व्यवधान) देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है।...(व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि जब यह चर्चा निकल पड़ी है, तो बात दूर तक चली जाए।

प्रधान मंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी को प्रधान मंत्री बनना था, इसलिए हिन्दुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बँटवारा कर दिया गया। बँटवारे के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में हिन्दुओं, सिखों और अन्य

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, जोर-जबरदस्ती हुई उनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है।

मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भूपेन्द्र कुमार दत्त का नाम सुना है?... (व्यवधान) दादा! आप कांग्रेस में चले गए? ... (व्यवधान) ममता दीदी भाषण सुन रही है। ... (व्यवधान)

कांग्रेस के लिए यह जानना बहुत जरूरी है और जो यहाँ नहीं हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी है। भूपेन्द्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए। वे एक ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिनों तक जेल के अन्दर भूख हड़ताल की थी। यह भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेन्द्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहाँ की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान के काम की शुरुआत के ही दिन थे, उस समय भूपेन्द्र कुमार दत्त ने उस संविधान सभा में जो कहा था, उसे आज मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग हम पर आरोप मढ़ रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है। भूपेन्द्र कुमार दत्त ने कहा था- 'So far as this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquified.'

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Liquidated.

SHRI NARENDRA MODI: Practically liquidated. He also says, 'Those of us who are here to live represent near a crore of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration.' भूपेन्द्र कुमार दत्त ने बँटवारे के तुरन्त बाद वहाँ की संविधान सभा में यह दर्द व्यक्त किया था।

(1400/PC/UB)

स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही वहां के अल्पसंख्यकों की यह हालत थी। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप इंडिया को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेन्द्र दत्त को भारत आकर शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी मां भारती की गोद में हुआ। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): तो क्या हुआ? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ। ... (व्यवधान) कुछ नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

आपके लिए तो सामान्य है। ... (व्यवधान) आए तो आए, मरे तो मरे। ... (व्यवधान) यही आपकी सोच है। ... (व्यवधान) यही आपकी सोच है, महापुरुष। ... (व्यवधान) यह आपकी सोच है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, तब के पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्रता सेनानी रुक गए थे -जोगेन्द्र नाथ मंडला... (व्यवधान) वे बहुत ही पीड़ित, शोषित, कुचले समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। ... (व्यवधान) उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। 9 अक्टूबर, 1950, अभी आजादी के और बंटवारे के दो-तीन साल हुए थे, 9 अक्टूबर, 1950 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ... (व्यवधान) उनके इस्तीफे का एक पैराग्राफ, इस्तीफे में जो लिखा था, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था - "I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan." उन्होंने आगे कहा था - "Pakistan has not given the Muslim League, entire satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way be influenced by them."

यह मंडल जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था। इन्हें भी आखिरकार भारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी मां भारती की गोद में हुआ। इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली है। वहां आज भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी-अभी नानकाना साहेब के साथ क्या हुआ, सारे देश और दुनिया ने देखा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिन्दू और सिखों के साथ ही होता है, और भी माइनोंरिटीज़ के साथ ऐसा ही जुल्म वहां होता है। इसाइयों को भी ऐसी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। ... (व्यवधान)

सदन में चर्चा के दर्मियान गांधी जी के कथन को लेकर भी बात कही गई है। कहा गया कि सीएए पर सरकार जो कह रही है, वह गांधी जी की भावना नहीं थी। खैर, कांग्रेस जैसे दलों ने तो गांधी जी की बातों को दशकों पहले छोड़ दिया था। ... (व्यवधान) Quotable quote is available, हमने पचासों बार दे दिया है। ... (व्यवधान) आपने तो गांधी जी को छोड़ दिया है। ... (व्यवधान) इसलिए न मैं, न देश आपसे कोई अपेक्षा करता है, लेकिन जिसके आधार पर कांग्रेस की रोजी-रोटी चल रही है, मैं आज उनकी बात करना चाहता हूं। वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ।

(1405/MM/KMR)

भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनोरिटीज की सुरक्षा को लेकर यह समझौता हुआ। समझौते का आधार- पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनकी बात हम बोल रहे हैं, उनके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा, नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्यूलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनोरिटी के बजाय “सारे नागरिक” ऐसे शब्द प्रयोग क्यों नहीं किए? अगर इतने ही महान और इतने ही उदार थे तो क्यों नहीं किया? कोई तो कारण होगा? लेकिन इस सत्य को आप कब तक झुठलाओगे? माननीय अध्यक्ष जी, यह उस समय की बात है। यह मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) नेहरू जी इस समझौते में पाकिस्तान की माइनोरिटी, इस बात पर कैसे मान गए? जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम आज बता रहे हैं, वही बात उस समय नेहरू जी ने बताई थी।

माननीय अध्यक्ष जी, नेहरू जी ने माइनोरिटी शब्द का प्रयोग क्यों किया? यह आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको तकलीफ है। लेकिन नेहरू जी खुद इसका जवाब देकर गए हैं। मुझे मालूम है आप उनको भी छोड़ दोगे। जहां जरूरत पड़े, आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। नेहरू जी ने नेहरू-लियाकत समझौता साइन होने के एक साल पहले असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी को एक पत्र लिखा था। गोपीनाथ जी को जो पत्र लिखा और उसमें जो लिखा था, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने पत्र में लिखा था। जो लोग कहते हैं न कि हम हिन्दू-मुस्लिम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। नेहरू जी ने क्या कहा था, यह आप याद रखना। गोपीनाथ जी, जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनको नेहरू जी ने लिखा था – “आपको हिन्दू शरणार्थियों और मुस्लिम इमिग्रेंट्स, इसके बीच फर्क करना ही होगा और देश को इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी।” उस समय के असम के मुख्यमंत्री को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है। नेहरू-लियाकत समझौते के कुछ महीने बाद ही नेहरू जी का इसी संसद के फ्लोर पर 5 नवम्बर, 1950 का उनका एक बयान है। 5 नवम्बर, 1950 को नेहरू जी ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में सेटल होने के लिए आए हैं, ये लोग नागरिकता मिलने के हकदार हैं और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

वर्ष 1963 में लोक सभा के इसी सदन में और इसी जगह से वर्ष 1963 में कालिंग अटेंशन मोशन हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

(1410/SJN/SNT)

मोशन का जवाब देने के लिए जब विदेश राज्य मंत्री श्रीमान् दिनेश सिंह जी बोल रहे थे, तो आखिर में प्रधान मंत्री नेहरू जी ने उनको बीच में टोकते हुए कहा था। उन्होंने जो कहा था, मैं वह कोट करना चाहता हूँ कि "पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ की अर्थोरिटी हिन्दुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है।" यह पंडित जी का स्टेटमेंट था।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : हम भी यही शिकायत करते हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : पाकिस्तान के हालात को देखते हुए गांधी जी ही नहीं, बल्कि नेहरू जी की भी यही भावना रही थी। इतने सारे दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हैं।...(व्यवधान) सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं।...(व्यवधान) मैंने इस सदन में तथ्यों के आधार पर।...(व्यवधान)

मैं अब कांग्रेस से खास रूप से यह पूछना चाहता हूँ और उनका ईको सिस्टम भी मेरा सवाल समझेगी। मैंने जो ये सारी बातें बताई हैं, क्या पंडित नेहरू जी कम्युनल थे? मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। क्या पंडित नेहरू जी हिन्दू-मुस्लिम में भेद किया करते थे?...(व्यवधान) क्या पंडित नेहरू जी हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते थे? उन्होंने जो बातें कही हैं, क्या पंडित नेहरू जी हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते थे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वह बातें बनाती है, 'झूठे' वादे करती है और वह दशकों तक वादों को टालती रहती है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, यह 'झूठ' बात डिलीट कीजिए। यह 'झूठ' शब्द अनपार्लियामेन्ट्री है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है, तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है।...(व्यवधान) मैं इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को इस सदन के माध्यम से फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए कहना चाहता हूँ, संविधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूँ, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूँ, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि सीएए, इस बिल से, इस एक्ट से हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी नहीं होने वाला है।...(व्यवधान) इससे भारत की माइनोरिटीज़ को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।...(व्यवधान) फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, वे लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यह खेल खेल रहे हैं। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

मैं विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो माइनोरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। क्या कांग्रेस को सन् 1984 के दिल्ली के दंगे याद हैं?...(व्यवधान) क्या वह माइनोरिटी नहीं थी?...(व्यवधान) वह माइनोरिटी थी कि नहीं थी?...(व्यवधान) हमारे सिख भाइयों के गलों में टायर बांध-बांधकर उनको जला दिया गया था।...(व्यवधान)

इतना ही नहीं, आपने सिख दंगों के आरोपियों को जेल में भेजने तक का काम नहीं किया है... (व्यवधान) इतना ही नहीं, आज जिन पर सिख दंगों को भड़काने के आरोप लगे हुए हैं, आप आज उनको मुख्य मंत्री बना देते हैं... (व्यवधान) सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने में, हमारी उन विधवा माताओं को तीन-तीन दशकों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा है। क्या वह माइनोरिटी नहीं थी?... (व्यवधान) क्या माइनोरिटी के लिए दो-दो तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? ... (व्यवधान)

(1415/GG/GM)

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी – जिसने इतने सालों तक देश में राज किया, आज देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में देश को अपेक्षाएं थीं, वे आज गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। यह रास्ता आपके लिए भी मुसीबत पैदा करने वाला है। देश को भी संकट में डालने वाला है। यह चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम सबको देश की चिंता होनी चाहिए। देश के उज्ज्वल भविष्य की चिंता होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर राजस्थान की विधान सभा कोई निर्णय करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे और राजस्थान में वह कोई मानने को तैयार न हो, जलसे-जुलूस निकाले, हिंसा करे, आगजनी करे, आपकी सरकार है, क्या स्थिति बनेगी? मध्य प्रदेश – आप वहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश की विधान सभा कोई निर्णय करेगी और वहां की जनता उसके खिलाफ इसी प्रकार से निकल पड़े। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या एनार्की का रास्ता सही है? ... (व्यवधान) इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। ... (व्यवधान) अपने इतना गलत किया है, इसीलिए तो वहां बैठना पड़ा है। यह आपके कारनामों का ही परिणाम है कि जनता ने आपको वहां बिठाया है। ... (व्यवधान) इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में हरेक को अपनी बात बताने का हक है। लेकिन झूठ और अफवाहें फैला कर, लोगों को गुमराह कर के हम देश का कोई भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूँ – आइए, संविधान का सम्मान करें। आइए, मिल-बैठ कर को देश चलाएं। आइए, देश को आगे ले जाएं। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए एक संकल्प ले कर हम चलें। ... (व्यवधान) आइए, देश के 15 करोड़ परिवार, जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, वह पहुंचाने का संकल्प करें। ... (व्यवधान) आइए, देश के हर गरीब को पक्का घर लेने के काम को हम मिल कर के आगे बढ़ाएं, ताकि उनको पक्का घर मिले। आइए, देश के किसान हों, मछुआरे हों, पशुपालक हों, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। ... (व्यवधान) आइए हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें। ... (व्यवधान) आइए, एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प ले कर हम आगे बढ़ें। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम मिल-बैठ कर आगे चलें। ... (व्यवधान) इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक-अनेक धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के सामने मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1419 बजे

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही, तीन बज कर बीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न पन्द्रह बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1520-1525/PC/RBN)

1527 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजकर सत्ताइस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।(डॉ. किरीट पी. सोलंकी पीठासीन हुए)**सामान्य बजट - सामान्य चर्चा**

1527 बजे

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): अब हम सामान्य बजट पर चर्चा आरंभ करते हैं।

श्री मनीष तिवारी।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय के ऊपर आज अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज से सात दशक पहले, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, उसकी प्रस्तावना को अपनाया था। उस प्रस्तावना में एक पंक्ति है। हमने अपने लोगों के साथ एक वायदा किया था कि हम उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे?

महोदय, आज सात दशक के बाद इस सदन को बहुत गंभीरता से इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि क्या जो वायदा हमने अपने लोगों से किया था, उसको हम पूरा कर पाए हैं या नहीं। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय किसी हद तक हम दे पाए हैं, पर क्या जो आर्थिक न्याय का वायदा है, वह हम पूरे कर पाए हैं? इसके ऊपर इस सदन में एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज सुबह जब प्रश्न काल चल रहा था तो भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसके ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से एक मंत्री महोदय ने एक टिप्पणी की थी। मैं उस टिप्पणी को दोहराना चाहता हूँ। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वह दुनिया का 2.4 प्रतिशत है। भारत की जो जनसंख्या है, वह दुनिया की जनसंख्या की 17.7 प्रतिशत है, लेकिन भारत में जो 73 प्रतिशत धन है, वह एक प्रतिशत लोगों के हाथ में है। 101 पूंजीपति 20 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के मालिक हैं। भारत सरकार का पिछले वर्ष का जो पूरा राजस्व है, वह 27 लाख करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 2017-18 में, जिसके आंकड़े एवलेबल हैं, जो यह 101 पूंजीपति थे, उनका जो धन था, वह 4.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़ा था।

(1530/MM/SM)

67 करोड़ भारत के नागरिकों का धन उसी कार्य काल में सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ा था। यह परिस्थिति सिर्फ भारत की नहीं है। अगर आप दुनिया के परिपेक्ष्य को देखें तो 8 बिलियर्स के पास उतना ही धन है, जितना 400 करोड़ लोगों के पास है। 25 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जो आय है, वह 85 प्रतिशत मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा है। इसलिए हमको बहुत गम्भीरता से इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि 124 करोड़ लोगों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए हमने अपना जो

आर्थिक ढांचा अपनाया है, क्या वह आर्थिक ढांचा सही है या नहीं? अगर आप वर्ष 1947 से वर्ष 2020 तक का जो भारत का सफर है, उसको दो भागों में बाटते हैं तो वर्ष 1950 से 1990 तक के 40 वर्षों में जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, वह 4.45 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक 6.51 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इस वर्ष वह सिर्फ 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसीलिए मैं दोबारा से यह बात दोहराना चाहता हूँ कि हमने जो आर्थिक ढांचा अपनाया है, जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, उसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

बजट के आय-व्यय से पहले सरकार इस सदन के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण रखती है। वह आर्थिक विश्लेषण सरकार की आर्थिक सोच को इंगित करता है। मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक विश्लेषण है, वह पूरी तरह से दिशाविहीन है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जो धन पैदा करने वाले हैं, उनका स्तुतिगान यह करता है। धन पैदा करने वालों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को यह साफ करना चाहिए कि सरकार की जो आर्थिक नीति है, जिसको आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखा गया है, क्या वह 125 करोड़ भारतीयों के लिए काम करेगा या 101 पूंजीपतियों के लिए काम करेगा? दूसरा, जो आर्थिक विश्लेषण है, वह एक पुरानी और बेकार की बहस को दोबारा शुरू करना चाहता है और वह बहस क्या है, न्यू लिब्रलिजम अर्थात् नव उदारतावाद बनाम समाजवाद। अब यह वर्ष 1990 की बहस है। वर्ष 1990 की बहस को वर्ष 2020 में पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस नव उदारतावाद को, इस वैश्विकरण की बात को दोबारा से सदन के समक्ष रखना चाहते हैं, वह शायद इस बात को भूल रहे हैं कि जो नव उदारतावाद के, न्यू लिब्रलिजम के जनक थे, उन्होंने उस नव उदारतावाद को आज नकार दिया है। जो वाशिंगटन कंसैन्स के निर्माता थे, उन्होंने उस वाशिंगटन आम सहमति को उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह है। अगर आप वर्ष 1990 के मॉडल को वर्ष 2020 में पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं तो आप भारत की जनता के साथ, भारत के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तीसरी बार मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस सदन को बड़ी जिम्मेवारी से आने वाले भारत के भविष्य के लिए क्या आर्थिक मॉडल होना चाहिए, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है।

(1535/SJN/AK)

सभापति महोदय, अब मैं आम बजट पर आता हूँ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस हुआ है और सरकार ने उसको जुकाम की दवाई दे दी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत, 11 सालों में सबसे कम। निजी खपत 5.8 प्रतिशत, 7 वर्षों में सबसे कम। निवेश ग्रोथ 1 प्रतिशत, 17 वर्षों में सबसे कम। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2 प्रतिशत, 15 वर्षों में सबसे कम। कृषि की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत, 4 वर्षों में सबसे कम। अप्रैल-जनवरी,

2020 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 7.6 प्रतिशत। पिछले वर्ष उसी अप्रैल-जनवरी, 2019 में यह 14.5 प्रतिशत था।

मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखना चाहता हूँ। बेरोजगारी दर 7.35 प्रतिशत, 5 सालों में सबसे ज्यादा। एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से 6.1 प्रतिशत, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा। सीएमआई के हिसाब से बेरोजगारी दर 8.45 प्रतिशत, 3 वर्षों में सबसे ज्यादा। जो आयात है, वह दिसंबर, 2019 में 27.36 बिलियन यूएस डालर था, वह पिछले वर्ष के बनिस्बत 1.8 प्रतिशत कम है। जो निर्यात था, वह 36.61 बिलियन डालर था, पिछले वर्ष के बनिस्बत 8.83 प्रतिशत कम है। जो बिजली की खपत थी, वह 5 प्रतिशत कम है। जो हाउस होल्ड सेविंग रेट था, वह एक वर्ष में 23.6 प्रतिशत से घटकर 17.2 प्रतिशत रह गया है। ऐसे अनेक आंकड़े हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वह आज एक बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति में है।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत आधार है, जो बचत से, खपत से, निवेश से और रोजगार से मापा जाता है, जिसको अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कहते हैं। सेविंग्स, कन्जम्प्शन, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लॉयमेंट, आज सभी के परखच्चे उड़े हुए हैं। पिछले वर्ष सरकार ने एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ स्टिम्युलस देने की कोशिश की थी। लेकिन मैं उस स्टिम्युलस पर आने से पहले आपको कुछ और आंकड़े देना चाहता हूँ। अगर आप फिर भारत को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत की जो 66 प्रतिशत जनता है, वह ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत के 90 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। जब तक वे खपत करना शुरू नहीं करेंगे, वे कन्ज्यूम करना शुरू नहीं करेंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसका चक्र दोबारा से घूमना शुरू नहीं होगा। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने पिछले वर्ष भारत के जो पूंजीपति हैं, भारत के धनपशु हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको 1,45,000 करोड़ रुपयों की रियायत दे दी थी। यह सोचकर की जो अर्थव्यवस्था का चक्र है, वह दोबारा से घूमना शुरू हो जाएगा।

मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि सरकार में बैठे लोग यह नहीं जानते हैं कि जो डिमांड साइड प्रॉब्लम है, उसका जो समाधान है, वह सप्लाई साइड से नहीं हो सकता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या सरकार इस आर्थिक मंदी के पीछे छिपकर जो पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है?

(1540/GG/SPR)

क्योंकि 31 मार्च, 2020 को जब पिछले वर्ष की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सार्वजनिक होंगी, तो यह पता लगेगा कि उन पूंजीपतियों की जो आय है, उनका जो रेवन्यू है, वह कितना बढ़ा और भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने कितना पैसा लगाया। इसकी जो सच्चाई है, यह 31 मार्च – एक अप्रैल 2020 को उजागर होगी। मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो समस्या है, वह डिमांड साइड है। जो उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वह सप्लाई साइड सॉल्यूशन है। अब आप इस बजट के आंकड़े उठा कर देखिए। मनरेगा – जो सीधे तौर पर गरीब आदमी के हाथ में, जो सबसे गरीब है, जो सबसे वंचित है, जो सबसे शोषित है, उसके हाथ में पैसा पहुंचाता है, उसको पिछले वर्ष, जो रिवाइज्ड एस्टिमेंट था, वह 71 हजार दो करोड़ रुपये

था। उसको कम कर के 61 हजार पांच सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है। 13.04 प्रतिशत से उसको कम कर दिया गया है। पिछले वर्ष पीएम किसान योजना में 75 हजार करोड़ रुपये बजटिड था, खर्च कितना हुआ? मात्र 54 हजार 370 करोड़ रुपये खर्च हुआ। पिछले साल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर 19 हजार करोड़ रुपये बजटिड था। खर्च कितना हुआ – 14 हजार 70 करोड़ रुपये। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, जो माननीय वित्त मंत्री जी के वित्तीय भाषण का एक बहुत बड़ा अंग था, उस पर पिछले साल जो बजटिड था, वह एक लाख 51,518 करोड़ रुपये था। जो रिवाइज्ड था, वह एक लाख 20,835 करोड़ रुपये था। इसी तरह से यूरिया सब्सिडी के ऊपर जो रिवाइज्ड बजट था, वह 53,629 करोड़ रुपये था, लेकिन खर्च 47,805 करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण विकास का रिवाइज्ड बजट 1,43,409 करोड़ रुपये था, लेकिन इस वर्ष जो बजट दिया गया है, वह 1,44,817 करोड़ रुपये है, महज़ 0.098 प्रतिशत से उस आउटले को बढ़ाया गया है।

महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा चलाना चाहती है, तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि जब तक 90 करोड़ लोग खपत करना नहीं शुरू करेंगे, आप उनके हाथ में पैसा नहीं देंगे, तो जो अर्थव्यवस्था का घटनाचक्र है, वह नहीं घूम सकता है। क्या सरकार इस बात को समझती नहीं है। अगर सरकार इस बात को समझती है तो उस पर काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जितनी वे स्कीम्स थीं, जितनी वे नीतियां थीं, जिनके कारण अर्थव्यवस्था रिवाइव हो सकती थी, घटनाचक्र घूम सकता था, क्यों उसके ऊपर पैसे बढ़ाने की जगह, उसमें कटौती की गई है। अब सरकार ने अपने बजट में यह घोषणा की कि हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे कर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था 148 लाख करोड़ रुपये की है। चार प्रतिशत आय कर दाता भारत का 60 प्रतिशत टैक्स देते हैं। Four percent assesseees actually pay 60 percent of our tax. अगर सरकार के आंकड़ों से भी आप जाएं, अगर आपने चालीस हजार करोड़ रुपये की रियायत दे भी दी, जो कि चालीस हजार करोड़ रुपये नहीं होगी। परंतु मान लिया कि चालीस हजार करोड़ रुपये की आपने रियायत दे भी दी तो वह तो ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है। कैसे भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा से घूमना शुरू करेगी? इसी तरह से डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स में आपने क्या किया है कि कॉर्पोरेट से हटा कर उसका बर्डन इंडीविजुअल के ऊपर डाल दिया है। एक हाथ से दे और दूसरे हाथ ले, यह डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स की कहानी है।

(1545/KN/UB)

हाँ, कुछ कारपोरेट्स के ऊपर जो रेग्युलेटरी बर्डन है, वह जरूर कम होगा। पर भारत की अर्थव्यवस्था का, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

सभापति महोदय, मैं तीन आखिरी चीजें और कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1947 से वर्ष 2020 तक इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, जिसे आप पब्लिक सेक्टर कहते हैं। अब वित्त मंत्री जी उस पब्लिक सेक्टर को डिस-इनवेस्ट करना चाहती हैं, 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये कमाने के लिए, जिससे वे अपना वित्तीय घाटा पूरा करना चाहती हैं। वह

एलआईसी को भी बेचना चाहती हैं, वह बीपीसीएल को भी बेचना चाहती हैं, वह एयर इंडिया को भी बेचना चाहती हैं और भी जो कम्पनियां उनके संज्ञान में आए, उनको भी बेचना चाहती हैं। पर उस सबसे पहले मैं एक बहुत बुनियादी सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ और वह बुनियादी सवाल यह है कि क्या यह सरकार इस बात को मानती है कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र होना चाहिए? Does the Government believe that India requires a public sector? दूसरा सवाल, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को पब्लिक सेक्टर में विश्वास है? तीसरा, क्या सरकार स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर में कोई फर्क करती है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब वर्ष 2008 में आर्थिक महामंदी का माहौल था, तो अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बचाया और भारत के पब्लिक सेक्टर ने बचाया, अन्यथा बाकी दुनिया की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी लुढ़कती हुई कहीं पर पाई जाती। अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, तो वह हमारे सार्वजनिक क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से है। जो सरकार को यह बात समझाते हैं कि it is not the business of the Government to be in business. मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ, उनसे आगाह रहिए। कल को यही लोग आपको यह कहेंगे, that it is not the business of the Government to be in governance. इन लोगों से आगाह रहने की जरूरत है, जो आज यह कहते हैं- "It is not the business of the Government to be in business". Tomorrow, they will say, "It is not the business of the Government to be in governance". आप कहाँ तक इस चीज को लेकर जाएँगे। इसके ऊपर बहुत गम्भीरता से सरकार को चर्चा करनी चाहिए।

मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आज शायद पहली बार इस देश में हुआ है कि सरकार के जो इकोनॉमिक्स नम्बर्स हैं, सरकार के जो आर्थिक आँकड़े हैं, उन आर्थिक आँकड़ों के ऊपर प्रश्न-चिह्न लगा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, आप नहीं मानते उस विश्वविद्यालय में, पर माननीय वित्त मंत्री जी उसी की छात्रा रही हैं, उनके एक अर्थशास्त्री ने, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि- "Every single number in the Budget is a 'lie'". If you want I can put that statement on the floor of the House. मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के अर्थशास्त्री, जब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर यह बात सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि "Every single number in the Budget is a 'lie'". इसका बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व में भारत की छवि को लेकर पड़ता है, तो सरकार को अपने जो आर्थिक आँकड़े हैं, उनकी विश्वसनीयता दोबारा कायम करने के लिए एक पहल करनी चाहिए।

मैं सिर्फ दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, इस सदन में अपने बजट के भाषण में 12वें पैरा में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के बीच 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। 27 million people were lifted out of poverty and we should be proud of it. मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उन 10 वर्षों में 8 साल इस देश में यूपीए का शासन था और वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक भारत की

अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत से साल दर साल दस साल बढ़ती रही। इसके बावजूद कि आर्थिक महामंदी आई, यूरो ज़ोन क्राइसिस आया, जो कच्चे तेल की कीमत थी, वह आसमान छू रही थी।

सभापति महोदय, अगर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, तो 8 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर के साथ हमने एक मूलभूत ढाँचा तैयार किया था।

(1550/CS/KMR)

राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, मनरेगा, यानी रोजगार का अधिकार, आरटीई, यानी शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्यान का अधिकार और डीबीटी, जिस 'जैम' की आप आज बात करते हैं, वह भी उसी समय शुरू किया गया। यह कोई जादू की छड़ी यूपीए की सरकार ने नहीं घुमायी थी। हमने एक बहुत संवेदनशीलता से एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया था और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया था कि उस बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचे। वह फायदा आखिरी कतार में खड़े हुए उस आखिरी व्यक्ति तक जाए और इस तरह से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था।

अंत में, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव ने, माननीय वित्त मंत्री जी रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, एक बहुत सटीक बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि Money is a coward and money goes to the safest harbour. सामाजिक तनाव और आर्थिक विकास साथ-साथ नहीं चल सकता। अगर आप आर्थिक विकास चाहते हैं तो इस देश में सामाजिक सद्भाव बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप यह सीएए, एनआरसी, एनपीआर करेंगे तो उसका सीधा-सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो वह नकारात्मक सीएए, एनपीआर और एनआरसी के माध्यम से नहीं होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठकर आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1552 बजे

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बजट और अर्थव्यवस्था पर आपके सामने कुछ बातें रखने का एक अवसर दिया है। अभी मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि हमें एक नया डेवलपमेंट मॉडल, एक नई विचारधारा खड़ी करनी होगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा, उन्होंने हमें विस्तार से समझाया कि हमें एक नए इंडिया की ओर बढ़ना है, एक न्यू इंडिया की ओर बढ़ना है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम लोगों को खड़ी करनी है। हमें इस अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, तो पुरानी विचारधारा, पुरानी सोच से, पुराने डेवलपमेंट मॉडल से हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था को नहीं खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हमें उत्साहित किया कि हमें एक नई सोच से, एक नई ऊर्जा से और एक नए विश्वास से एक न्यू इंडिया को बनाना पड़ेगा। मैं अपने विपक्ष के, खासकर कांग्रेस, यूपीए के अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ और बड़ी खुशी से मैं सदन के पटल पर इस किताब को रखूँगा कि जब यूपीए के डेवलपमेंट मॉडल और यूपीए की विचारधारा का जिक्र होता है, लोग इसके बारे में कहते हैं कि उस समय क्रोनी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो था, फ्रॉड सोशलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म चरम पर था। वह आसमान छू रहा था और इस पर एक किताब भी निकली। जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिलियोनेर राज था, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म बिलियोनेर राज था।

जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया है और मैं स्वर्गीय श्री अरूण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सदन के प्रति, पूरी जनता के प्रति और अब माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बिलियोनेर राज को, यह जो बिलियोनेर राज था, जो पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को पकड़े हुए था, इस बिलियोनेर राज को छोड़कर आज नई विचारधारा से प्रेरित होकर, नई ऊर्जा से बढ़ते हुए हम लोगों ने बिलियोनेर राज पीछे छोड़कर एक जनता का राज बनाया है और इसे यह बजट भी दर्शाता है।... (व्यवधान) प्रोफेसर साहब, यह बिलियोनेर राज नहीं, यह जनता का राज है।

अब हम इस बजट पर आएँ, जो जन-जन का बजट कहला रहा है। दूर-दूर, मीडिया में सब लोग इसे जन-जन का बजट कह रहे हैं, जनता का राज है। हमारे क्षेत्र में एक बड़े महाकवि हैं, सिंह साहब को शायद अच्छी तरह से मालूम होगा, हमारे क्षेत्र के, बिहार के, झारखंड के एक महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं।

(1555/RV/SNT)

मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है –

नर हो, न निराश करो मन को

कुछ काम करो, कुछ काम करो

सभापति महोदय, इस कविता में जो पंक्तियाँ हैं, इस बजट स्पीच के बाद इन्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैं इन्हें थोड़ा रिफाइन करता हूँ। हमें कहना पड़ेगा - 'नारी हो', क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने दिखा दिया –

नारी हो, न निराश करो मन को
कुछ काम नहीं, बहुत काम करो, बहुत काम करो

यह बजट इसको दर्शाता है क्योंकि इतिहास में यह सबसे लम्बा बजट है। यह लम्बा बजट था। कुछ काम नहीं, इस बजट से बहुत काम हुए। बजट लम्बा था क्योंकि लोगों के साथ जो बातचीत हुई, जो कंसल्टेशंस हुए, उसके आधार पर इस बजट को तैयार किया गया। इस बजट में हर वर्ग के लिए, हर विषय पर, सबका हल था, सबका समाधान था, चाहे वे किसान हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, शोषित, वंचित जो भी हों, आदिवासी हों, सबके लिए इस बजट में कुछ-न-कुछ था। यह एक फील-गुड बजट था, जन-जन का बजट था। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हमारे दल की तरफ से और मुझे लगता है कि पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, जब हम इस बजट पर बातचीत करते हैं, विपक्ष के साथ हम लोगों की चर्चाएं होती हैं, बहसें होती हैं, तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। चिंता इसलिए होती है कि जब भी हम विपक्ष से इस बजट के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा उलटा देखते हैं, हर चीज को उलटा देखते हैं। समझिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप रियर-व्यू मिरर में तो नहीं देखेंगे। गाड़ी चलाने के लिए तो आपको विंडशिल्ड से देखना होगा। आप विंडशिल्ड से देखिए। आप जो आंकड़े बताते हैं, मनीष जी ने अभी-अभी कई आंकड़े दिए, वे सब पुराने आंकड़े हैं। इसका मतलब है कि विंडशिल्ड से आगे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में इनकी कोई बात ही नहीं होती है, इसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। हमें विंडशिल्ड से देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है - चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है। हम आगे देखें। अर्थव्यवस्था में जिसे कहते हैं - हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें तो वे दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी करवट ली है। अगर अभी हम देखें, अभी जो अखबारों में आया है, उसे भी हम सदन के सामने रखेंगे, तो अगर हम उसे देखें तो वहां नजर आएगा कि जो 'परचेजिंग मैनेजर्स' सर्वे आता है, वह 7-ईयर हाई पर है। यह मैनुफैक्चरिंग का है। जो सर्विसेज का है, वह दर्शाता है कि वह 8-ईयर हाई पर है। आप कोर आउटपुट देखें। वह बढ़ने लगा है। जो कंजम्पशन है, फास्ट-मूविंग-कन्ज्यूमर-गुड्स हैं, अगर उन्हें देखें तो वे बढ़ने लगे हैं। इसलिए अगर आप आगे की तरफ देखें, विंडशिल्ड से देखें, पीछे की तरफ न देखें, रियर-व्यू मिरर में न देखें, आप आगे देखें तो आपको नजर आएगा कि जो अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि यह आगे नहीं बढ़ेगी, वह 6-6.5 प्रतिशत रियल ग्रोथ रेट पर आगे बढ़ने वाली है। यह सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा गया है, यह आज के समय आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक और जो सारी बड़ी प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, वे सब यह बता रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती से आगे बढ़ने वाली है।

सभापति महोदय, एक और आंकड़ा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जी.एस.टी. का कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। यह एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया है। जहां तक मुझे खबर है, 1.1 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन जनवरी में हुआ है और यह कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। जिस कुशलता से जी.एस.टी. पर अमल किया गया है, वह सबसे ब्रॉड-बेस्ड इकोनॉमिक

एक्टीविटीज़ का जो इंडिकेटर है, वह जी.एस.टी. है। जी.एस.टी. के कलेक्शंस में हमें वह नजर आ रहा है कि इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जा रही है।

सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था करवट लेकर और तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वह इसलिए बढ़ रही है कि जो प्राथमिकता हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक स्टैबिलिटी पर देना था, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैबिलिटी के द्वारा अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाना था, उसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से किया है।

हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें। वर्ष 2018-19 में वर्ष 2019 में जो 3.4 प्रतिशत था, वह इस बार 3.8 प्रतिशत है और उन्होंने यह अनुमान किया है कि आगे यह 3.5 प्रतिशत है। इस समय जो 0.5 प्रतिशत का पॉज़ लेना था, उन्होंने बड़ी कुशलता से लिया है और फिस्कल डेफिसिट को एकदम नियंत्रण में रखा है।

(1600/CP/GM)

इससे लोगों का विश्वास अवश्य बना है। जो फिस्कल डेफिसिट आया है, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा कि इस पर आप जरा ध्यान दें कि जो खर्च हुआ है, जो डेफिसिट पेंडिंग हुई है, उसकी क्या रूप-रेखा है, किस प्रकार से इस पर खर्च किया गया है? अगर आप गौर से बजट के नंबर पर ध्यान दें और जो हुआ है इसके बारे में, यह अनुमान नहीं है, हकीकत है, हकीकत यह है कि कैपिटल एक्सपेंडीचर इस साल, मैं फिस्कल 2020 की बात कर रहा हूं, जो साल अभी गुजर रहा है, फिस्कल 2020 में जहां हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट 1.17 लाख करोड़ है, 3.8 पर्सेंट को अगर आप देखें, तो फिस्कल डेफिसिट 63,000 करोड़ था, जो 1.17 लाख करोड़ बढ़ा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर अगर हम लोग देखें, तो कैपिटल एक्सपेंडीचर भी 1.4 लाख करोड़ बढ़े हैं। अगर हम लोगों ने खर्च किया है, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, तो वह कहां बढ़ा है? वह वहां बढ़ा है, जहां हमें निवेश करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडीचर करना चाहिए, जिसमें कि आगे के समय अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़े।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आपको फिस्कल डेफिसिट पेंडिंग करनी पड़ी, तो आपने ऐसे क्षेत्र में किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे के समय और फायदा होगा और उससे जॉब क्रिएशन भी होगा। जब नया इनफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो हम सब लोगों को इससे लाभ भी होगा। इस एसेट क्रिएशन के साथ जो मार्केट बारोइंग्स हैं, वे 4.48 लाख करोड़, मतलब काफी संतुलित तरीके से किया गया है और आगे के समय 12 पर्सेंट ही इसमें ग्रोथ होने वाली है। मार्केट बारोइंग्स भी बड़े कंट्रोल में है, जो 4.99 लाख करोड़ होने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए अगर आपको और ऋण लेना पड़े, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सही चीज है, इसके द्वारा एसेट क्रिएशन हो रहा है।

मनीष जी के साथ हम लोग फाइनेंस कमेटी में हैं। उनके साथ हरदम चर्चा होती रहती है। बड़े ध्यान से और बड़ी महीनता से वे हर चीज को देखते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे चिंता होती है कि वे थोड़ा उलटा देखने लगते हैं... (व्यवधान) जिन बुनियादी पैरामीटर्स के बारे में उन्होंने कहा, कंजम्पशन, इनवेस्ट, सेविंग और रियर व्यू मिरर से जो पीछे की चीजें देख रहे थे, उन्हीं बातों को मैं अब थोड़ा सही रूप से पेश करता हूँ। इस पर बड़ी बातचीत हो रही है कि कंजम्पशन पर क्या हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, कंजम्पशन में प्रोत्साहन हुआ है या नहीं? मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ विपक्ष के अपने साथियों को कि किसान सम्मान योजना, फिसकल 2020 में हमने कहा था कि हम इस पर खर्च करने लगे, सीधे किसान के हाथ में हम लोग सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके समर्थन पहुंचाएंगे। फिसकल 2020 में इस पर 54 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। कंजम्पशन बूस्ट की बात हो रही है कि हम कंजम्पशन को प्रोत्साहन कैसे देंगे? माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या किया है? फिसकल 2020, यानी जो आने वाला साल है, इस साल जो 54,000 करोड़ रुपये था, अब किसान सम्मान योजना के तहत हम लोग 75,000 करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक के खाते में दे रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट हो गया। मनीष जी, आप देख रहे हैं या नहीं, यह 54 से 75 हुआ या नहीं। बस थोड़ा आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा।

नरेगा के खर्च में भी बढ़त हो रही है। नरेगा में भी पैसा दिया जा रहा है। इससे भी लोगों का कंजम्पशन बूस्ट होगा। मेरा अनुमान है कि हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल कंजम्पशन जिसकी बात होती है, अगर 15-18 करोड़ परिवार जो रूरल सैक्टर में हैं, तो किसान सम्मान योजना के तहत और नरेगा के तहत हम लोग उनको सहयोग दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हर परिवार को सालाना 10-15 हजार सीधा इनके बैंक के खाते में कंजम्पशन बूस्ट हम लोग देने वाले हैं। यह तो बड़ा जबरदस्त कंजम्पशन बढ़ गया।

अब हम टैक्स कट पर आते हैं। यहां भी मनीष का एनालिसिस थोड़ा उलटा था।

1604 बजे

(श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

हम देखें कि जो अर्बन मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स हैं, उनको टैक्स कट के द्वारा कितना लाभ मिल रहा है, तो मनीष जी ने कहा कि उन बड़े-बड़े टैक्स पेयर्स को देखो, जो अधिकतर टैक्स भरते हैं। आप देखें कि किस तरीके से और कितने स्िकलफुली वित्त मंत्री जी ने इस टैक्स कट को तैयार किया है। आप अनुमान करें, मनीष जी तो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बहुत जाने-माने एडवोकेट हैं, तो शायद 15 लाख रुपये से कम आय के जो लोग हैं, उनको कितना टैक्स भरना होता है, उनकी कितनी बचत होती है, शायद उनको उतना अनुमान न हो।

(1605/RK/NK)

लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि अखबार में काफी कुछ निकला था- जो पन्द्रह लाख रुपये से कम टैक्सपेयर्स हैं those with the highest propensity to consume, are the ones who are going to get the most benefit from this tax slab. आज चालीस हजार करोड़ रुपये उन लोगों के पास जा रहा है जिनकी कमाई पन्द्रह लाख से कम है और वही खर्चा करेंगे, वही चालीस हजार करोड़ रुपये इनकी बचत होगी। एक अनुमान है जो अखबारों में एनालिसिस निकला

है कि लगभग तीन से पांच हजार रुपये आपकी हर महीने बचत होगी, अगर आपकी एक-डेढ़ लाख रुपये से कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि कंजम्पशन बूस्ट करना चाहते हैं, वह इसके द्वारा मिलेगा।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, आपने रुलिंग दिया था कि सभी लोगों को अपनी-अपनी सीट से बोलना चाहिए।

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): He has taken permission to speak from here.

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): I have the permission.

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, अब मैं कंजम्पशन पर एक और बात कहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में बड़े विस्तार से उन्होंने इसे समझाया। स्वर्गीय अरुण जेटली जी की कुशलता थी, उन्होंने जीएसटी काउन्सिल के द्वारा जीएसटी में क्रांति आई है, उसमें उन लोगों ने कितना बड़ा कंजम्पशन बूस्ट दिया है। ये आंकड़े बजट स्पीच में हैं, आप इस पर जरूर ध्यान दें। मनीष जी, आपको इसमें भी नजर आएगा। जीएसटी के द्वारा टैक्स इन्सिडेंस दस परसेंट कम हुआ है यानी पूरे देश में जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमें मालूम है कि करीब आठ करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कोई जाकर साबुन खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, सभी लोग जीएसटी देते हैं। पहले जो लोग इन-डायरेक्ट टैक्स देते थे, आज जीएसटी के सरलीकरण के कारण दस परसेंट टैक्स इन्सिडेंस कम हुआ है। एक करोड़ लाख रुपये की बचत है, वह भी आपके हाथों में गई है, इससे भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है।

इसलिए जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं। वह कंजम्पशन स्टिमुल्स डिमांड को बूस्ट करना था, उसे हम लोगों ने बहुत सही रूप से किया है। इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है। मनीष जी, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जिक्र किया है।

इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत बड़ी रोचक बात है। वह रोचक बात थालीनोमिक्स की है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो इसे जरूर देखें। थालीनोमिक्स में क्या किया है। उन्होंने दिखाया है कि अगर आप एक वेजिटेरियन थाली खरीदें, पिछले पांच सालों में वेजिटेरियन थाली का भाव क्या है, हमारे हजारीबाग में लोग इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं कि थाली में कितना खर्च हुआ। आप चाहे वेजिटेरियन थाली पच्चीस रुपये का देख लीजिए या नॉ-वेजिटेरियन थाली चालीस रुपये का देख लीजिए। इसमें कोई महंगाई नहीं हुई है, पांच साल बाद भी पच्चीस रुपये की है, जो चालीस रुपये की थी, वह आज भी चालीस रुपये की ही है। यह भी कंजम्पशन बूस्ट है। इस दरम्यान जब आपके खाने-पीने का खर्च था वह स्टेबल रहा, आपकी आमदनी बढ़ती चली गई, आपने खाने-पीने पर जो खर्च किए थे वह आज भी उतना ही है तो आपका कंजम्पशन बूस्ट ही हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने महंगाई और ब्याज दर पर भी अच्छा नियंत्रण रखा है। महंगाई का दर कम रहा है, इंटरैस्ट रेट कम हुए हैं, इससे भी एक बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट हुआ है।

आप पूरे व्यापक डिमांड को समझने की कोशिश करें, उल्टी नजर से नहीं बल्कि आगे की नजर से देखेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि जो इस समय अनिवार्य था, आर्थिक परिस्थितियों के कारण कंजम्पशन को प्रोत्साहन मिले, उस कंजम्पशन को सही प्रोत्साहन मिला है। यह कंजम्पशन की बात हुई, जैसा मनीष जी ने कहा कि अगर हम इसे बुनियादी रूप से समझें तो हमें कंजम्पशन देखना होगा,

इन्वेस्टमेंट देखना होगा, सेविंग देखना होगा, यही सब चीजें हम लोग देखते हैं। हमने कन्जप्शन देख लिया, सही रूप से देखें तो आपको सहमति देनी पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं।

इन्वेस्टमेंट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी महीनता से नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया है और 6500 प्राजेक्ट्स को चिन्हित किया है, उसमें 105 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की बात की है। इससे आपको नजर आएगा कि इन्वेस्टमेंट पर भी हम लोगों का ध्यान है और इस बजट में इस पर ध्यान दिया है।

(1610/SK/PS)

आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देख लीजिए, 37,000 करोड़ फिसकल 2020 में खर्च किया, फिसकल 2021 में कह रहे हैं कि इसे 43,000 करोड़ यानी 16 परसेंट की ग्रोथ देखेंगे। हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम लोगों के लिए पीएमजीएसवाई बहुत जरूरी है। फिसकल 2020 में पीएमजीएसवाई जो खर्च हुआ, वह 14,000 करोड़ था, अब बजट में 19,000 करोड़ रुपये है यानी 36 परसेंट ग्रोथ है।

अब देखिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जा रहा है। इन्डस्ट्रियल कोरिडोर में जहां 950 करोड़ रुपये दिए गए थे और अब 1200 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं यानी 26 परसेंट ग्रोथ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में देखिए कि कितना जोर दिया जा रहा है।

विमानन क्षेत्र, एयरपोर्ट्स पर उड़ान कितना सफल हुआ है। यहां माननीय निशिकांत दुबे जी बैठे हैं, उनको मालूम है की देवघर का एयरपोर्ट किस रफ्तार से बन रहा है। बिद्यूत जी जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन रहा है। वी.डी. राम जी बैठे हैं, डाल्टनगंज पलामू में बन रहा है। हजारीबाग में एयरपोर्ट बन रहा है। दुमका में एयरपोर्ट बन गया है, सुनील सोरेन जी होते तो बहुत खुश होते। झारखंड में छः एयरपोर्ट बन रहे हैं। कोई कल्पना भी कर सकता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में छः एयरपोर्ट बनेंगे। पूरे देश में एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है। जेवर में बन रहा है, मोपा में गोवा का एयरपोर्ट बन रहा है। अरविंद जी आपके ही क्षेत्र में ट्रांस हार्बर पाइपलाइन लिंक में विशाल एयरपोर्ट बन रहा है। सब लोग गदगद हैं कि एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट बने जा रहे हैं। 'उड़ान' स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे देश में हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे। हवाई चप्पल वाले न सिर्फ हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, बल्कि बुलेट ट्रेन में भी बैठने वाले हैं। हम बुलेट ट्रेन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, तेजस को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब राजधानी ट्रेन रांची, बड़काधाना, हजारीबाग, कोडरमा से दिल्ली आएगी, हम इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करके सब जगह प्रयोग कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, 450 गीगावाट्स की रिनुएबल एनर्जी आ रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री को विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 22,000 करोड़ रुपये बजट में खास प्रावधान किया है। इसके द्वारा 1 लाख करोड़ का लैवरेज बनाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर सकते हैं। मनीष जी, यह दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट पर कितना जोर दिया जा रहा है।

अब मैं जरा सस्टेनेबिलिटी पर आता हूं, ग्रीन इकोनॉमी पर आता हूं। 'स्वच्छ भारत अभियान' में सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इकोनामी के लिए जो किया जा रहा है, वह भी इस बजट में है। 'स्वच्छ

भारत अभियान' कुल मिलाकर 'ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन' के लिए 30,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रीवर डैवलपमेंट के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रसोई गैस, क्लीन गैस मतलब साफ हवा हो, के लिए भी हमने बहुत लोगों को गैस सिलेंडर दिलाया है। अब तक 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिल गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा और ठोस कदम लिया है जो खासकर दिल्लीवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह है 'नेशनल क्लीन एयर मिशन' में 4,000 करोड़ रुपये दिए हैं। झाड़ू ने पॉल्युशन नहीं साफ किया, दिल्ली में झाड़ू कुछ काम नहीं आया। ... (व्यवधान) दिल्ली जो पहले गैस चैम्बर था, आज भी गैस चैम्बर है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली को झाड़ू से साफ कर दो। ... (व्यवधान) झाड़ू को दिल्ली से साफ कर दो, दिल्ली को स्वच्छ बना दो। ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, he is talking about Delhi Elections. ... (Interruptions)

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): प्रोफेसर साहब, दिल्ली के हर बाग में, हर गुलिस्तां में गुलाब खिलेंगे और कमल भी खिलेंगे। ... (व्यवधान) यह तो होने ही वाला है। ... (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा इनीशिएटिव रहा है, ईज ऑफ लिविंग। इसके सरलीकरण के लिए क्या प्रावधान बजट में किए गए हैं।

(1615/MK/RC)

यह भी अद्भुत है। मनीष जी आपने जे.ए.एम. का जिक्र किया है। आप देखिए, डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर आज के समय कितने लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। मैं आपको संक्षेप में एक छोटी-सी कहानी बताना चाहता हूँ। हजारीबाग में टाटीझरिया हमारा प्रखंड है। निशिकांत जी को अच्छे से मालूम है। गिरिडीह की ओर बढ़ते हुए टाटीझरिया पार करते हुए आप विष्णुगढ़ पहुंचते हैं। टाटीझरिया में हम एक बार चुनावी प्रचार में निकले हुए थे। हम जुलूस में चल रहे थे, नारे दिए जा रहे थे, ढोल बज रहा था, हंगामा चल रहा था। एक वृद्ध महिला मेरे पास आईं। यह पांच-छः साल पहले की बात है। वर्ष 2014 के चुनाव की बात है। उन्होंने कहा आप बड़े नेता हैं, आप जुलूस में जा रहे हैं, आपके साथ ढोल बजाने वाले लोग हैं, नारे लगाने वाले भी लोग हैं, आपके साथ झंडा वाले भी लोग हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी मुट्ठी में सिर्फ एक फूल है। मैं आपको फूल दे देती हूँ, लेकिन आप मेरा जो वृद्धा पेंशन है, वह मुझे दिलवा दीजिए। मैं बड़ी खुशी से आपको बता सकता हूँ कि आज के समय उस महिला को वृद्धा पेंशन डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर के तहत सीधा उनके खाते में मिल रहा है। इसके द्वारा नौ लाख करोड़ ऐसी महिलाओं के बैंके के खाते में गया है और उसकी एक लाख सत्तर हजार करोड़ की बचत हुई है। ऐसी कितनी महिलाएं थीं, ऐसे कितने वंचित लोग थे, जिनको हम लोगों ने डायरेक्ट बनेफिट, ईज ऑफ लिविंग, सरलीकरण द्वारा लाभ पहुंचाया है।

आप जीएसटी को देखिए, जीएसटी में कितना सरलीकरण हुआ है। जीएसटी में 20 परसेंट टर्न अराउंड टार्गट बचाया गया है। इसलिए, जीएसटी में भी सरलीकरण हुआ है, ईज ऑफ लिविंग हुआ है। सब लोग आसानी से अपना पैसा देते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन होता है, किसी को कोई तकलीफ

नहीं होती है, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है। जो इंस्पेक्टर राज था, उसे हमने दूर करके सीधा अपनी जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के राज में उन पर विश्वास करके हम लोगों ने ये सब सुविधाएं पहुंचा दी हैं।

अभी इस बजट और बजट के पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स कट आया था, उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए कि इज ऑफ लिविंग और सरलीकरण में क्या किया गया है। एकजम्पशन और डिडक्शन, मनीष जी को अच्छी तरह से मालूम है, वे एडवोकेट हैं। आप जाकर टैक्स कोड को देखिए, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स कोड को देखें या इंडिविजुअल टैक्स कोड को देखें कि आज वह कितना मोटा हो गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सरलीकरण के लिए 100 एकजम्पशन और डिडक्शन में से 70 को हटा दिया, 30 को छोड़ दिया और आपको एक रास्ता भी दिखा दिया। अगर आपको कम टैक्स देना है, चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें या इंडिविजुअल टैक्स की बात करें, इतना सरलीकरण हो गया है कि आप अपना 5-10 परसेंट टैक्स भी बचा लीजिए और टैक्स फॉर्म एक पन्ने में भरकर आप उसको ऑटोमेटिकली जाकर दे दीजिए। अब सीए की भी जरूरत नहीं है... (व्यवधान) अब निशिकांत जी क्या करेंगे? सरलीकरण हो गया है, एक सिम्प्लीफिकेशन हुआ है, जिसके द्वारा इज ऑफ लिविंग जो हम लोगों की एक बहुत बड़ी सोच हैं, जो एक न्यू इंडिया की खूबी है, गुण है, उसी इज ऑफ लिविंग की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं।

अब मैं डिजिटल पेमेंट्स पर आता हूँ। आप सभी लोग माहिर हैं। आप सबके पास स्मार्ट फोन है। आप चाहे अपना भीम का ऐप इस्तेमाल करें या यूपीआई का उपयोग करें, आप देखिएगा कि कितनी आसानी से सबको, बस एक एड्रेस दीजिए, उसके बाद ओटीपी आता है, आप अपना ओटीपी स्वीकार कीजिए और फटाफट सबको भुगतान कर दीजिए, चाहे वह रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो चाहे किसी सी छोटे व्यापारी को भी देना हो, सबको सरलीकरण कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जी की सोच को देखिए, कितनी बारीक सोच है कि उस ठेले वाले के बारे में भी सोचकर यूपीआई को प्रोत्साहन दिया है और जैसे उन्होंने खुद कहा है कि आज के समय हर महीने दो लाख करोड़ रुपये का यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्सन हो रहा है। अगर यूपीए सरकार यह कहती है कि हम सब कर रहे थे तो क्या आपके समय में दो लाख करोड़ रुपये का डिजिटल पेमेंट से ट्रांजैक्सन हो रहा था? नहीं हो रहा था। 38 करोड़ जन-धन खाते खुले थे? नहीं खुले थे। आज के समय 121 करोड़ जो आधार के कार्ड आए हैं, वे आपके समय में नहीं थे। जब एक सुदृढ़ तरीके से, प्रतिबद्ध होकर, एक सोच लेकर, एक नई ऊर्जा से और एक नई विचाराधारा से भारत का निर्माण करते हैं तो ये परिणाम आते ही चले जाते हैं और ये हम लोग इस बजट के द्वारा और अपने काम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं।

(1620/SRG/YSH)

Now, I will come to a somewhat more technical matter on which those of us who are interested in financing are very, very focused on right now. If we are going to build a USD 5 trillion economy, do we have the ability to finance that USD 5 trillion economy? Do we have a long-term financial architecture in place

that can enable us to generate an investment rate of, let us say, 30-35 per cent which is required to achieve USD 5 trillion economy? Now, think about it. If you have a USD 5 trillion economy at an investment rate of let us say 33 per cent, through our financial system, from the savers to the people who will actually make investments, we have to intermediate USD 1.5 trillion. That is the kind of financial system we have to build. That is what is required for a USD 5 trillion economy. So, we have to intermediate USD 1.5 trillion, let us say, a trillion dollars of debt financing and USD 500 billion of equity financing. That is the kind of financial architecture we have to build, so we can have sufficient financing capacity to achieve USD 5 trillion economy. Now, please look at the Budget and understand with what felicity and with what sophistication we are actually establishing the pillars for this kind of long-term financial architecture. I will draw your attention to four or five important matters that are well worth our consideration.

I will first come to the Insolvency and Bankruptcy Code. The Insolvency and Bankruptcy Code is a landmark legislation and again we have to thank Shri Arun Jaitley Ji who piloted it, worked on it and amended it; this has, of course, been amended twice.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): You were also part of that process.

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Yes, I was also a part of the process. It was my great good fortune Professor Sahab to be part of that. If you look at what the Insolvency and Bankruptcy Code is, these are the data that have been provided to us in the Finance Committee as well. Professor Sahab you have that data as well. So, I will draw your attention to those. If you look at the recoveries that have come through under the Insolvency and Bankruptcy Code, today the recoveries are already at about Rs. 3.6 lakh crore. More than 50,000 or 60,000 cases have come into the Insolvency and Bankruptcy Code. What experts tell us is that it is not simply what is coming into NCLT that is of importance, but it is what is not coming into NCLT that is even more important. That is because, as has been said famously, 'the fear of hanging concentrates the mind wonderfully'. So, when you are in a situation when you are looking at impending bankruptcy filing, that forces creditors - operational as well as financial - equity holders, everybody to come together to resolve matters before their hanging. So, what is not happening, which we do not see in the data, but I can tell you from anecdotal

evidence and in my conversation with leading industrialists and investors that because of the Insolvency and Bankruptcy Code, which is a landmark legislation, the resolution of these kinds of problems is happening at a far faster pace than ever before. ...(*Interruptions*). There is a lot of global data on what the typical haircut is in the bankruptcy process. Typically, those haircuts can range from 30-50 percent, be it a resolution or a liquidation. Liquidation can be less than 10 per cent and our recovery is absolutely in line with global experience in this matter. ...(*Interruptions*). As I said, previously, there was no recovery and if the recovery was happening, it was happening five, six or ten years later. Now, we have already got Rs. 3.6 lakh crore of recovery and it is happening on an average in 1.6 years because of the timelines that we have imposed in Insolvency and Bankruptcy Code. So, the velocity of resolution has gone up which is extraordinarily important.

Now, please note this, the World Bank has said that with the Insolvency and Bankruptcy Code, what has happened is that the quality of the resolution process in India - remember we are an economy with GDP per capita of USD 1800 - now matches that of OECD countries, that is rich countries with GDP per capita of USD 30,000-50,000. That is what we have achieved not just through this legislation, in which all of you have been participants and we thank you for that, but also I will commend the Insolvency and Bankruptcy Code and the Ministry of Finance for their continuous efforts to fine-tune and improve upon this legislation. This is a remarkable achievement for the country to have achieved what we have through the Insolvency and Bankruptcy Code and that is a crucial building block for creating a financing system that can fund a USD 5 trillion economy.

(1625/RPS/RU)

Now, resolutions happen very quickly. We move assets from those who cannot fund these assets going forward to those who can fund these assets going forward as has happened with Electrosteel. हमारे यहां झारखण्ड में इलेक्ट्रोस्टील प्लांट है, आज वह वेदान्ता के हाथ में है, वेदान्ता उसे चला रही है। जो वहां रोजगार का सृजन हुआ था, इसके कारण आज वह सुरक्षित है। आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। अगर आप बोकारो जाएं तो बोकारो में एक समस्या थी, लोग बहुत चिन्तित थे कि यह इलेक्ट्रोस्टील का विशाल प्लांट बन्द हो जाएगा। आज एनसीएलटी के कारण वह प्लांट कायम है, अच्छी तरीके से चल रहा है और सभी लोगों का रोजगार सुरक्षित रहा है। अब मैं बैंकों पर आता हूँ ...(*व्यवधान*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): How much more time do you require to conclude?

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): जितना समय आप लोग देना चाहें, दे दें बोलने के लिए बहुत कुछ है। जब मंत्री जी ने इतनी लम्बी बजट स्पीच दी है तो मुझे भी कुछ समय दीजिए... (व्यवधान) । I am not repeating any point.

HON. CHAIRPERSON: Try to conclude within ten minutes.

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): आज आप बैंकों की हालत देखिए। पिछले पांच-छः सालों से हम लोग बैंकों में लगे रहे हैं। पहले 'इन्द्रधनुष' आया और हम लोगों ने बैंकों का पूरी तरीके से रिकैपिटलाइजेशन कर दिया, साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये दिए। फिस्कल डेफिसिट को हम लोगों ने कंट्रोल में रखा है, तब भी हमने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये बैंकों में डाले हैं, जिससे जो आपने एनपीए किए थे, जो आप कह रहे थे कि वर्ष 2008-2009 में आप लोगों ने बहुत बचाया था, क्या बचाया आपने, आपने तो एकदम डुबा दिया था। फिस्कल डेफिसिट छः प्रतिशत बढ़ गया था, जो बैंकों का एनपीए था, जब हम लोगों ने आकर उसकी एसेट क्वालिटी रिव्यू किया और देखा कि उस एसेट की क्वालिटी क्या है, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा निवेश हुआ, आप जिस निवेश की बात करते हैं, अगर आप उसे देखें तो वे सब एनपीए निकले। ... (व्यवधान) फिस्कल डेफिसिट छः प्रतिशत तक चला गया था, रुपया एकदम डूब गया था और एनपीए 11 प्रतिशत या 12 प्रतिशत हो गया था। अब हम लोगों ने उसे किसी तरह से कंट्रोल किया है और अब एनपीए डिक्लाइन होते चला जा रहा है। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के तहत उस एनपीए की रिकवरी हो रही है। बैंकों का कंसॉलिडेशन हो रहा है। दस बैंक अब चार बैंक बन रहे हैं। हमारे बैंक्स मजबूत, दुरुस्त और ग्लोबली कम्पिटिटिव हो रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनना है तो हमारा फाइनेंसिंग सिस्टम ग्लोबली कम्पिटिटिव हो और हमारे बैंक्स ग्लोबली कम्पिटिटिव हों।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, विपक्ष के माननीय सदस्य पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर पर हमें गर्व है, साथ ही हमें अपने प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्व है। आज के समय हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन, उनके मल्टिपल्स पूरे विश्वभर में नम्बर वन हैं। हमें प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे यहां इतने बढ़िया, ग्लोबली कम्पिटिटिव बैंक्स हैं और उनको हम पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने बिलियन-राज और क्रोनी कैपिटलिज्म समाप्त किया है, जनता का राज बनाया है। हम आंट्रेप्रिन्योरियल कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें, आज के समय जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल है, जो एट रिस्क इक्विटी कैपिटल हमारे नए-नए आंट्रेप्रिन्योर्स को और स्टार्ट अप्स को जाती है, जो यूपीए के समय में सालाना दस बिलियन डॉलर थी यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपये थी, आज बढ़कर तीन गुना ज्यादा हो गई है। जो पहले दस बिलियन डॉलर थी, वह बढ़कर 35 बिलियन डॉलर हो गई है। ऐसा इसलिए हो गया, क्योंकि हमारे देश में विश्वास है, हमारे आंट्रेप्रिन्योर्स हैं। यही तो हमारी पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी को फाइनेंस करेगा।

अगर आप एफडीआई को देखें, वह भी बढ़कर चालीस से पचास बिलियन डॉलर हर साल चल रहा है। इस बजट में कुछ ठोस कदम लिए गए हैं, डेट ईटीएफ के लिए बॉण्ड, मार्केट के लिए बॉण्ड्स, इंडिसेज में डाला जाएगा, वहां भी हमारी फाइनेंसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और सॉवरेन वेलथ फण्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्च, 2024 तक टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, जिससे वे जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्ट करते जाएं।

जहां तक एनबीएफसीज की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 10,000 करोड़ रुपये का स्ट्रेस्टेड एसेट्स का फण्ड आएगा, आरबीआई की प्रूडेंशियल रेगुलेशन और टाइट होती चली जाएगी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आरबीआई के पूरे रेगुलेशन में ले आया जाएगा। हमें एनबीएफसीज को सुदृढ़ करना था, दुरुस्त करना था। ... (व्यवधान) अभी कोऑपरेटिव्स के लिए किया गया है। ... (व्यवधान) आप इसे न भूलें कि हम अपने सेवर्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनको हमने सेफ्टी का वचन दिया है, वादा किया है कि हमारे डिपॉजिट्स और हमारा बैंकिंग सिस्टम एकदम मजबूत-दुरुस्त है और जो एक लाख रुपये का कवर था, आज उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। ... (व्यवधान)

(1630/IND/NKL)

मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम पांच ट्रिलियन डॉलर की बात क्यों करें, क्योंकि पांच ट्रिलियन तो हो ही रहा है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अब हमें पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो हो ही जाएगी, अब हमें दस ट्रिलियन इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। मनीष जी, आप पीछे देख रहे हैं। विपक्ष पीछे देख रहा है और हम आगे दस ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखें कि दस ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने किस कुशलता से क्या-क्या इस बजट में लिया है, यह मैं आपको बताता हूँ। 'Fund of Funds' द्वारा हमारा स्टार्ट-अप इको सिस्टम है, उसके तहत वेंचर केपिटल को प्रोत्साहन देंगे, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन को तैयार किया गया है। मैं आईआईटी से हूँ। मनीष जी, आप एडवोकेट हैं और मैं इंजीनियर हूँ। मैं आईआईटी, दिल्ली से हूँ। आईआईटी में हम यही देखते हैं कि हमें सरकार से ऑन दि फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का सहयोग मिल रहा है। मैं सभी इंजीनियर्स की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने क्वांटम कम्प्यूटिंग जिसमें सुपर कम्प्यूटर, सिस्टम के लिए आपने सालाना 1600 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे हम ग्लोबल लीडर्स, सेमी कंडक्टर ऑन नेशनल क्वांटम कम्प्यूटिंग बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अब बहुत उम्र हो गई है और हम गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। अब हमें वापस इंजीनियर बनना चाहिए। जब क्वांटम कम्प्यूटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हम पहले जो कोडिंग करते थे, वह वापस करने चले जाएं। इसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशंस एमिनेंस को प्रोत्साहन मिल रहा है, ज्यादा फंडिंग मिल रही है। हॉयर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथोरिटी है, उसे दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। हम लोगों ने ईसीबीज और एफडीआई अपनी टॉप यूनीवर्सिटीज को दिया है, ये प्रोत्साहन बहुत अच्छा है। जो डेटा हमारा न्यू ऑयल है, जो

हम लोगों को एआई के लिए अपने ही देश में घरेलू तौर पर एक बहुत बड़ा एसेट बनाना है, वह डेटा सेंटर पार्क्स को भी हम लोग इस बजट द्वारा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम लोगों को आगे की तरफ देखना चाहिए - चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। मनीष जी, आप डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, यह बिल्कुल सही है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दस ट्रिलियन डॉलर के लिए हमारी क्या सोच है, क्या हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, इस बारे में मैं अपनी सोच बताना चाहता हूँ। हमें फ्यूचर में जिस प्रकार ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन पर पिछले 20-25 साल ध्यान दिया, उसी तरह हमें आगे कम्पेटिटिवनेस पर ध्यान देना है कि पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर में हमारी कम्पनीज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं हैं, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कम्पेटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी पर यानी क्लीन और ग्रीन इकोनॉमी हमें बनानी है। We must go for the green frontier, the frontier in terms of both competitiveness and sustainability. अगर हम वहां पहुंच जाएं, तो हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, जो हम शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अगर हम ग्रीन फ्रंटियर की तरफ बढ़ें, तो ये कदम हमें जरूर दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं।

महोदय, मैंने अपनी बात महाकवि की कुछ पंक्तियों के साथ आरम्भ की थी। मैथिलीशरण गुप्त जी हमारे क्षेत्र के थे। जिस महाकवि की पंक्तियां मैं अब कहना चाहता हूँ, उससे शायद आप लोगों को खटास हो, क्योंकि वे हमारे दल के हैं। वे न सिर्फ महाकवि हैं, बल्कि वे देश के महान प्रधान मंत्री भी रहे हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं।... (व्यवधान) प्रोफेसर साहब, आपने शायद उनकी कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं उनकी दो पंक्तियां सुनाता हूँ और आप मेरे साथ सहमत होंगे, कि वे महाकवि हैं। अटल जी ने हमें प्रोत्साहन दिया। उनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं :

“लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा
कदम बढ़ रहे हैं, कभी नहीं रुकेंगे।”

ये अटल जी की पंक्तियां हैं। इस प्रकार से हम नए इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी न रुकेंगे और दस ट्रिलियन हासिल करेंगे।

(इति)

(1635/KSP/ASA)

1635 hours

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, I would like to begin by thanking the Finance Minister for including Adichanallur as one of the five archaeological sites that would be developed as iconic sites with onsite museums and this is particularly significant to the Tamil Civilization as the findings date back to 690-905 BCE.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): At the time of Budget presentation, you were opposing it.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Not Adichanallur.

But I would also like to draw the attention of this House to a point made by the Finance Minister in her Budget Speech. She has gone out of her way to rename the Indus Valley Civilization, as we know it, as the Saraswati-Sindhu Civilization. Even scholars, scientists, archaeologists who have been working for decades on this subject have not been able to come out with any conclusive or concrete proof about the existence of the mythical Saraswati River and what the Indus script says. The Finance Minister has followed the footsteps of some people who actually would like to push the Vedic Age to 10,000 years BCE and to say that the River Saraswati mentioned in the Rig Veda is the same river on which the Indus Civilization flourished which is farthest from the truth. This is a blatant attempt to rewrite history as the BJP has always attempted to do and they always love to give us history lessons as we have been seeing regularly.

The Government not only attempts to paint contemporary India saffron, but it wants to go back in history and paint the past saffron too. Indologists like Asko Parpola and Iravadam Mahadevan have categorically said that the Indus Civilization is the Dravidian Civilization and the Murugan worship had gone from South India to the Indus Valley. Moreover, the Minister has made a statement that deciphering of hieroglyphics of the Harappa Valley has happened. I would like to tell her that there is no conclusion about it, people are still debating about it and nobody has actually been able to really read what is there. So, I humbly request the Government and the BJP to leave things like this to the scholars and historians. I would again request the politicians to stay out of this and stop using their versions of religion to rewrite what India is.

India had very high hopes from this Budget. But I fail to see how any of the proposed allocations will boost the income and enhance the purchasing power of the people. A newspaper headline read, "Not a full thali, only morsels for everyone". This is what the long Budget left us with.

They have been talking about the five trillion-dollar economy and Mr. Jayant Sinha has become very ambitious, he has been talking about US 10 trillion-dollar economy. We have to start making allocations for equity funding for this every year. That has not happened and we cannot see it anywhere in the Budget and today, in real terms, the growth is only 5 per cent of GDP.

(1640/KKD/RAJ)

At this rate, how are they going to be able to achieve what they are posing to us?

The GST has been hailed as a great key reform since Independence, but sadly, the model and implementation have been flawed since the very beginning. Many of us supported it hoping that it would bring ease of business. But it has not brought ease of business. It actually closed down many industries. The entire industry especially small traders are in distress. The system has got several glitches. It was evident when the Finance Minister summoned the Infosys for explanation.

The Finance Minister in the Budget said: "Our Government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022." The agriculture sector has just grown by two per cent in the first quarter of this year as compared to 5.1 per cent growth in the same quarter in the previous year.

The RBI Annual Report shows that the contribution of agriculture in the last five years has halved. The NITI Aayog Report says that you need a 14 per cent growth to double the farmers' income. At this pace, how can we double the farmers' income?

The National Crime Records Bureau Report says that 10,349 people working in the farm sector have ended their lives in 2018. I would like to say that it is not because nature has been brutal to them. The crop insurance scheme, which had to protect them, protect their crops and livelihoods failed to do so. It is a shame that many farmers in Tamil Nadu received as little as Rs 4, Rs. 5 and Rs. 10 as crop insurance. This was highlighted by our party leader, M.K. Stalin in the Tamil Nadu Assembly that the farmers got as little as Rs. 4, Rs.5 and Rs.

10 as crop insurance. The farmers have been paying around Rs. 610 per acre as premium for insurance and spending more than Rs. 30,000 per acre for cultivation; and after the loss of the crop, the insurance amount sanctioned to them is highly insulting. Three years and seven crop seasons after, it was rolled out. The Centre's flagship farm insurance scheme remains behind its own target, and its outreach is as low as 26 per cent.

The least the Government could have done is to provide immediate relief to the farmers by waiving off the farmers' loans, which has been their demand for a very long time, and we saw the farmers protesting in Delhi also.

The UPA Government in 2008 waived off more than Rs. 72,000 crore of farm loans, which provided the much needed relief to the farmers as well as the rural economy. Our friend, Mr. Sinha here is talking about old-age pensions reaching the old people all over the country. If he comes with me to my Constituency, I can show him that everyday 100s of old men and women come with petitions; and they are waiting for years to get their old-age pensions. I really do not know where this amazing blissful place is, which he is talking about ...*(Interruptions)* You come with me.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Sinha, it is a fact ...*(Interruptions)*

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): One of the biggest schemes that has the capacity to actually put money in the hands of the people is MGNREGA. It was mentioned here by the speaker from Congress Party, Shri Manish Tiwari-ji, that there has been a steep fall in the money allocated for MGNREGA.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is demand-driven, Madam.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): MGNREGA's financial statement as of 26th January, 2020 has shown that more than 96 per cent of the allocated money has already been spent or is needed to pay pending dues. Less than Rs. 2,500 crore is left to sustain the scheme and nearly 15 States are already in the red.

A minimum of Rs. 96,000 crore is needed to implement MGNREGA in the coming year. The national average wage of MGNREGA worker is around Rs. 178 per day, less than half of the amount of Rs. 375 per day minimum wage recommended by the Labour Ministry Panel. I request the Government to increase the wages, at least, to Rs. 350.

(1645/RP/VB)

Now, I am coming to the Fifteenth Finance Commission. DMK has always been at the forefront on the struggle for federalism and decentralisation. It is entirely with this objective that I wish to highlight the unfair wages in which the Fifteenth Finance Commission tilts the fiscal scale in Centre's favour. The Fourteenth Finance Commission had promised that there will be incentives for States that undertook measures to control population explosion. But the Fifteenth Finance Commission is using demography as the sole benchmark.

The Fifteenth Finance Commission has the 2011 Census as the sole criteria for the population but has reduced the weightage of the population to 15 per cent from earlier 27.5 per cent. It is extremely unjust to punish States like Tamil Nadu and the Southern States that have achieved a neutral net reproductive rate target.

The Fifteenth Finance Commission has granted Rs. 4,025 crore to Tamil Nadu as devolution grant which is only a temporary relief. We need a permanent solution and justice to be done to the Southern States which are highly affected by this.

In July, 2019, the Terms of Reference of the Finance Commission were amended to include "allocation of resources towards defence and internal security imperatives". Experts have noted that this is an unprecedented move to raise funds for the country's defence and security from the States. This is erroneous and unfair as defence comes under the Union Government. Why should the States pay for something which is entirely under the Centre's purview unless you intend to move Defence to the Concurrent List?

We have gone from the times when the Union Government would finance States and incentivise good schemes. Now, as far as the programmes run by the Centre and the States, the Centre has been consistently reducing its contribution which is very unfair.

You always said that Make-In-India will create jobs. Now, you are saying 'Study in India' through Ind-SAT. Are we making sure that people will come to India and study here? Are we making the Universities safe for students? Recently, we sent back a German student who was studying in the IIT Madras because he participated in the anti-CAA protest. The way the students were being attacked in our University campuses like JNU and Jamia, how can we

convince the world community that our Universities and colleges are a safe place for the students to study? Here, I would like to quote John. F. Kennedy who said: "Those who make peaceful resistance impossible will make violent revolution inevitable."

Now, I am coming to disinvestment. "Listing of companies on stock exchanges discipline a company and provides access to financial markets", this is what the Finance Minister said in her Budget speech. I would like to say that, actually, the LIC was nationalised only because there were unfair trade practices. That is why, it was brought under the public sector. In 1990, the insurance sector was opened to the private sector. LIC has been doing remarkably well among the other insurance companies. There is no reason to disinvest the LIC other than the Government's desperate attempt to raise money through disinvestment as they are failing to realise their tax revenue targets. I would like to borrow the words of *dada* who keeps saying: "Do not sell the family silver." That is exactly what we are doing. These are very desperate times. I would also like to say that these private companies do not have any commitment. They are not legally bound to give reservation in their companies or industries. The more you disinvest and the more you give away the public sector companies to the private hands, the number of job opportunities given to the weaker sections of the people will be reduced. The reservation is meant to do justice to the people who have been ignored for centuries.

(1650/RCP/PC)

That has been cut drastically. This is just not only a wrong economic move to disinvest but also it is against social justice. I think, you are hacking at the roots of social justice in this country by disinvesting.

We were talking about unemployment. I think, it is often being quoted that it is at 45-year high. But it is very alarming to see that 22.5 per cent of the urban youth are unemployed and it is worst in the rural sector.

I would like to bring to your notice what happened recently in Salem district in Tamil Nadu. A woman who lost her husband could not find employment. She sold her hair for Rs. 150 to feed her three children and then she said, "I do not have anything more to sell, to support my family." This is the state this country is in and we are talking about 10 trillion-dollar economy.

Budget allocation to welfare schemes is a key measure of our commitment to development goals. Under the National Programme of Mid-day Meals in schools, the Budget Estimates for 2019-20 was Rs.11,000 crore, but the Revised Estimates is Rs.9,912 crore. In September 2019, a journalist was booked for conspiracy after he reported that only *rotis* and salt are being served as mid-day meal in a Government school in Uttar Pradesh. In this situation, how can the Government justify Rs.1,088 crore lesser funds for this project? For the umbrella ICDS scheme, the BE 2019-20 was Rs.27,584 crore but the RE 2019-20 was Rs.24,995 crore. There is a decrease of Rs.2,589 crore. This lowering of spending for the ICDS is not justified when India has the highest number of under-five deaths according to a UNICEF Report of 2018.

I would like to talk about the MSMEs. With the introduction of GST and demonetization, the twin attack on the Indian economy, the MSME sectors were challenged. According to a Government policy note of the Government of Tamil Nadu, the AIADMK Government, which is your ally, more than 50,000 MSMEs have been closed and five lakh jobs have been lost in Tamil Nadu. MSMEs are reeling under the credit crunch created by demonetization. Banks are lending loans to MSMEs at the rate of 11 per cent. Since the repayment has been computerized, even if there is a small error in repaying returns, the MSMEs are declared as NPAs. They have to clear all the dues to be declared as non-NPAs. The Non-Banking Financial Corporations are apprehensive to lend money to the MSMEs and are charging an interest rate of 15 per cent to 17 per cent which is too high. The Debt Service Coverage Ratio parameter, which is used to assess the ability to repay the loans by the firms, is same for the MSMEs and the corporates. This should be rationalized according to the needs of the MSMEs.

The matchbox industry is particularly prominent in my constituency, Thoothukkudi. They have been demanding that the GST on matchboxes to be reduced from 18 per cent to 5 per cent. It is because they are partly handmade. I myself have written to the Finance Minister. They have also come and met her and requested her to give them reduction in GST. I would request the Finance Minister to kindly consider this because the entire sector is in distress and they are closing down.

(1655/SMN/MM)

In 2019, over four thousand hours of internet shutdown has cost India over Rs. 9300 crore.

While the Government continues to deny that there is no negative impact on tourism, there has been an 18 per cent fall in the tourists in December, 2019 alone resulting in heavy loses for both hospitality and the tourism sectors.

Several world leaders have also expressed displeasure over CAA and Kashmir shutdown and they have even cancelled their visits to India. Recently, several investment firms are reducing their Indian Government bond holdings on concerns over the CAA and also diverting funds into other countries. Certainly, the combination of the abrogation of Article 370 and the CAA implementation is forcing the world to take a step back from India. Is this the India we aspire and strive to be? Everybody is fond of quoting here.

“Iyatralum Eettalum Kaathalum Kaatha Vahuthalum Valla tharasu.”

Generating revenue justly, increasing its earnings to the exchequer, protecting the same and distributing it fairly are the attributes of a good Government.

But unfortunately, I cannot say these things for this Government. Thank you.

(ends)

1656 hours

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I rise here today to speak on the Union Budget 2020-2021 in this august House and in this temple of democracy.

Before I start my speech, I bow down to every citizen of this country. I bow down to their indomitable will and to their unsinkable determination. I bow down to their continuous struggle in pursuit of peace and harmony. I pay my respects to the draftsmen of our democracy, the architects of the Constitution, the Members of the Constituent Assembly who drafted this holy book which is the foundation of this great Republic.

Let us remember all those who helped to shape the dream, the dream of an Independent India. I bow my head to all of them - from Netaji Subash Chandra Bose to Matangini Hazra, from Binoy Badal Dinesh to Khudiram Bose, from Maulana Abul Kalam Azad to Dr. B.R. Ambedkar, from Gandhi ji to Rabindranath Tagore, from Bagha Jatin to Jatin Das, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, from Ishwar Chandra Vidyasagar to Raja Ram Mohan Roy.

Sir, the Finance Minister, a couple of days back, delivered a two- hour-forty-minutes long Budget Speech. The nation watched her eagerly with aspirations in their hearts and optimism in their minds. The 1.3 billion people, 130 crore Indians waited to hear how the BJP Government will care for them and for their lives, how the Government understands their problems and aspirations, how the Government is going to address the grave concern of unemployment, how the Prime

Minister would spur economic development. We saw the Finance Minister speaking incessantly. She used couplets, poems and quotes in her Speech. We saw the Prime Minister and the Members of the Treasury Benches thumping the desks at least 30 times in these 160 minutes. We saw the Finance Minister losing her breath. We were concerned. We saw her taking a pause. We saw her regain her energy. We saw her back on her feet once again to project hard numbers, once again to hear the truth. We all waited. We waited patiently and eagerly. We waited Sir and then her Speech ended. What did the 130 crore Indians achieve at the end of the Budget Speech? What did the middle class, the lower middle class, the minority, the SC, ST, OBC and this country get after the end of this Budget Speech? A big zero -- zero economic development, zero caring and zero aspirations.

Sir, the Government at the Centre talks every now and then about simplifying the tax system wherever they go and from the last six years, they have been consistently saying that they are trying to simplify the tax system and eliminate tax terrorism.

(1700/VR/SJN)

But, Sir, what the Finance Minister said in her 160 minutes long speech, forget about the common Indians, even the eminent economists and the global experts of the nation or the world failed to understand and were left rankled. No wonder, the Government clearly went ahead in its endeavour to present this year's Budget with a clear motto. What is the motto? It is: "If you cannot convince them, confuse them". So, there was a clear motto when she presented the Budget.

Seemingly, the Budget has three pillars which the Finance Minister laid down and explained. What are these three pillars? The three pillars, she said, are one, Aspirational India; two, Economic Development; and three, a Caring Society. Now, if you are to compare what the actual situation is on the ground you will see that aspirations have been taken over by autocracy. There is no economic development. You will see economic misery on the ground. People are losing jobs. Manufacturing units are shutting down every now and then and GDP slips below 4.5 per cent. Then, there is no caring. Caring has been taken over by cruelty. The Ruling Party at the Centre is spreading and pushing venom and hatred in the society just for their own vested interests and petty political benefits.

Sir, the Budget 2020, as the Member of the ruling dispensation has very rightly said, is historic. I agree with him. It is historic. The Budget is historic in so many ways. It is historic because it was 160 minutes long. It is historic because you got a 11-year low GDP rate. It is historic because there is a 17-year low in investments. It is historic because there is a 15-year low in manufacturing. It is historic in four-year low agriculture. It is historic because there is a 8-year low in household financial savings. It is historic for so many more reasons. I only mentioned a few.

Since we are discussing history, I would also like to mention that this is the first time that the country is witnessing that an institution like the Reserve Bank of India has someone at the helm of affairs, who has a major in History, and the ones, who are fit enough and credible enough to lead that institution, are now tucked into the pages of history. This is the BJP Government for you.

Instead of making such historic records, maybe the BJP Government could have listened to the former Chief Economic Advisor, Dr. Arvind

Subramanian, who compared India's worst growth in 30 years to the Great Depression of 1929. He said and I quote him:

"It is India's great showdown where the country seems headed for an Intensive Care Unit".

1703 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

If you do not agree with Dr. Arvind Subramanian, listen to the former RBI Governor, Dr. Raghuram Rajan. He said that the successive shocks of demonetization and GST have seriously impacted India's growth. It has fallen off when growth in the global economy is peaking up. This is what Dr. Raghuram Rajan said.

If the above two gentlemen's views are unsuitable to the Ruling dispensation, let me give you a third view, and they are very fond of this person, who I am about to quote. Who is that person? He is the former Chief Minister of Gujarat and a current Member of this august House. He said and I quote him again:

"Till you do not have a proper IT infrastructure, GST will never be successful."

This was said, that is for you to guess, by the hon. Prime Minister of this great nation. If that particular quote does not suit them either, let us see what Dr. Abhijit Banerjee, someone who made India and West Bengal proud by winning a Noble Prize in Economics, said:

"The Indian economy is doing very badly. There is an enormous fight going on in India about which data is right, and the Government has a particular view. All the data that is inconvenient to it is wrong."

This is what Dr. Abhijit Banerjee said. This is not me, Abhishek Banerjee. I share the surname. But this is Dr. Abhijit Banerjee.

Mr. Chairman, Sir, with this Budget we have witnessed the country's triple murder. Why did I say, 'triple murder'?

(1705/SAN/GG)

There has been a triple murder of the economy – demonetisation was the first murder, GST implementation was the second murder and Budget 2020 is

the latest. ...(*Interruptions*) Let me say a few words about the first of triple murder. After the demonetisation was announced on 8th November, 2016, our leader, the Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee was the only person who put out a tweet in the next one hour where she said: "WITHDRAW THIS DRACONIAN DECISION". Like most of the warnings BJP ignored, it brutally murdered the hope and aspirations of the people.

Now, I come to the second murder of the economy. What was that? It was GST. In 2012, the Finance Minister of Gujarat had said that 'GST is completely against fiscal federalism.' My party Trinamool supported the concept of GST, but we warned on the floor of the House not to rush with the implementation. We support GST, but at the same time, you have to understand that the country is not ready to implement GST at this point of time. Once again, you did not heed to our warning and look where you stand now. More than Rs. 70,000 crore stand due to the States from the Centre. The Centre owes a huge amount of money, in thousands of crores of rupees, to States like Delhi, West Bengal, Punjab, Rajasthan and Telangana.

Mr. Chairperson, Sir, now I talk about the third murder of this triple murder sequence which is the Budget 2020, as I just mentioned. I think, the third murder was more brutal, more barbaric. It was harsh and heinous. Let me tell you why I use these adjectives. It is because of privatisation and an array of schemes like Make in India. Hon. Prime Minister was mentioning them in his intervention when he was addressing the House this afternoon. After the BJP's all these failed flagship schemes like Make in India, Fit India, Khelo India, StandUp India campaigns, now this Government has come up with their most ambitious project. What is that project? The project is 'Becho India'. Considering their current strike rate, if you take the leaders in the market space or the market place, they will surpass Amazon, Flipkart and OLX in the days to come. ...(*Interruptions*) They have come with their flagship scheme which is 'Sell India'. I will just explain why I say this. One after another, they have sent the organisations for privatisation. Will the proposal to disinvest LIC need an amendment in the Parliament? If the answer to my question is 'yes', let me assure everyone, every citizen of this country, including the employees of LIC, the agents of LIC and the freelancers working with LIC that Trinamool will oppose this to the core, including

in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha and outside the Parliament as well. If required, we will take it to the streets also.

Sir, I wish to make an appeal to every Member of this august House, including the BJP Members who are present here. You talk about *desh bhakti*, you talk about patriotism, you talk about country's pride and you talk about 'देश के लिए खड़ा रहना'. If you have the spine, show your spine, stand up for your country and save LIC from privatisation. I challenge all of you that अगर ताकत है, दिल है, जोश है, दम है, तो इसको रोक कर दिखाओ। हम तो रोकेंगे। यह हमारी देशभक्ति है। हम फर्जी देशभक्ति में यकीन नहीं रखते हैं कि आर्मी कुछ काम करे और उसका क्रेडिट हम ले जाएं। जहां देशभक्ति दिखानी चाहिए, वहां दिखाइए। Where your patriotism should speak, use that platform. Why can you not stand up for your own right, as if you do not know what is best in your country's interest and what is right and what is wrong? One after another, the jewels of the country are being sold every now and then.

(1710/RBN/KN)

You start with Air India, then Indian Railways, then IDBI and now it is LIC. LIC's policies cover 70 per cent of those Indians who are insured. It has approximately 14 lakh agents and 90,000 full time employees. Sadly, LIC did not foresee and take out a policy to save its own life. Do you know why? It is because 37 per cent of India which voted for the BJP, which voted for this current Ruling Party, voted with aspirations, voted with faith, voted with hopes in their minds, with optimism in their hearts. LIC trusted you. LIC had faith in you. LIC supported you on your lows. LIC bailed the Government out in situations where the Central Government was in hand to mouth existence. Look what have you done? आपने उसी माँ को बेच दिया। आप नारे लगाते हैं- भारत माँ की जया अरे, भारत माँ है। हमारे लिए भारत माँ है। माँ है, तो उसकी हिफाजत करिए, माँ है, तो उसकी रक्षा करिए, माँ है, तो उसको तकलीफ से दूर रखिए। माँ है, तो उसका सम्मान करिए। माँ को सरेआम बाजार में ले आकर कोई नीलाम नहीं करता है। आपको यह जानना चाहिए और मैं यह क्यों बोलता हूँ? पहले बीएसएनएल, फिर रेलवेज़, फिर एयर इंडिया, आईडीबीआई और अब एलआईसी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सर, इनके कुछ मंत्री बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि पहले बीएसएनएल, फिर रेलवेज़, फिर एयर इंडिया, फिर एलआईसी और बहुत जल्द एफसीआई- फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। बीपीसीएल भी, आईडीबीआई बैंक, बहुत हैं, नाम गिनाने लग जाऊँ तो कल सुबह हो जाएगी, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। Why did I take the name of Food Corporation of India? This is because the Budget has slashed the food subsidy funds by Rs. 70,000 crore. Rs. 1.5 lakh crore is not enough to

provide subsidised ration to more than 80 crore households which comprises poor and the lower income groups across the country. Food Corporation of India which ensures that poor Indians do not go hungry under the PDS, will now have to borrow money to sustain itself. What can be a bigger shame?

The Government's unpaid bill to FCI is around Rs. 2 lakh crore. So, if this is taken into account, the fiscal deficit is actually close to five per cent. This comes at a time when the Consumer Food Price inflation is at a six-year high at 14 per cent. This will hurt the poor and the lower income groups the most. So, FCI is eventually the next target. This is going on record. आज मैं अपनी स्पीच में यहाँ बोल रहा हूँ आप कल देख लेना, ये क्या करते हैं? What after that? You all can guess it. Fertilizer subsidy has been slashed by Rs. 9,000 crore, which is down to 11 per cent.

As of May, 2019 the BJP Government has failed to pay farmers more than 40 per cent of Rs. 12,867 crore of the estimated claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

The Government takes pride for raising the insurance cover to Rs. 5 lakh. Is it enough? I want to ask the hon. Finance Minister. There are a lot of families in the country, there are a lot of parents, a lot of couples, a lot of individuals who save their life earnings just to ensure that their children get better education when they grow up. There are people who save money for various other purposes. A father may be saving money for his daughter's marriage. A boy or a girl might be saving money for his or her parent's future treatment. Then, you say that they will get only Rs. 5 lakh. नो मैटर, आपने दस लाख रुपये जमा किए, 12 लाख रुपये जमा किए, 15 लाख रुपये जमा किए। सर, देश में कितने लोग हैं? जिन्दगी भर मेहनत करके किसी ने 10 लाख रुपये जमा किए, किसी ने 12 लाख रुपये जमा किए, किसी ने 15 लाख रुपये जमा किए और आज क्या होता है? सरकार कह रही है कि अगर कुछ हो जाए तो आपको पाँच लाख ही मिलेगा। Why this hypocrisy? Why this duplicity? If you cannot provide security, safety, and surety to your own citizens, then you have no right to collect taxes from them. आप किस हक से उनसे टैक्स माँग रहे हैं, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते, आप उनको सेफ्टी नहीं देते, आप उनको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। Where will they go? It is either the devil or the deep blue sea. 'एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं'। सर, साधारण आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? Where will the commoner go? 'एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं'। घर में किसी ने पैसा रखा, तो असली चोरों का डर होता है और बैंक में पैसा रखा तो फर्जी चौकीदारों का डर होता है। सर, आम आदमी जाए कहाँ?

(1715/SM/CS)

And the murder continues; a systematic murder of federalism. We have had enough big talk. Now, it has turned from cooperative to operative! ...*(व्यवधान)* भाई साहब, शारदा के जो मेन लोग हैं, वे आपकी पार्टी में हैं। पहले उन्हें निकालो, फिर बात करना ठीक है और आप चिल्लाने की बात करते हो, अध्यक्ष जी से जरा अनुमति ले लो, 10 घंटे मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर चिल्लाऊँगा। किसके गले में कितना दम है, हम देख लेंगे...*(व्यवधान)* आप बात करना बंद करो। Sir, I will take extra time for the interruption in my speech. Just drop the 'C' from the cooperative federalism. So, from cooperative, make it operative.

Sir, regarding railway project, when Mamata Banerjee was the Railway Minister, she started new projects not only in Bengal, but in every corner, every part of India. She laid new railway lines; she started new freight corridors; she built new locomotive factories.

Sir, what has Bengal got in this Budget? It is just Rs.1,000 for every scheme. It is not rupees one lakh. सर, दो 500 रुपये के नोट बंगाल को दिए गए हैं। आप पहले बंगाल में जाओ, 18 सांसद चुनो, फिर बंगाल को आपने यह दिया है, दो 500 रुपये के नोट दिए हैं। This is what Bengal has got. सर, यह हम लोगों को नहीं चाहिए। This is what Bengal has got in this Budget when it comes to railway schemes. Shame!

Sir, when it comes to cooperative federalism, let me just give you one more example. Cyclone Bulbul destroyed 14.8 lakh hectares agricultural land and over 5.2 lakh thousands houses in Bengal were affected. Total estimated loss was about Rs.23,811 crore and it affected actually 35 lakh people. We have got no financial assistance in this account. The Government of India has not given a penny in this account.

Federalism for you means targeting the federal opponents and suppressing their voices. Your ED, IT and CBI are very dynamic when it comes to going after the political opponents from different States.

But let me ask them, where is Nirav Modi? Where is Lalit Modi? Where is Vijay Mallya? सर, जितने भी बैंक डिफॉल्टर्स हैं, हजार-हजार करोड़ रुपया देश से लूटकर चले गए और वे आज दूसरे देशों में जाकर ... *(Not recorded)* कर रहे हैं। जब गरीब आदमी लाइन में खड़ा होकर एक लाख रुपये का लोन माँगता है, तो उससे कहा जाता है कि ये कागजात लाओ, वो कागजात लाओ, हजार बहाने, सौ बहाने बनाए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि यह नहीं होगा। घर गिरवी रखो, मकान गिरवी रखो, जमीन गिरवी रखो। क्या यह इनका इंसोफ है? क्या यह सरकार का इंसोफ है? मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो देश से हजार-हजार करोड़ रुपया मारकर गए हैं, लूटकर गए

हैं, वे कहाँ हैं?... (व्यवधान) क्या वे वापस आए हैं?... (व्यवधान) वे कहाँ हैं, टिकट कहाँ है?... (व्यवधान) उन्हें वापस लेकर आइए, फिर बात करना... (व्यवधान) ... (व्यवधान)

When we talk on the subject of federalism, I can give you many examples ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Do you have a second speaker?

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I am the only speaker.

While we talk on the subject of federalism, I can give you many examples. But let me just give you a few examples where I can show that Bengal is doing better when it comes to how the country is performing under PM's leadership.

In 2018-19, Bengal's growth was 12.58 per cent. India's growth rate was almost half of that at that point of time. It was just 6.8 per cent. The Centre's fund for agriculture, health, education, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes' welfare have together seen a reduction of 8.9 per cent. But in Bengal, investment in agriculture is up nine times and investment in social sector is up by 4.5 times.

Sir, Bengal is number one when it comes to MGNREGA. It has the highest number of man-days and the highest number of fund allocation. In the Budget, MGNREGA funds have been cut by 13 per cent to Rs.61,500 crore for 2020-2021. It is evident what importance the Government gives to the rural economy.

It is distressing that instead of focussing on increasing rural wages and improving the functioning and payments of MGNREGA, the BJP-led Government is wasting resources on divisive policies like NPR and NRC.

Sir, let us move into girl child education. The BJP Government has spent Rs.644 crore on *Beti Bachao, Beti Padhao*. Out of Rs.644 crore, about 55 per cent have been spent on advertisement.

(1720/AK/RV)

Sir, I will give you an example as to what Bengal has done. I will tell you about the Kanyashree Scheme. In the last six-seven years, the Mamata Banerjee Government -- the '*Ma, Mati, Manush*' Government -- has spent Rs. 7,000 crore on one scheme in one State. She has received UN recognition for this, and eventually 60 lakh girls have been benefitted from it.

A five per cent cess has been announced in the Budget on imported medical devices. This will lead to increase in medical expenses and treatment

where the common people are involved, and they will eventually end up suffering. The common people will continue to suffer after this step. But, in Bengal, the entire cost of treatment is borne by the State. There is paperless, cashless, free treatment, and up to 70 per cent discount on medicines. Further, more than 7.5 crore people are covered under the Swasthya Sathi Scheme.

Sir, please allow me to share a few more achievements of the State. Bengal is number one in ease of doing business. The credit lending to MSME sector is at Rs. 56,458 crore, which is the highest in Bengal. Bengal is number one when it comes to skill development. The average annual income of farmers has increased by more than three-times -- and it has been done already -- from 91,000 in 2011 to 2,91,000 in 2019. Nearly, 69 lakh farmers were given Kisan Credit Cards in 2018. Under the 'Sabooj Sathi' Scheme, more than one crore cycles were distributed to school-going children. Since last eight years, more than 1.98 pre-matric and post-matric scholarships were awarded to SC / ST and OBC students. Almost 100 per cent households have access to uninterrupted power in the State. There has also been a 37 per cent increase in power generation.

Now, let me talk about 'Make in India'. The Prime Minister says sell anywhere, but 'Make in India'. He says this everywhere. But what is the reality? He himself does not live by this slogan. सर, चीन से वर्कर्स आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाते हैं। आप दीवाली में शंघाई और बीजिंग से लाइट्स मंगाते हैं। बैग के जिप से पेन की निब तक सब मेड-इन-चाइना है। Then, you say 'Made in India'! This is why this is not helping in creation of jobs and our youth continues to suffer. In a year when joblessness is at a 45-year high, this Budget is offering fresh Graduates internships. The youth of this country does not want to live at their mercy. The youth wants jobs and not internships. हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार को लेकर इस बजट में कोई चर्चा ही नहीं की गई है।

If you do a word search, सर, यह जो पूरी बजट स्पीच है, इसमें टोटल 13,200 वर्ड्स हैं। मैंने एक-एक को पढ़ा है। इन 13,200 वर्ड्स में 'अन-एम्प्लॉयमेंट' वर्ड एक बार भी नहीं आया है। कोई सोचेगा कि यह पाँच बार आया होगा, कोई सोचेगा कि दस बार आया होगा, कोई सोचेगा कि दो बार आया है, चार बार आया है। यह 'जीरो' है। 'Unemployment' has been mentioned 'zero' times in these 13,200 words long 162-minute Budget speech. This is the Central Government for you! They are not addressing the falling GDP; they are not addressing the grave concerns of unemployment; they are not addressing the

concerns that are affecting the common people including the price rise; and then you talk about the \$5 Trillion economy. जी.डी.पी. तो 5 प्रतिशत के नीचे है और आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी, तब तक वर्ष 2040 हो जाएगा।

Auto companies like Maruti Suzuki, Hyundai, Honda, Tata and Mahindra & Mahindra have partially stopped production, and even reported plant shutdowns. The total industry output is reduced by 20-25 per cent. More than 2,30,000 workers in the auto sector are now jobless.

For all the big talk on national security, the Government is so desperate when it comes to taking credit for the work our Army, Air Force and Navy are doing. The Defence Budget has been raised by just five per cent reducing military's buying power. This does not even cover inflation. This will eventually stall all the procurement of important military equipment, air defence systems, and artillery. ...(*Interruptions*)

Sir, I will take two minutes more to speak.

(1725/SPR/CP)

This will stall the procurement of important military equipment. Is it because elections are not knocking at the door now? Elections are over. That is why, defence does not get a priority. उपयोग हो, अब छोड़ दो, अब डिफेंस की जरूरत नहीं है। सर, जहां पर देना चाहिए, वहां पैसे नहीं देते हैं। Again I think defence will get priority in 2024. जब लोक सभा चुनाव आएं, तो फिर करेंगे। इनकी सिर्फ एक नीति है, उपयोग करो और भूल जाओ। यहां पर शिवसेना के सांसद बैठे हुए हैं, एनसीपी के सांसद बैठे हुए हैं। If media reports are to be believed, bullet train project has been stalled. बुलेट ट्रेन के 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये आप आर्मी को क्यों नहीं देते हैं कि वह बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे? हम चाहते हैं दो, देश चाहता है दो। Why do you not give that Rs.1.10 lakh crore to the Army to buy bullet proof jackets? The country does not need bullet train. Our Army needs bullet proof jackets. Why do you not spend that money to build freight corridors to carry food for the poor and marginalised? वहां पर पैसे खर्च करिए। Why do you not spend that money by giving homes to the homeless? Why do you not spend that money for uplifting the marginalised? Why do you not spend that money to give food to the hungry? It can feed scores of people.

I want to spend just one minute on austerity. The time has come for austerity measures. I speak on behalf of my Party, whose Chairperson does not preach austerity, she practices it. Instead of selling country's jewels like Air India,

BSNL, LIC, IDBI, BPCL, Indian Railways, why does the Government not consider doing anything about the Raj Bhavans? आप राजभवन के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप रेलवेज बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, what are your thoughts and plans on Raj Bhavan? Sir, Raj Bhavans across India are only being used as BJP's extended offices and post-retirement mansions of BJP leaders. Nothing else. Almost all or maximum Members in this House would agree with me on this. Let us have a vote of the Members present. Will you be able to do it? ...*(Interruptions)* Do you have the guts? I want a division on this right now. ...*(Interruptions)* Do I go for the division? Sir, preach what you practice. सब की परीक्षा मत लीजिए। किसी दिन हम परीक्षा ले जाएंगे, फेल कर जाएंगे, सब एक नहीं होते। ...*(व्यवधान)* All the money spent on the maintenance of properties and the ceremonial lifestyle of handful. ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Shri Abhishek, you have put forth your points across very succinctly, I think. Please conclude within one minute.

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Yes, Sir. Various newspapers have reported that the Government of India is buying an aircraft for a whopping \$ 200 million for the travel of VVIPs and VIPs. Sir, I wonder is this the reason why Air India is being privatised just for better maintenance of these fleets! The Central Government has spent Rs.6,000 crore on advertisement. सर, आप इसी पैसे को मनरेगा में क्यों नहीं देते हैं, इसी पैसे को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्टेट्स की सहायता क्यों नहीं करते हो, इन्हीं पैसे से जीएसटी के ड्यूज क्लियर क्यों नहीं करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ Why is Rs,70,000 crore still owed to all the States of India? It is very unfortunate. We are heading to a position where the country was – I mentioned in my last speech – in the operation theatre, now it will be heading to a ventilator position where it will not be able to resurrect and revive. These are serious issues. All that this Government is doing is, cracking jokes and making mockery of the economy.

A Minister says, slowdown in automobile sector is because the mindset of millennials, who pay for Ola and Uber. Sir, imagine. While another Minister says, India has a sound economy because three Bollywood movies have done Rs.100 crore of business in a day. This is the mindset. How can you imagine the country with people like them? After listening anxiously to each and every word of what the Finance Minister has said, I am left and stuck with one thought.

(1730/UB/NK)

Is it the speech of Government of India or is it the speech of Government of India Private Limited? Sir, I will take twenty seconds. Sir, their slogan is '*Sabka Sath, Sabka Vikas*'. मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अपने दल के सभी सांसद को लेकर अपने लीडर्स के पास जाएं और उन्हें बोलें कि इस बजट के बाद आपका स्लोगन 'सबका साथ सबका विकास' नहीं रहा, देश कह रहा है देश की भूल कमल का फूल। So, I end my speech on this note.

(ends)

1730 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): I just listened to the volcanic speech of the hon. Member sitting next to me but my speech is going to be in contradiction with what he spoke. I think it is a good Budget covering the short, medium, and the long-term objectives of the Government for an aspirational India, for a caring India and for a modern India.

I want to start with the subjects which are good and, at the same time, where they need a little improvement. I wanted to give my suggestions also. I start with agriculture. Though agriculture is a State subject, the Government of India has taken a very caring view wherein not only a mere expression of caring is there, but the hon. Finance Minister also gave sixteen measures which she had explained one by one as to how the goal of doubling the farmers' income can be achieved. In addition to that, Rs. 15,695 crore were given to the farmers' insurance scheme, Fasal Bima Yojana. Our beloved Chief Minister, along with the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme under which the Government of India has given Rs. 65,000 crore for the country, has given a little over 20 per cent of the matching grant under PM Kisan Samman Nidhi Yojana, and almost 44 lakh farmers have been benefited in our State. So, we are supplementing the Government of India Scheme with our Rythu Bharosa Scheme which has been named after our beloved former Chief Minister who is the metaphor of our party.

There are various good schemes. Under PMKUSUM, the farmers will be given the benefit of solar power and another 15 lakh farmers are getting grid-connected pump sets. This is a very good initiative. The major initiative taken by this Government is what Sitharaman ji has announced, where there is no water availability, where there is a barren land, the scheme enables them to set up their own solar plants with the support of the Government funding and also to tie up with the electricity boards concerned. With this wonderful initiative, the job seekers in the rural areas would become job givers. So, this is also a very good initiative for the rural areas.

With regard to the Krishi Udan and Kisan Rail schemes, no doubt, these two schemes are very good for agriculture but this would predominantly benefit the traders who are involved in this sector. How can the benefits be transferred to the farmers? I would request the hon. Finance Minister to ensure that the benefits of Krishi Udan and Kisan Rail percolate down to them. There is also a

provision of Viability Gap Funding to set up warehouses at the block level where the self-help groups would be involved. It is indeed a wonderful scheme and the women folk in the rural areas would have immense benefit. Under this Scheme, they would also be a part of the system where they will all become sufficiently rich in the short term.

(1735/KMR/SK)

Mr. Chairman, I have a few concerns. The hon. Finance Minister announced Rs.15 lakh crore credit being made available for the farming community. As per the statistics, even today only 30 per cent of the farmers are able to access credit from banks while the rest 70 per cent are depending on moneylenders who charge high rates of interest on daily basis and in some cases even on hourly basis. To put an end to this, the Government has to come up with various measures.

There is a minimum threshold of 18 per cent loans to be given to the farmers by banks. NABARD is doing a good job. But, how much credit is really being given by banks without misrepresenting the heads of account? They give loans under some head and then try and put it under the head of agriculture. I urge the hon. Finance Minister to go through this in detail. If she can ensure that the threshold of 18 per cent loans being extended to the farmers is met, there is nothing like it. In addition to 'Rythu Bharosa', the Government of Andhra Pradesh is supplying free power for agricultural pump sets.

Another important point the hon. Finance Minister mentioned is the support given to aquaculture. Though I am one among 543 Members here, it is as though this point addresses my Constituency directly. Hon. Finance Minister has set the target of increasing exports to Rs.1 lakh crore. Today the exports are around Rs.50,000 crore. Today, we in the two Godavari Districts are able to export around 65 to 67 per cent of the produce. Madam Finance Minister, we will be able to easily achieve this target of Rs.1 lakh crore.

The State Government of Andhra Pradesh is supplying power at Rs.1.50 per unit despite the problems the State is facing owing to shortage of money. Still, to protect the interest of farmers, we are supplying power at a subsidised rate of Rs.1.50 per unit. We are happy that Rs.540 crore has been announced. But since we account for a major chunk of the exports target, since we are giving you the guarantee of meeting the Rs.1 lakh crore exports target, I would request

you to utilise the major chunk of funds for setting up the Aquaculture University there and for setting up more laboratories.

Mr. Chairman, the people involved in the activity of agriculture and aquaculture are saying that while the Department of Agriculture is promoting production, for sale of produce in international markets they are asked to go through APEDA which is controlled by the Ministry of Commerce. The Ministry of Commerce deals with several products of various categories. Therefore, it is felt that the Commerce Ministry would not be able to spend the time that the Ministry of Agriculture can spend on this activity. I am not saying anything against the Commerce Ministry but the affection with which the Ministry of Agriculture can take care of the export of agricultural produce would be much more. If you look at the rice exports, there has been an increase all through the last five years. However, there is a projected decrease of 20 per cent in the export of rice, which constitutes two per cent of the overall exports from the country. That 20 per cent fall is quite high. I spoke to many people in the trade and they are all of the firm opinion that if APEDA is left to the Ministry of Agriculture, there would be better synchronisation. Similarly, if MPEDA is left to the Fisheries Ministry, there would be better synergy and we would be able to easily achieve the export target set by the hon. Finance Minister. I, therefore, urge upon the Government to kindly consider these two points on top priority.
(1740/SNT/MK)

The next point I would like to highlight is health. As far as health is concerned, the best policy till date in the country was announced by the mentor of our party Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy by the name 'Rajiv Aarogyasri'. Earlier there were only 1,000 diseases covered under this scheme. Today, we are covering 2,016 diseases under this scheme. Rs.5 lakh is the income limit but there is no upper limit. Just now, my colleague Mr. Abhishek Banerjee was talking of ceiling. We do not have that kind of ceiling in our State. 150 super-speciality hospitals are covered under this scheme.

I would like to tell the Government and the Pradhan Mantri that Ayushman Bharat is indeed a wonderful scheme but the criteria that one should not have a motorcycle, one should not have a phone, etc., all these things, should not be there. Today, even the poorest of the poor is having a vehicle to travel and he is having a cell phone or a landline phone. So, this kind of criteria has to be

changed. Otherwise, the target of delivery of 11 crore Ayushman cards would not be achieved. If you will strictly go by these criteria, even 2-3 crore cards would not be delivered. In our State, under Rajiv Aarogyasri, we are covering almost 70-75 per cent of our State's population. I would like to tell the hon. Prime Minister that this is a very important and wonderful scheme. Kindly look at our State also and implement this.

Now, I am coming to my State's problems. The main thing is the special category status we have been requesting. We once again urge whether we use the title of special category status or not, we have to get Rs.18,000 crore for the shortage of Polavaram project. Out of Rs.11,000 crore, which we have spent, we have got only Rs.8,000 crore. There is Rs.3,500 crore still to be given. For rehabilitation, another Rs.40,000 crore is required. Since it is a national project, sufficient allocation of funds is required. Our Chief Minister has targeted to complete it by 2021, which is an ambitious target, for which we need the hon. Prime Minister's support.

We have a few more concerns wherein we are seeking the support of the Government of India. There has been a one per cent reduction, that is, Rs.1,800 crore in GST rates. As we all know, ours is a new State where at a nascent stage, we need the helping hand of the hon. Prime Minister for our State. For our State, it has to be compensated.

We very much appreciate the concern of the hon. Prime Minister for futuristic India. We are all with the hon. Prime Minister. We request the hon. Prime Minister to give a helping hand to our beloved Chief Minister and bring Andhra Pradesh our past pride.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): You have raised your points very well.

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Thank you, Sir.

(ends)

1744 बजे

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब यहां अपना बजट रखा तो उन्होंने पहले दो घंटे तीस मिनट तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया। मैं आपको आदरपूर्वक सल्यूट करता हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक प्यास को सहन किया।

(1745/YSH/GM)

आपको प्यास लगी या नहीं लगी यह हमें मालूम नहीं, लेकिन लोग प्यासे थे। लोग बहुत प्यासे थे और वे चाह रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आज सुबह प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई सुझाव देता है या आलोचना करता है तो उसकी आलोचना को न देखकर उसे स्वीकार करना चाहिए। आपने ही कहा था कि "I appear to be conservative, but I want to be realistic." So, today I also would like to go for a realistic view of the Budget. मुझे उसमें पहला वाक्य बहुत अच्छा लगा The Budget is to boost the income and enhance the purchasing power. This is the ground; this is the foundation of the entire Budget. जब मैं आगे चलकर देखता हूँ तो आप पानी भी नहीं पी रही थीं। दो घंटे के बाद जैसे ही आपका भाषण समाप्त हुआ तो सबसे बुरा स्वागत अगर किसी का हुआ तो वह सेंसेक्स का हुआ। शेयर मार्केट इस तरह से नीचे गिरा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिर गए। मैंने लोगों से पूछा कि आपको बजट से क्या लगा, तो लोग असमंजस में थे। कोई अच्छा बोल रहा था तो कोई बुरा बोल रहा था। उसी समय मुझे एक व्यक्ति, जो बीजेपी को बहुत प्यार करता है, वह मिला और मुझे बोला कि अरविंद जी आपको पता है।

“जाने वे कैसे लोग थे, जिनके प्यार को प्यार मिला,
हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला।”

मैंने उससे पूछा कि इस बजट में तकलीफ क्या है? उसने मुझे बताया कि हमारी सरकार यह मानने को ही तैयार नहीं है कि मंदी है। अगर वे मान लेंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा। आप जब यह मानेंगे कि मंदी है या स्लोडाउन है तब आप इलाज परफेक्ट करेंगे। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं। इसलिए हम इलाज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने जो मार्ग अपनाया है, वह हमें गति नहीं दे रहा है। उस गति को पाने की आवश्यकता है। हमें वह गति क्यों नहीं मिल रही है। What are the hurdles? Why are people not accepting it? आपके भाषण में The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially which will benefit the consumer. ये आपके बूस्ट ऑफ इनकम से रिलेटेड वाक्य है। इससे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने से मार्केट में पर्चेजिंग पावर भी बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब मंत्री था तो आपके पास भी गया था।

आज इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी। मैं आगे भी बोलूंगा, लेकिन अभी याद है तो मैं उदाहरण देता हूँ। मैं मैटल इंडस्ट्री की बात कर रहा था। मुम्बई शहर में कॉपर इंडस्ट्री है। हो सकता है कि यह

दो राष्ट्रों की ट्रीटी होगी। विदेशी प्रोडक्ट जो बाहर से आता है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है और रॉ मेटिरियल पर कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी लगने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ने से माल या तो कोई लेता नहीं है या फिर महंगा हो जाता है। इससे इनकम तो बूस्ट होती नहीं है, बल्कि हमारा जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, वह वहीं पर ही डिफीट हो जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो उद्दिष्ट हैं Make in India, boost the income, and enhance the purchasing power, it gets defeated there itself. हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं, आपने बहुत सारी नीतियां उसी तरह अपनाई हैं। You wanted to protect them; I know it. शायद आपकी नजर से हट गई होगी। मैं मैटल इंडस्ट्री के लिए आपसे मांग कर रहा हूँ। अगर आप इसको करेंगी तो उनका रोजगार रहेगा। Many companies in metal industry are closing down. अगर वे क्लॉज डाउन करते हैं तो जो हम इम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की बात करते हैं, वह भी डिफीट हो रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आपको ध्यान देकर इसका निराकरण करना होगा, उसके बाद ही हमें बढ़ोतरी मिलेगी, उससे कंपनी भी खड़ी रहेगी और रोजगार भी मिलेगा।

(1750/RPS/RK)

अभी जीएसटी पर इन्होंने भी बहुत बोला है। आप जानते हैं कि जीएसटी के बारे में महाराष्ट्र सरकार की जो राशि केन्द्र सरकार से आनी थी, वह नहीं आई। कब आई? जब नए मुख्य मंत्री आए, आदरणीय उद्धव साहब ने आपको पत्र लिखा तो पिछले अक्टूबर-नवम्बर के 15,500 करोड़ रुपये में से कुछ 4,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इतनी कम राशि में वहां भी सरकार चलानी है, क्योंकि जो वहां का बजट था, जिसका स्रोत सेल्स टैक्स था, वह बन्द हो गया। ऑक्टोई बन्द हो गया, महानगरपालिका पर भी बर्डन आ रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जीएसटी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जीएसटी की क्लिष्टता आज भी परेशान कर रही है, उस क्लिष्टता को थोड़ा आसान करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को सुविधा हो। आपने कुछ काम किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका स्वागत है। हम अच्छे को अच्छा कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे और जो सुधारना है, उसे सुधारने के लिए कहेंगे। आपने स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और सोलर पावर की बात की है, लेकिन जो पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर वलनरेबल सेक्शन्स, क्रेडिट सपोर्ट, डिजिटल पेनेट्रेशन विद ब्रॉडबैंड, एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, इन सारी चीजों को भी देखिए।

आप देखिए, जो पेंशन स्कीम है, अगर आप 1995 की पेंशन स्कीम को देखें, आज उसके लाभार्थी करीब 65 लाख लोग हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, वहां जो बिहाइण्ड द स्क्रीन हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि क्या 2500 रुपये में अपना परिवार चलेगा? क्या 3500 रुपये में आपका परिवार चल जाएगा? उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है? आज तकरीबन करोड़ों लोग 1995 की पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। उनकी ओर से जो राशि आपके पास आती है, अगर आप उसका ब्याज भी देखें, इस पेंशन स्कीम के तहत जो राशि सरकार के पास जमा है, अगर उसका इनवेस्टमेंट

किया जाए तो उसके ब्याज से आप इन पेंशनधारकों को 5,000 रुपये से 7,000 रुपये पेंशन दे पाएंगी। इससे आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। इतने सारे बुजुर्ग लोग इसमें हैं। आज लोगों की लांजेविटी बढ़ी है, बच्चों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि वे खुद के पैरों पर खड़े रहें। हालांकि बाकी योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना आदि का लाभ उनको मिल सकता है, वहां सरकार कुछ कर रही है। लेकिन यदि उनके हाथ में पेंशन आती है तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

अब आपने डिजिटल पेनेट्रेशन की बात की है। आप सभी को पता है कि भारत संचार निगम इस देश के कोने-कोने में पहुंचा है। महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई महानगर के कोने-कोने तक पहुंचा है। आप किसको यह काम दे रहे हैं? हर जगह प्राइवेट कंपनी क्यों? आप आज इन कंपनियों के रिवाइवल के लिए वीआरएस लेकर आई हैं। आपको पता है कि वीआरएस लाने के बाद करीबन एक लाख कर्मचारियों ने दोनों कंपनियों से वीआरएस ले लिया है। एक तारीख को ऑफिस में कर्मचारी नहीं थे। अब ग्राहक वहां गया, उसे नई लाइन लेनी है या कुछ बिल पे करना है, वहां बीएसएनएल के ऑफिस में कोई नहीं है। लगभग 80,000 लोग चले गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? न हमारी मैनेजमेंट प्रिप्रेयर्ड थी, न सरकार प्रिप्रेयर्ड थी। चाहते थे कि लोग जाएं, लेकिन जाने के बाद कंपनी को कैसे चलाएंगे? एक तरफ हम कहते हैं कि हम रिवाइव करने वाले हैं, आप रिवाइवल करने वाले हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी कि एक तारीख से यहां इतने कर्मचारी होंगे, जो आगे चलकर कंपनी को चलाएंगे। ऐसी तैयारी मुझे नहीं दिखी। इसलिए आप जो डिजिटल पेनेट्रेशन करना चाहते हैं, खासकर ऑप्टिकल फाइबर या एफटीटीएच की, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह काम इनको दीजिए, इससे उनके रिवाइवल प्लान को ऑटोमैटिक सपोर्ट मिलेगा। जो कर्मचारी बचे हुए हैं, कुछ और टेम्पररी बेसिस पर लेकर करेंगे और वह काम अच्छी तरह से हो जाएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आलरेडी तैयार है, उनको पता है कि कहां देना है, किस तरह से देना है। आप जो प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वह सक्सेसफुल होगा, गांव की ग्राम पंचायत में भी आपको एफटीटीएच देना है तो वहां आलरेडी केबल है, उनको पता है कि कैसे देना है और यह काम अच्छी तरह से हो जाएगा। एमटीएनएल के पास मुंबई में अच्छे डेटा सेंटर्स हैं, अगर आप उनके डेटा सेंटर्स भी ले लेंगी तो अच्छा होगा।

(1755/IND/PS)

माननीय सभापति जी, अगला महत्वपूर्ण विषय प्रधान मंत्री आवास योजना है। मैं समझ सकता हूं कि डेढ़ लाख रुपये में घर नहीं बन सकता है। पिछली बार शहर के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार शहरों के लिए दस हजार करोड़ रुपये रखे हैं और दस हजार करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखे हैं। डेढ़ लाख रुपये में यदि एक घर बनता है, तो दस हजार करोड़ रुपयों में कुल छह या साढ़े छह लाख घर ही बन सकते हैं। डेढ़ लाख के अलावा जो पैसा लगेगा, वह कॉमन मैन को कैसे मिलेगा? यह बात आम आदमी की समझ में नहीं आ रही है। पहले मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चैन्नई मेट्रोपोलिटन सिटीज थीं। इनमें चैन्नई और दिल्ली में तीन या इससे ज्यादा मंजिल के मकान कम थे, लेकिन मुंबई और कोलकाता में ज्यादा मंजिलों के मकान थे। अब मुंबई में सौ साल पुरानी इमारतें हैं और वे गिर रही हैं। हम पक्के मकान का वायदा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स गिर

रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को कुछ तो करना होगा। हमारी मुम्बई में केंद्र सरकार की जमीन पर चाहे रेलवे की जमीन हो, डिफेंस की जमीन हो, एयरपोर्ट की जमीन हो या दूसरी सरकारी विभागों की जमीन हो, इनकी जमीनों पर झुग्गी-झोपड़ियां हैं और कुछ इनकी बिल्डिंग्स भी हैं। मैं एलआईसी का विषय आपके पास लाया था। डिफॉल्ट के कारण वह बिल्डिंग आपके पास आई है। वह बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है। वह भी सौ साल पुरानी है। आप उन्हें डेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं और न स्वयं कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का पक्का मकान देने का सपना है। यदि कल एलआईसी की बिल्डिंग ढह गई, तो आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि एलआईसी की बिल्डिंग मुम्बई शहर में बादामबाड़ी गिरगांव एरिया में है, उन्हें रीडेवलपमेंट करने की अनुमति दी जाए। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट तो वहां के लोगों के साथ छल कर रही है। रेलवे की जमीन पर जो झुग्गी-झोपड़ियां थीं, उन्हें तोड़ दिया गया है। आप लोग 20-25 साल पुरानी झुगियां कैसे तोड़ सकते हैं? एक तरफ हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी कहते हैं कि किसी का मकान तोड़ना नहीं है और पक्का मकान देना है, लेकिन दूसरी तरफ रेल विभाग वाले 20-25 साल पुरानी झुगियों को तोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप प्रधान मंत्री जी के सपनों को साकार कर रहे हैं या उन्हें धवस्त कर रहे हैं, यह भी आपको सोचना पड़ेगा।

महोदय, प्रधान मंत्री जी की फसल बीमा योजना है, प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना है। मैं दोनों योजनाओं का स्वागत करता हूँ। फसल बीमा योजना का पैसा आज भी किसानों को नहीं मिला है। आप जानते हैं कि हम एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के दस जिलों में एक भी बीमा कम्पनी किसानों को फसल बीमा योजना देने के लिए तैयार नहीं है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Shri Arvind Ji, we are nearing 6 o'clock. Hardly one minute is left.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I am concluding. जो सरकारी कम्पनी थी, उसका आप डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, वे वहां बीमा करने नहीं आ रही हैं, क्योंकि प्राइवेट कम्पनियों का कर्म मुनाफा कमाना है और सेवा देना सरकारी कम्पनियों का धर्म है।

1759 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष जी, मंत्री जी क्या चाहती हैं? क्या वे मुनाफा कमाने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं या सेवा करने वाली कम्पनी, धर्म का काम करने वाली कम्पनी एलआईसी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, यह आप तय कीजिए। लोगों को सेवा नहीं मिल रही है। एक भी जिले में फसल बीमा योजना देने के लिए कोई कम्पनी नहीं आ रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि निजीकरण, उदारीकरण का कृपया अंधा अनुकरण न करें। हम पश्चिमी राष्ट्रों का अनुसरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां आबादी नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आबादी है। आप चाइना की बात करेंगे, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है। वहां यदि यह कानून बनाना पड़े कि सिर्फ एक बच्चा ही होना चाहिए, तो एक बच्चा ही होगा। ऐसा यहां नहीं हो सकता है। जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्या हम उन्हें

नौकरियां दे सकेंगे? यहां बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी, आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। उदारीकरण के चक्कर में हम यह तो न भूलें कि हम उनके रोजगार छीन रहे हैं।

(1800/ASA/RC)

आप देखिए कि पिछले कितने सालों से बेरोजगारी बढ़ी है? कितनी कंपनियां बंद पड़ी हैं? कितना नया रोजगार निर्माण हुआ है? कितनी नई कंपनियां आईं? अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में हम रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं।

आपको पता है कि एयर इंडिया में 20-20 सालों से लोग उसी एक तनखाह पर काम कर रहे हैं। हम भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो देखते हैं, कितना बुरा लगता है। कहने के लिए सरकार कह सकती है कि इतने लोगों को रोजगार दिया। लोगों की तनखाह छठे पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन से बढ़ती है लेकिन इन बेचारों को क्या है? 10-10 हजार, 5-5 हजार पर पिछले दस सालों से एक ही तनखाह पर, कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम इस बारे में कभी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी के भाषण पूरा होने तक सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाता है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, दो-तीन मिनट में खत्म कर देता हूं। हमारी पार्टी से एक ही आदमी बोलेंगे।

आज सारे जो रिसैशंस हैं, निर्मला जी, जो अच्छा काम किया है, वह बताने के लिए वक्त नहीं है, नहीं तो मैं वह भी बोलता। किसानों की एश्योर्ड इंकम नहीं है। हमारी एश्योर्ड इंकम है। हमें तनखाह मिलती है। बारिश आने दो, बाढ़ आने दो, तनखाह मिल रही है। लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है? भावंतर योजना लाने की आवश्यकता है। आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी है और अगर भाव डाउन हुआ, जैसे कल ओनियन की बात हुई थी। The same thing is happening now. It is at Rs.2 per kilogram now. It was Rs.50 per kilogram and Rs.200 per kilogram also but it has now come down to Rs.2 today. Who will compensate them? The MSP should be decided for that. उसमें जो लॉस होगा, वह अगर भावंतर योजना आई तो किसान उस पर खड़ा रह सकता है।

अंत में, मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एक मुद्दा रिक्रूटमेंट के बारे में बताया। मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारे यहां स्टॉफ सलेक्शन कमीशन है या स्टेट के कमीशंस हैं। पूरे देश में रिक्रूटमेंट होती है। हाल ही में कुछ मंत्रियों ने अच्छी बात की। अपने-अपने राज्य की बात की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये रिक्रूटमेंट आप रीजनल करिए।

टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात छोड़िए। इसमें भी लोगों की भावनाएं बहुत भड़क रही हैं। Sons of the soil should be given preference. The sons of the soil can be given preference if it is regional recruitment. If you do not do it, it will always be an injustice to them. और उसका रिएक्शन आता रहेगा।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): आप टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ में हैं कि विरोध में हैं?

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): नहीं, नहीं, विरोध में हैं। देश के टुकड़े करने दें, क्या बात करते हो? ...(व्यवधान)

यह जो रिक्रूटमेंट है, अगर वह रीजनल लैवल पर होगा तो वहां के राज्य के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तमिलनाडु में आजकल जो मेडिकल एडमिशन के ऊपर विरोध हो रहा है, उसका रीजन वही है। Their own people do not get admissions over there. That is why, I am saying that the recruitment should be done at the local level. Regional Recruitment Centres should be opened so that justice can be done to the sons of the soil.

आप रेल का निजीकरण करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है, आप क्या-क्या निजीकरण करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा कि अंधानुकरण न करें। तेजस आई, अच्छी आई। मगर एक सवाल मेरे मन में आया। दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से कल को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर तेजस के जो प्रवासी हैं, उनको कौन इंश्योरेंस का पैसा देगा या उनको कौन रिलीफ देगा? रेल में यहां आ गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, इस बात पर ये बोल नहीं सकते हैं। ये उस विभाग के मंत्री रहे हैं, इसलिए ये इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करके ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। अभी इन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया है, इसलिए ये बोल नहीं सकते हैं। ये उस विभाग के मंत्री रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): यह मजाक की बात छोड़िए। सच्चाई की बात करिए। जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया। यही गलती हो रही है। हमने क्या किया, लोगों को लगा कि यदि एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा? जो गाड़ी है तो उसका मालिक दे देगा। अभी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चल रहा है। मोटर साइकिल वाला, रिक्शा वाला या टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो गया, अगर मरा हुआ आदमी बहुत बड़ा रईस था तो कहां से पैसा देगा? वह मरेगा। वह तो जेल में ही जाएगा और उधर इंश्योरेंस कंपनी सेफ है। प्राइवेट इंश्योरेंस वालों का जो धंधा है, वह आपको देखना पड़ेगा।

(1805/RAJ/SRG)

मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं और आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने एजुकेशन पॉलिसी में जो कदम उठाए हैं, उसकी सराहना करता हूं, लेकिन खास कर प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वहां कम से कम दो-तीन सब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो standard of education throughout the country will remain the same, otherwise people would be deprived of the quality education and the discrimination will go on.

आपने जो बजट रखा है, आप शुरू में बुके लाए, बुके में फूल थे, आपने तीन फूल रखे थे, लेकिन महक नहीं आ रही है। न रही बांस, न बजेगी बांसुरी, ऐसा हो रहा है, उससे बाहर आएं, तो मुझे आपका अभिनंदन करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1806 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, दिनांक 07 फरवरी, 2020 / 18 माघ, 1941 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।